चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

www.chauthiduniya.com

फोरेंसिक साइंस लेबोरेट्री का फर्जीवाड़ा

पेज-3

इस चेतावनी को सिर्फ़ रैली न समझें

पेज-4

ममता युवाओं में आस जगाएंगी

पेज-5

सनातन धर्म के साथ खिलवाड़

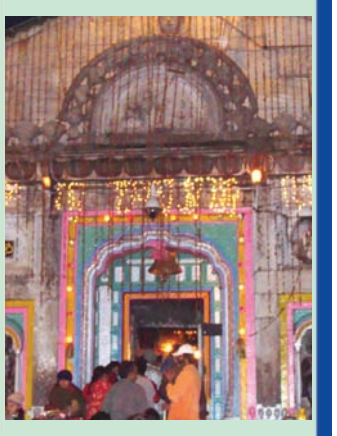

पेज-6

1986 से प्रकाशित | दिल्ली, 21 मार्च-27 मार्च 2011 | मूल्य 5 रुपये

लगता है बाबा रामदेव से कांग्रेस डर गई

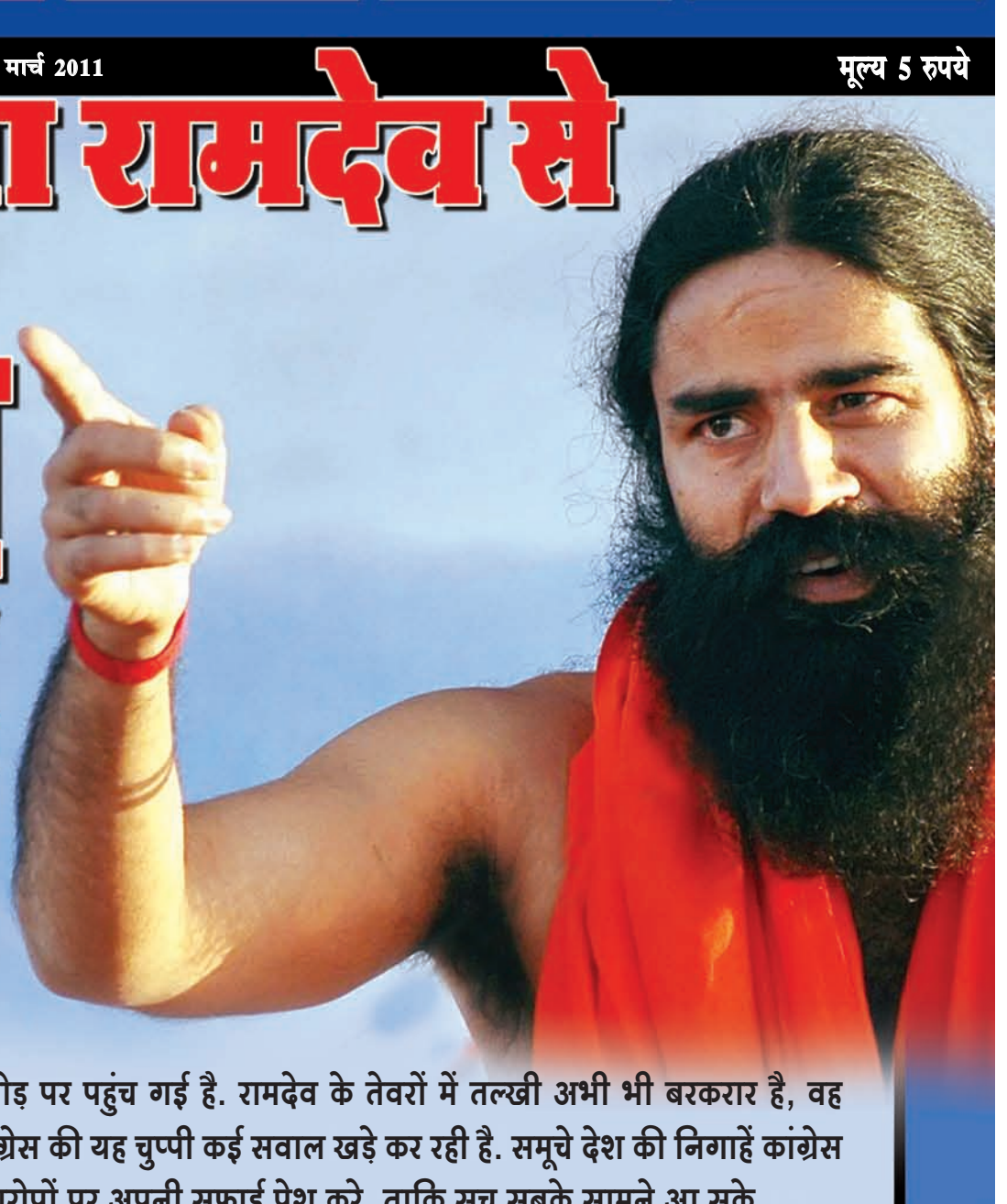

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

बाबा रामदेव और कांग्रेस पार्टी के बीच चल रही लड़ाई एक दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है. रामदेव के तेवरों में तल्खी अभी भी बरकरार है, वह रह-रहकर दहाड़ उठते हैं, लेकिन कांग्रेस ने अचानक चुप्पी साध ली है. कांग्रेस की यह चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है. समूचे देश की निगाहें कांग्रेस की ओर हैं कि वह बाबा एवं उनके सहयोगियों द्वारा लगाए गए आरोपों पर अपनी सफाई पेश करे, ताकि सच सबके सामने आ सके.

मनीष कुमार

- **रामदेव की बात पर सोनिया को किसने डराया, क्यों डर गई कांग्रेस?**
- **रामदेव के जवाब पर दिग्विजय सिंह क्यों चुप हुए?**
- **क्या दिग्विजय सिंह ने जानबूझ कर रामदेव के ख़िलाफ़ बयान दिया?**
- **शुरुआत में कांग्रेस ने बाबा रामदेव की मदद क्यों की?**

राजनीति और आध्यात्म में सबसे बड़ा फ़र्क़ यह है कि आध्यात्म मनुष्य को मौन कर देता है, जबकि राजनीति में मौन रखना सबसे बड़ा पाप साबित होता है. बाबा रामदेव के हमले के बाद कांग्रेस पार्टी आध्यात्म की ओर मुड़ गई है, उसने चुप्पी साध ली है. यह चुप्पी किसी योजना या रणनीति का हिस्सा नहीं है, बल्कि डर का परिणाम है. बाबा रामदेव और उनके सहयोगियों ने काले धन की आड़ में कांग्रेस और गांधी परिवार पर हमले किए. उनका आरोप है कि राहुल गांधी को रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी से पैसे मिलते हैं. राजीव गांधी ने स्विस बैंक में काला धन जमा किया. कांग्रेस सरकार ने क्वात्रोकी के बेटे को अंडमान निकोबार में तेल की खुदाई का ठेका दिया. काला धन जमा कराने वालों में केंद्रीय मंत्री विलासराव देशमुख और सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल का नाम लिया गया. इन आरोपों के जवाब में पार्टी ने मौन धारण कर लिया है. लगता है, बाबा रामदेव से कांग्रेस पार्टी डर गई है.

दरअसल, यह मामला अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुआ. बाबा के शिविर में कांग्रेस के सांसद निनोंग एरिंग मौजूद थे. बाबा रामदेव अपने शिविरों में योग के साथ-साथ राजनीति की बातें करते हैं. बाबा ने गांधी परिवार पर कुछ टिप्पणी की तो सांसद एरिंग ने विरोध किया. बाबा का आरोप है कि कांग्रेसी सांसद ने उन्हें ब्लडी इंडियन कहा. वहां मीडिया था, कैमरे थे, इस पूरे मामले का वीडियो इंटरनेट पर भी उपलब्ध है. घटना के बाद बाबा रामदेव का बयान भी है, लेकिन हैरानी इस बात की है कि सांसद ने जो कुछ कहा, उसका वीडियो कहीं नहीं दिखा. निनोंग एरिंग सफ़ाई देते रहे कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, लेकिन तीर कमान से निकल चुका था. बाबा रामदेव और कांग्रेस की जंग शुरू हो चुकी थी. इसके तुरंत बाद कांग्रेस के प्रो-एक्टिव महासचिव दिग्विजय सिंह ने मोर्चा संभाला. बाबा रामदेव द्वारा कांग्रेस के ख़िलाफ बयानबाजी और गांधी परिवार पर आरोप लगाने की उन्होंने भर्त्सना की और बाबा के धन का हिसाब मांग लिया. दिग्विजय सिंह ने कहा कि बाबा रामदेव के पास इतने पैसे कहां से आए, इसका भी हिसाब उन्हें देना चाहिए. मामले ने तूल पकड़ा. बाबा रामदेव एक फाइल के साथ हर टीवी चैनल पर नज़र आने लगे. वह फाइल पतंजलि ट्रस्ट के इनकम टैक्स रिटर्न की थी. अचानक दिग्विजय सिंह भी चुप हो गए. कांग्रेस का हमला बंद हो गया, लेकिन रामदेव ने नए सिरे से हमला शुरू कर दिया.

दिल्ली के रामलीला मैदान में बाबा ने रैली की. भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ लड़ने वाले चेहरों को स्टेज पर बुलाया. कांग्रेस पर एक से बढ़कर एक आरोप लगाने शुरू कर दिए. आरोप भी ऐसे कि जिन्हें सुनकर देश के तबाह होने का डर पैदा हो जाता है. इन आरोपों के जवाब में कांग्रेस ने कुछ भी नहीं कहा. किसी नेता ने कोई जवाब नहीं दिया या रामदेव पर कोई हमला नहीं किया. हैरानी की बात यह है कि दिग्विजय सिंह ने भी मौन धारण कर लिया. कांग्रेस के कई नेताओं से बातचीत के दौरान यह समझ में आया कि कांग्रेस के हर लीडर को बाबा रामदेव और उनके सहयोगियों द्वारा लगाए गए आरोपों के बारे में जानकारी है. फिर ऐसा क्या हुआ. ऐसा क्या निर्देश दिया गया. ऐसा क्या फ़ैसला लिया गया कि कांग्रेसी नेताओं की पूरी मंडली में एक भी ऐसा नहीं है, जिसने बाबा के ख़िलाफ़ मुंह खोला हो. बात यहीं ख़त्म नहीं हुई. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी ने यह कहकर चौंका दिया कि पार्टी के महासचिव दिग्विजय सिंह का बयान उनका निजी बयान है, कांग्रेस पार्टी को इससे कुछ लेना-देना नहीं है.

इसका मतलब तो यह है कि जो सत्यव्रत चतुर्वेदी कह रहे हैं, वही पार्टी का फ़ैसला है. वही सोनिया गांधी का फ़ैसला है. बाबा रामदेव के आरोपों पर कांग्रेस में बहस हुई. एक योजना बनी. यह तय किया गया कि बाबा रामदेव को इग्नोर किया जाए. रामलीला मैदान की रैली में कांग्रेस पर जो आरोप लगे, उनसे कांग्रेस में हड़कंप मच गया. जिस तरह के आरोप लगाए गए, वे बिल्कुल आरएसएस स्टाइल के आरोप थे. काला धन से यह मामला सोनिया गांधी तक चला गया.

कांग्रेस के कुछ नेताओं ने सोनिया गांधी को यह समझा दिया कि दिग्विजय सिंह की वजह से ही बाबा रामदेव आरोप लगा रहे हैं. दिग्विजय अगर मुंह नहीं खोलते तो बाबा रामदेव नहीं बोलते. कुछ कांग्रेसी नेता तो यह भी कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह ने जानबूझ कर बयान दिया. मतलब यह कि इस विवाद के लिए दिग्विजय सिंह ही ज़िम्मेदार हैं. इन नेताओं ने सोनिया गांधी को डराया कि रामदेव को हमने ही मुद्दा दे दिया. हम पहले से ही घोटालों में घिरे हुए हैं. मनमोहन सिंह सरकार ठीक से काम नहीं कर पा रही है. महंगाई है. ऐसे में बाबा रामदेव से टकराना ठीक नहीं है. फिर सोनिया गांधी को यह समझाया गया कि कांग्रेस के कुछ नेता बाबा रामदेव को ख्वामखाह बड़ा बना रहे हैं. बेवजह हम बाबा रामदेव को ख़तरा समझ रहे हैं. यह भी समझाया गया कि अगर कांग्रेस पार्टी कोई प्रतिक्रिया देती है तो बाबा रामदेव देश में घूम-घूमकर कांग्रेस के ख़िलाफ़ बयानबाज़ी करेंगे. बाबा रामदेव के साथ जनता का समर्थन है, इसलिए पार्टी को नुक़सान हो सकता है. स्वाभिमान आंदोलन की भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ लड़ाई में सिर्फ़ कांग्रेस निशाने पर आ जाएगी. इसलिए बाबा रामदेव के आरोपों का जवाब न देकर ही इस मामले को ठंडा किया जा सकता है. पार्टी की इसी में भलाई है. कांग्रेस पार्टी बाबा रामदेव से डर गई और उसने बाबा रामदेव के आरोपों पर चुप्पी साध ली. दिग्विजय सिंह के बयान को उनका निजी बयान क़रार दिया गया.

इस घटना से कांग्रेस पार्टी की मानसिकता और राजनीति दोनों ही उजागर हो गई. कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में दक्षिणपंथी मानसिकता वालों की अच्छी ख़ासी संख्या है. ये मुखर भी हैं. इनका दबदबा भी चलता है.

(शेष पृष्ठ 2 पर)

“हम चाहते हैं कि बाबा जी भी इस बात का ध्यान रखें कि उनको जो दान मिलता है, वह कहीं काला धन तो नहीं है. बाबा जी से मेरी यही प्रार्थना है कि सबको एक लाठी से न लपेटा करें और सोच-समझ कर बयान दिया करें. क्या पूंजीवादी बस कांग्रेस में हैं और उनके साथ कोई पूंजीवादी नहीं है? कोई ग़रीब आदमी उन्हें दान देता है क्या?”

-दिग्विजय सिंह

“यह व्यक्तिगत झगड़ा है दोनों का, पार्टी का इससे कोई लेना-देना नहीं है. दिग्विजय सिंह ने अनेक बार ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं, जिनको पार्टी ने कहा कि यह उनकी व्यक्तिगत भावना है, व्यक्तिगत सोच है. यह बाबा और दिग्विजय सिंह के बीच की बात है, कांग्रेस और बाबा के बीच की नहीं है.”

-सत्यव्रत चतुर्वेदी

सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख को देखते हुए ऐसी उम्मीद की जा रही है कि सरकार इस पद के लिए किसी गैर आईएएस अधिकारी के नाम पर भी विचार कर सकती है.

दिल्ली का बाबू

बड़े बदलाव का इंतजार

हाल में कैबिनेट में हुए फेरबदल को देखकर ऐसा लगा, जैसे उक्त फेरबदल बेमन से किए गए थे और उत्साहविहीन थे. अब बड़े पदों पर बैठे बाबुओं में फेरबदल, जो लंबे समय से लंबित है, की प्रतीक्षा की जा रही है. सबसे पहले तो सीवीसी के पद पर कौन आएगा, इसी का इंतजार है. सूत्रों की मानें तो इस पद के लिए केंद्रीय वित्त सचिव सुषमा नाथ और केंद्रीय गृह सचिव जी के पिल्लई के नामों पर विचार चल रहा है. सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख को देखते हुए ऐसी उम्मीद की जा रही है कि सरकार इस पद के लिए किसी गैर आईएएस अधिकारी के नाम पर भी विचार कर सकती है. दूसरी ओर, यूपीए सरकार में के एम चंद्रशेखर की जगह कैबिनेट सचिव पद के लिए पुलक चटर्जी, जो अभी विश्व बैंक में हैं, के नाम पर भी विचार हो सकता है. विदेश मंत्रालय में भी व्यापक बदलाव होने की बात कही जा रही है. वर्तमान विदेश सचिव निरूपमा राव अमेरिका में भारतीय राजदूत के रूप में अपनी ही बैचमेट मीरा शंकर की जगह ले सकती हैं. राव का कार्यकाल आगामी जून में खत्म हो रहा है.

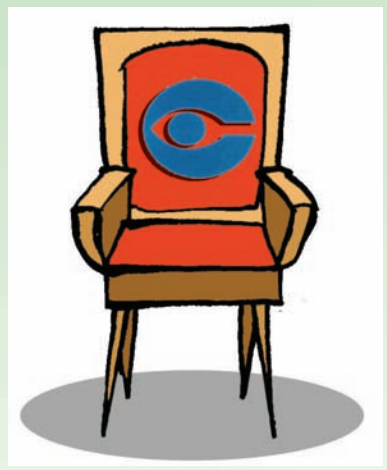

डीओटी की मुसीबत

ब्लैकबेरी सर्वर्स से संबंधित सूचना हासिल करने में नाकामी मिलने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस मामले से अपना हाथ खींच लिया है और इसकी जिम्मेदारी दूरसंचार विभाग पर डाल दी है. बहरहाल, इसके बाद गृह मंत्रालय के बाबुओं के लिए तो स्थिति आराम की हो गई है, लेकिन पहले से ही परेशान दूरसंचार विभाग के बाबुओं के लिए मुश्किलें पैदा हो गई हैं. एक तो दूरसंचार विभाग पहले से ही 2-जी मामले से निपटने में व्यस्त है और ऊपर से ब्लैक बेरी का एक और नया मामला. क्या दूरसंचार विभाग उन मुद्दों से निपट पाएगा, जिनसे गृह मंत्रालय के बाबू हार मान गए.

गलती किसकी

दिलीप चेरियन

जम्मू-कश्मीर सरकार में एक आईपीएस अधिकारी के जबरन रिटायरमेंट का मामला अब हाईकोर्ट में पहुंच गया है. जाली जन्म तिथि को लेकर आईजीपी फारुक अहमद को पिछले महीने रिटायर कर दिया गया था. अहमद ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. दिलचस्प रूप से जब अहमद को उनके पद से हटाया गया, तब इसके लिए उंगली उठी दिल्ली की ओर. सूत्रों का कहना है कि अहमद ने 1977 में राज्य पुलिस ज्वाइन की थी. तब उन्होंने अपनी जन्म तिथि में सुधार के लिए भी कहा था, जो स्कूल रिकॉर्ड में गलत दर्ज हो गई थी. यह मुद्दा वहीं खत्म हो गया होता, लेकिन राज्य सरकार ने जन्म तिथि में सुधार करने के बाद उसकी सूचना केंद्रीय गृह मंत्रालय को नहीं दी. इसके बाद 2001 से ही इस मामले से जुड़ी फाइल सरकार के रिकॉर्ड से गायब हो गई. फिलहाल यह मुद्दा अदालत में है और हम यह आशा करते हैं कि अंत में सच्चाई सामने आ ही जाएगी.

dilipcherian@gmail..com

साउथ ब्लॉक

आशीष बने एफए

राजस्थान कैडर और 1978 बैच के आईएएस अधिकारी आशीष बहुगुणा को कृषि विभाग में वित्तीय सलाहकार (एफए) और अतिरिक्त सचिव की जिम्मेदारी दी गई है. वह ए एस लांबा की जगह लाए गए हैं. बहुगुणा अभी कृषि विभाग में ही अतिरिक्त सचिव के पद पर थे.

जितेंद्र बने जेएस

वर्ष1990 बैच के आईएएस अधिकारी जितेंद्र नारायण लोक उद्यम विभाग में संयुक्त सचिव बनाए गए हैं. वह राकेश सारवाल की जगह नियुक्त किए गए हैं. सारवाल को आयुष विभाग में भेजा गया है.

निशा को शहरी विकास का जिम्मा

हिमाचल प्रदेश कैडर और 1987 बैच की आईएएस अधिकारी निशा सिंह को शहरी विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव बनाने की कवायद पूरी हो चुकी है. इस पद पर ए के मेहता थे, जो जनवरी में ही डीसीसीआईएल में सीवीओ पद पर जा चुके हैं.

पैनल ढूंढेगा जेएस

वित्तीय सेवा विभाग में संयुक्त सचिव पद पर किसे लाया जाए, इसके लिए एक पैनल गठित किया गया है. अभी तक इस पद पर वी एपेन थे, जो आईएमएफ, वाशिंगटन चले गए हैं.

वशिष्ठ बने निदेशक

वर्ष1994 बैच के आईएफएस अधिकारी सत्य प्रकाश वशिष्ठ ग्रामीण विकास विभाग के नए निदेशक होंगे. वह नितेन चंद्रा की जगह लेंगे. चंद्रा को संयुक्त सचिव बनाया गया है.

लगता है बाबा रामदेव से कांग्रेस डर गई

पृष्ठ एक का शेष

कांग्रेस के इसी दक्षिणपंथी गुट ने एक तरफ़ सोनिया को डराया, दूसरी तरफ़ राहुल गांधी की तरफ दबाव दिया गया कि वह दिग्विजय सिंह से किनारा करें. दरअसल ये लोग रामदेव को मौक़ा देना चाहते हैं कि वह देश में घूम-घूमकर कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज खड़ी कर लें. कांग्रेस के जवाब देने या न देने से रामदेव चुप होने वाले तो हैं नहीं. जबसे लोकसभा चुनाव शुरू हुए हैं, तबसे काले धन का मामला लेकर रामदेव ने हमला शुरू किया. इस विवाद से पहले भी वह कांग्रेस के ख़िलाफ़ बोल रहे थे. अब जब लड़ाई आमने-सामने की हो गई है तो उनका हमला और भी तेज़ हो गया है. कांग्रेस में एक दूसरा तबका भी है, जो बाबा रामदेव से दो-दो हाथ करना चाहता है. बाबा के ख़िलाफ़ लगे आरोपों की जांच कराना चाहता है. उनके हर आरोप का जवाब देना चाहता है, लेकिन कांग्रेस की यह वामपंथी लॉबी ख़ामोश है. शायद उनका अस्तित्व नहीं है. अगर है भी, तो पता नहीं वे किस मांद के अंदर बैठे हैं. संगठन में उनका दबदबा ख़त्म हो गया है. उन्हें हम अब कह सकते हैं कि वे कांग्रेस के विलुप्त प्राणियों में से हैं. कुछ सांसदों ने पार्टी में अपना नंबर बढ़ाने के लिए रामदेव के नार्को टेस्ट की बात ज़रूर कही, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि वे पार्टी की तरफ़ से नहीं, बल्कि एक सांसद होने के नाते यह मांग कर रहे हैं. कांग्रेस पार्टी अपने ही सांसदों की मांगों पर भी मौन है.

कांग्रेस के नेताओं ने एक तो सोनिया को डराया, दूसरा दिग्विजय सिंह को राहुल गांधी से दूर करने की चाल चली. राहुल गांधी ने सोनिया से बात करने की कोशिश की. समझने वाली बात यह है कि बाबा रामदेव राहुल गांधी से चुपके से मिले. वह चुपके से मिलने हरिद्वार भी जाते हैं. चुपके से इसलिए, क्योंकि तब मीडिया नहीं जाता. किसी को पता भी नहीं चलता. तब बाबा प्रेस को नहीं बुलाते. कई कांग्रेसी नेता दबी ज़ुबान में यह कहते हैं कि बाबा रामदेव को शुरुआत में कांग्रेस ने ही मदद की. सरकारी धन मुहैय्या कराया. उस वक़्त कांग्रेस के नेताओं को यह लगा कि बाबा रामदेव अगर पार्टी बना लेते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के ही वोट काटेंगे. बाबा रामदेव की राजनीति से कांग्रेस पार्टी को ही फ़ायदा होगा. बाबा रामदेव के ख़िलाफ़ जब दिग्विजय सिंह ने बयान दिया तो दक्षिणपंथी लॉबी परेशान हो गई. बाबा ने दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं को राहुल गांधी से अलग करने की भी कोशिश की, ताकि राहुल के आसपास भी दक्षिणपंथियों की भीड़ लग जाए. आज की तारीख़ में राहुल गांधी राजनीतिक मामले में दिग्विजय सिंह की बात सुनते हैं. यही वजह है कि दिग्विजय सिंह के एक बयान ने बाबा रामदेव को इतना परेशान कर दिया कि उन्होंने खुलेआम सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर हमला कर दिया.

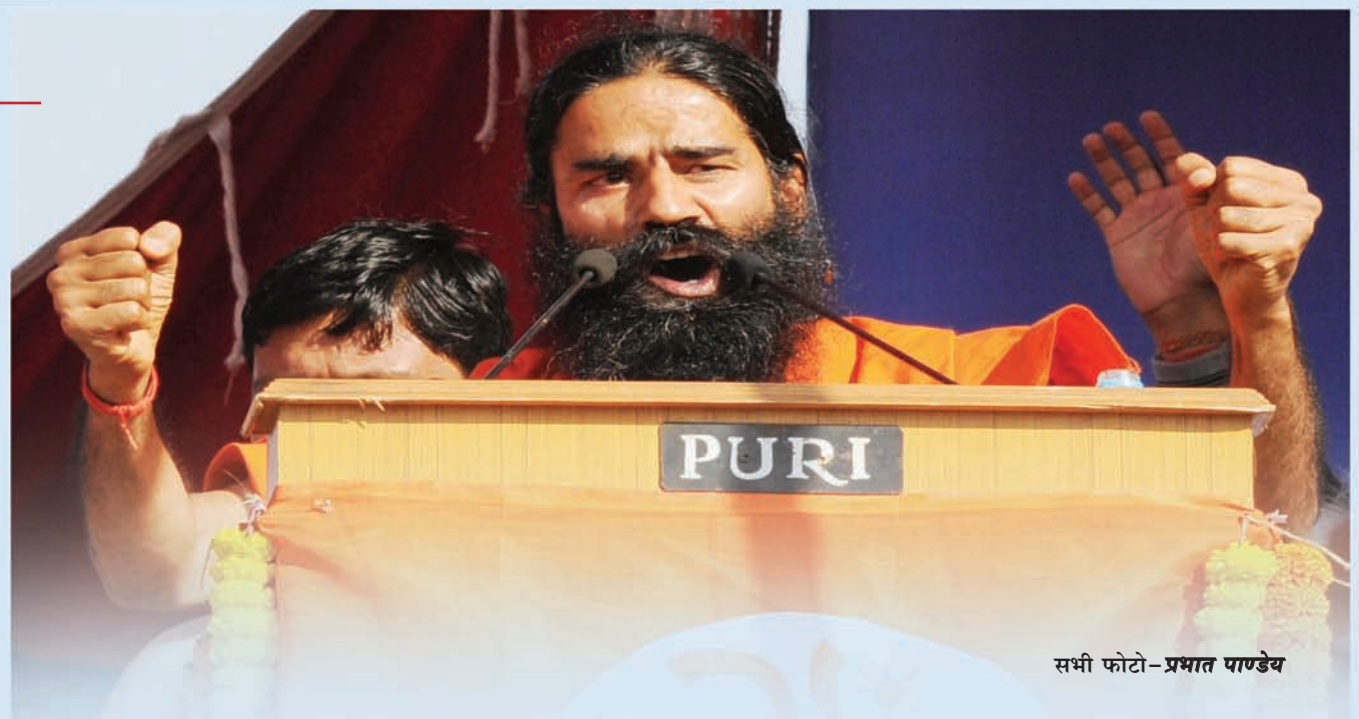

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

दिग्विजय सिंह कांग्रेस के सबसे प्रो-एक्टिव महासचिव हैं. राहुल गांधी के निकट हैं. पार्टी में उनकी अहमियत इसलिए है, क्योंकि वह एकमात्र ऐसे नेता हैं, जो कांग्रेस का मुस्लिम चेहरा बनकर उभरे हैं. आज की तारीख में दिग्विजय सिंह के अलावा कोई दूसरा नेता नहीं है, जिस पर देश के मुसलमान भरोसा करते हों. मुसलमानों के संगठनों से उनका संपर्क है. कांग्रेस पार्टी दिग्विजय सिंह के ज़रिए ही मुस्लिम संगठनों से बातचीत करती है. एक और खासियत यह है कि कांग्रेस में दिग्विजय सिंह के अलावा आरएसएस से लड़ने वाला कोई मुखर नेता नहीं है. आरएसएस के ख़िलाफ़ बयानबाजी हो, दिल्ली के बाटला हाउस में आजमगढ़ के छात्रों का एनकाउंटर हो, भगवा आतंक का विरोध हो, हर जगह दिग्विजय सिंह मुसलमानों के साथ खड़े नज़र आते हैं. बाबा रामदेव और कांग्रेस की लड़ाई की जड़ में दिग्विजय सिंह हैं. अगर दिग्विजय सिंह को पार्टी दरकिनार करती तो वह मुसलमानों के एजेंडे से दूर होती नज़र आती. समझने वाली बात यह है कि दिग्विजय सिंह मुस्लिम एजेंडे को उठाते ज़रूर हैं, लेकिन उन मुद्दों को, जिन्हें हम भावनात्मक कह सकते हैं. बेहतर तो यह होता कि दिग्विजय सिंह सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट के लिए संघर्ष करते तो मुसलमानों की परेशानी कम होती. असलियत यह है कि मुसलमानों को गुमराह करने में कांग्रेस ने कभी कोई कमी नहीं की. दिग्विजय सिंह भी यही कर रहे हैं.

कांग्रेस का इतिहास रहा है कि पार्टी में कभी भी वैचारिक पवित्रता कोई मुद्दा ही नहीं रही. यह बहुत बड़ी ख़ूबी भी है और कमज़ोरी भी कि कांग्रेस में अलग-अलग विचारधारा के लोग एक साथ काम करते रहे हैं, आपस में वर्चस्व की लड़ाई लड़ते रहे हैं. कांग्रेस को ऐसे लोगों ने भी नेतृत्व दिया है, जो हिंदू महासभा के लीडर हुआ करते थे. महात्मा गांधी मध्यमार्गी थे तो जवाहर लाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का झुकाव वामपंथ की ओर था. सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस के दक्षिणपंथियों ने ही विरोध किया था. इंदिरा जी हमेशा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लड़ती थीं. राजीव गांधी के समय से आरएसएस से यह लड़ाई कमजोर पड़ गई. जब राजीव गांधी को 412 सीटें मिली थीं, तब आरएसएस ने कांग्रेस की मदद की थी. कांग्रेस पार्टी का रोल बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि प्रकरण में विवादास्पद है. गुजरात में कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्ववादी पार्टी भी इन्हीं नेताओं की वजह से बन गई है. कांग्रेस का यही तबका सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट पर कार्रवाई करने में अड़चनें खड़ी करता है. पिछले 15 सालों में जबसे मनमोहन सिंह वित्तमंत्री हुए हैं, तबसे पार्टी में दक्षिणपंथियों का वर्चस्व बढ़ गया है. कार्यशैली बदल गई है. इनएक्शन को एक्शन समझ लिया गया है. निर्णय न लेना भी निर्णय बन गया है. चुप्पी जवाब बन गई है. आज नेहरू और इंदिरा गांधी की पार्टी का आलम यह है कि रामदेव और उनके सहयोगियों ने कांग्रेस पर आरोपों की झड़ी लगा दी है और पार्टी ने जवाब न देना ही सबसे सही जवाब मान लिया है. पांच राज्यों में चुनाव हो रहे हैं. इन चुनावों में भ्रष्टाचार सबसे मुख्य मुद्दा है. काले धन को लेकर आम जनता में रोष है. यह भी एक वजह है कि कांग्रेस बाबा रामदेव से टक्कर लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाई.

राजनीति भी अजब खेल है. यह कभी-कभी सर्वशक्तिमान को शक्तिहीन और एक फक्कड़ को सर्वशक्तिमान बना देती है. कांग्रेस के पास सरकार है, सरकार के पास जांच एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियों के पास शक्ति है, फिर भी पूरा कुनबा चुप है. रामदेव और उनके साथियों द्वारा लगाए गए आरोप अगर गलत हैं तो कांग्रेस को यह चुप्पी तोड़नी चाहिए. हर आरोप की जांच होनी चाहिए. अगर यह चुप्पी बनी रही तो लोग तो यही समझेंगे कि बाबा और उनके साथियों ने जो आरोप लगाए हैं, वे सच हैं.

manish@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 3 अंक 2
दिल्ली, 21 मार्च–27 मार्च 2011
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय

के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा
गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.

संपादकीय 0120-4783999/11-23418962
विज्ञापन व प्रसार +91 120 4783999
+91 9871194800
फैक्स न. 0120-4783950

पृष्ठ-16+4+4+4 (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड एवं पश्चिम उत्तर प्रदेश)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

बिहार

फोरेंसिक साइंस लेबोरेट्री का फर्जीवाड़ा

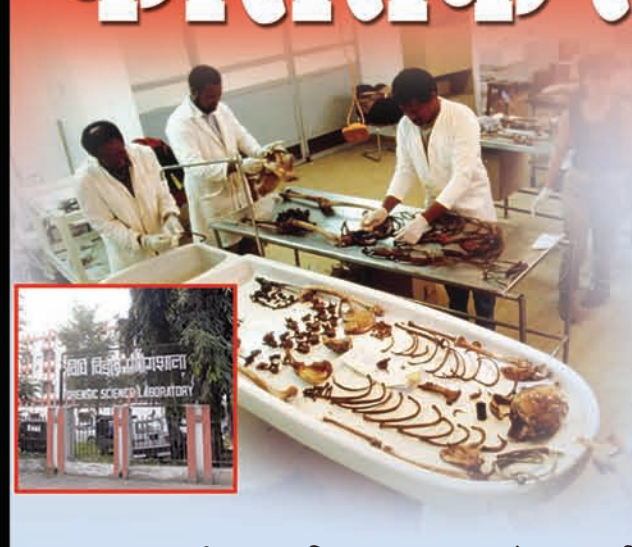

राजधानी पटना स्थित अपराध अनुसंधान विभाग (सीआईडी) अंतर्गत आने वाली विधि विज्ञान प्रयोगशाला भ्रष्टाचार और नाजायज़ कमाई का अड्डा बन गई है. इस प्रयोगशाला में नियम–क़ानूनों को ताक़ पर रखकर बिना किसी जांच के मनमाने तरीक़े से बिसरा जांच प्रतिवेदन निर्गत किए जा रहे हैं. अप्रशिक्षित, अराजपत्रित एवं अनाधिकृत लोगों के हस्ताक्षर से निर्गत फ़र्ज़ी बिसरा जांच प्रतिवेदन के चक्कर में पड़कर हज़ारों निर्दोष जेल जा चुके हैं अथवा सज़ा काट रहे हैं. ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया है, जो आने वाले समय में सुशासन के लिए काला धब्बा साबित हो सकता है, क्योंकि गृह विभाग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अधीन है.

निर्दोषों को फंसाने का यह घिनौना खेल खेलने वालों को न तो क़ानून और न्यायालय का डर है और न सरकार की प्रतिष्ठा गिरने की चिंता. विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल पटना) की इतनी महत्वपूर्ण रिपोर्ट की गंभीरता को कोई समझने वाला नहीं है और यह फोरेंसिक साइंस लेबोरेट्री के बजाय फाल्स एंड फेब्रिकेटेड साइंस लेबोरेट्री की तरह काम कर रही है. नियम–क़ानूनों को ताक पर रखकर एक नहीं, सैकड़ों रिपोर्ट्स इस विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा नाजायज़ लाभ लेकर निर्गत की गई हैं, जिनकी कोई वैधानिक मान्यता ही नहीं है. अवैध रूप से जांच प्रतिवेदन निर्गत करने वाले अराजपत्रित, अप्रशिक्षित एवं अनाधिकृत पदाधिकारी–कर्मचारी मालामाल हो रहे हैं और निर्दोष लोगों को जेल जाना पड़ रहा है.

इस प्रयोगशाला की विष विज्ञान प्रशाखा में बिसरा की जांच होती है, जो राजपत्रित एवं प्रशिक्षित सहायक निदेशक के निर्देशन में गठित टीम द्वारा की जाती है. पुलिस मैनुअल के अनुसार यह जांच संबंधित प्रशाखा के राजपत्रित एवं प्रशिक्षित सहायक निदेशक के निर्देशन में गठित टीम द्वारा होनी चाहिए और परिणाम को जांच प्रतिवेदन पर अंकित कर उसे सहायक निदेशक के हस्ताक्षर एवं निदेशक/प्रभारी निदेशक के प्रति हस्ताक्षर से न्यायालय को निर्गत किया जाता है, लेकिन विभाग इन तमाम प्रावधानों की धज्जियां उड़ाकर मनमाने ढंग से काम करके मोटी कमाई कर रहा है. आश्चर्यजनक बात यह है कि विष विज्ञान प्रशाखा में पिछले एक दशक से कोई राजपत्रित पदाधिकारी तैनात नहीं है. ऐसी स्थिति में पटना की प्रयोगशाला में बिसरा की जांच नहीं हो सकती. इसलिए बिसरा को जांच के लिए देश की अन्य प्रयोगशालाओं में भेजा जाना चाहिए, लेकिन नाजायज़ कमाई के चक्कर में बिसरा को बिना जांचे ही प्रशाखा के तृतीय श्रेणी के कर्मचारी सुरेश पासवान के हस्ताक्षर से क़रीब 560 बिसरा जांच प्रतिवेदन निर्गत किए जा चुके हैं. इतना ही नहीं, कभी भंडाफोड़ न हो या इससे प्रभावित कोई व्यक्ति चुनौती देकर दोबारा जांच न करा ले, इसलिए महत्वपूर्ण प्रदर्शों (मानव अंगों) को नष्ट करके साक्ष्य मिटाने का अपराध किया जा रहा है.

फतुहा थाना कांड संख्या–257/07 में निर्गत बिसरा जांच प्रतिवेदन 54/08 इसका ज्वलंत उदाहरण है, जिसमें प्रतिष्ठित अधिवक्ता रत्नेश कुमार पाठक एवं उनका पूरा परिवार बिना अपराध किए आज तक परेशान है. विधायक मंजीत कुमार सिंह ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रयोगशाला में चल रहे घिनौने खेल से अवगत कराया है.

नाजायज़ लाभ के लिए निर्गत बिसरा जांच प्रतिवेदन संख्या 54/08 नियम–क़ानूनों एवं प्रावधानों की धज्जियां उड़ाकर रत्नेश कुमार पाठक एवं उनके पूरे परिवार को फंसाने की बात प्रमाणित करता है. सीआरपीसी की धारा 293 के तहत 3 जुलाई, 2008 को निर्गत उक्त बिसरा जांच प्रतिवेदन पर सुरेश पासवान (प्रौद्योगिकी) के हस्ताक्षर एवं प्रभारी निदेशक के रूप में शिव लखन सिंह के प्रति हस्ताक्षर हैं. इस जांच प्रतिवेदन पर मेमो नंबर निल और दिनांक 18–12–07 अंकित है. इसके पार्सल कॉलम में कोई मानव अंग वर्णित न होकर सम डार्क ब्राउन फ्लूड की चर्चा की गई है, जबकि नालंदा मेडिकल कॉलेज के पत्रांक 215 में अंकित है कि बिसरा के रूप में क़रीब नौ मानव अंग मेमो नंबर 37/07 दिनांक 17–12–07 द्वारा फतुहा थाना के भरत सिंह को सौंपे गए थे. गृह (आरक्षी) विभाग के पत्रांक 7160 एवं अपराध अनुसंधान विभाग के पत्रांक 705 में स्पष्ट अंकित है कि सुरेश पासवान, जो प्रौद्योगिक पदाधिकारी (अराजपत्रित) हैं, बिसरा जांच प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत नहीं हैं और प्रभारी निदेशक श्याम बिहारी उपाध्याय हैं. शिव लखन सिंह उपकरण प्रशाखा के सहायक निदेशक हैं. इसलिए बिसरा जांच प्रतिवेदन संख्या 54/08 में मेमो नंबर निल होना, दिनांक 17–12–07 की जगह 18–12–07 होना, उपकरण प्रशाखा के सहायक निदेशक शिव लखन सिंह का प्रभारी निदेशक के रूप में प्रति हस्ताक्षर करना और अनाधिकृत, अप्रशिक्षित एवं अराजपत्रित सुरेश पासवान का जांच पदाधिकारी के रूप में हस्ताक्षर करके प्रतिवेदन निर्गत किया जाना विधि विज्ञान प्रयोगशाला में चल रहे गोरखधंधे का पर्दाफ़ाश करता है.

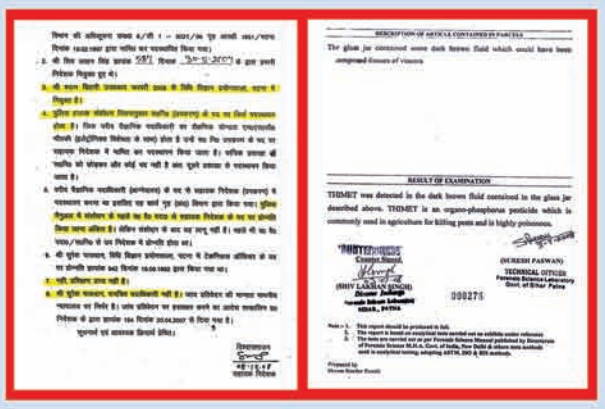

आश्चर्यजनक पहलू यह है कि पुलिस के कुछ पदाधिकारी भी इस मामले में शक के घेरे में हैं, क्योंकि इस बिसरा जांच प्रतिवेदन संख्या 54/08 को अग्रसारण पदाधिकारी–न्यायालय एवं नालंदा मेडिकल कॉलेज को न भेजकर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) को भेजा गया और पुलिस ने भी इसे क़रीब छह माह तक न्यायालय से छुपाए रखा. यह कृत्य पुलिस मैनुअल में वर्णित प्रावधानों, गृह (आरक्षी) विभाग के पत्रांक 7160 एवं अपराध अनुसंधान विभाग के पत्रांक 705 को मुंह चिढ़ाने और बेगुनाहों को साजिशपूर्ण तरीक़े से फंसाने की बात प्रमाणित करता है. जदयू विधायक मंजीत कुमार सिंह ने विधि विज्ञान प्रयोगशाला पटना द्वारा ग़लत तरीक़े से जारी बिसरा जांच प्रतिवेदन संख्या 54/08 समेत 560 प्रतिवेदनों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ध्यान आकर्षित करते हुए पत्र लिखा है. पत्र में विधि एवं न्याय के विपरीत ग़लत बिसरा जांच प्रतिवेदन निर्गत होने से अधिवक्ता रत्नेश कुमार पाठक एवं बिहार के सैकड़ों परिवारों के प्रभावित होने और न्याय से वंचित रहने की बात कही गई है. मंजीत सिंह ने ग़लत बिसरा जांच प्रतिवेदनों से प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाने और दोषी लोगों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है.

कुमुद सिंह
feedback@chauthiduniya.com

गरवी गुजरात

भारत का विकास इंजन

भारत की सिर्फ 5 प्रतिशत आबादी और 6 प्रतिशत भूतल जिम्मेदार है सम्पूर्ण भारत के...

- 17 प्रतिशत अचल पूंजी निवेश
- 22 प्रतिशत निर्यात
- 42 प्रतिशत फार्मास्युटीकल्स
- 62 प्रतिशत पेट्रोकेमिकल्स
- 65 प्रतिशत प्लास्टिक उद्योग
- 80 प्रतिशत हीरा प्रसंस्करण

... और भी बहुत कुछ के लिए

श्री नरेन्द्र मोदी
मुख्यमंत्री, गुजरात

राष्ट्रीय भूमि सुधार समिति ने अपनी एक रिपोर्ट में सरकार को वन अधिकार क़ानून (फारेस्ट राइट एक्ट) को कारगर ढंग से लागू करने की भी सलाह दी थी.

एकता परिषद

इस चेतावनी को सिर्फ़ रैली न समझें

सभी फोटो–प्रभात पाण्डेय

पहले पदयात्रा, फिर चेतावनी रैली और 2012 में एक लाख लोग दिल्ली में. आख़िर पिछले चार साल से इस देश की आम जनता को क्यों बार–बार दिल्ली आकर अपनी बात कहनी पड़ती है. आख़िर उसकी ऐसी कौन सी मांग है, जिसे सरकार पूरी नहीं कर रही या फिर करना नहीं चाहती?

शशि शेखर

वर्ष 2007 में जब 25 हज़ार लोग ग्वालियर से पैदल चलकर दिल्ली आए, तब तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री ने इन्हें आश्वासन दिया. 2009 में जब एक बार फिर ये लोग दिल्ली आए, तब भी इन्हें आश्वासन ही मिला. हर बार सिर्फ़ आश्वासन. नतीजतन, इस बार 15 हज़ार लोग जब दिल्ली आए, तब कोई मांग लेकर नहीं आए. आए तो सिर्फ़ चेतावनी देने. चेतावनी इस बात की कि अगर नई भूमि सुधार नीतियों का पालन ठीक से नहीं किया गया, अगर नेशनल लैंड रिफॉर्म काउंसिल को सक्रिय नहीं किया गया तो हम लाखों की संख्या में दिल्ली आकर बैठ जाएंगे. और तो और, अब एकता परिषद ने, जिसे कल तक गांववालों का आंदोलन माना जाता था, ख़ुद को इंडिया अगेंस्ट करप्शन जैसी मुहिम से जोड़ कर भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ भी हल्ला बोल दिया है. कल तक सिर्फ़ जंगल और ज़मीन पर ग़रीबों, भूमिहीनों एवं आदिवासियों के हक़ के लिए लड़ाई लड़ने वाली एकता परिषद अब जन लोकपाल बिल लाने के लिए भी आवाज़ बुलंद कर रही है.

बीते 6 से 8 मार्च यानी लगातार तीन दिनों तक दिल्ली के रामलीला मैदान में हज़ारों की संख्या में लोग एकत्र थे. ये लोग राष्ट्रीय भूमि नीति बनाने की दिशा में केंद्र सरकार के वादे के अनुसार क़दम न उठाने के विरोध में यहां आए थे. एकता परिषद के बैनर तले आए इन लोगों की बस एक ही मांग है, जो सीधे–सीधे इनके जीने के अधिकार से जुड़ी हुई है. ये सारे लोग भूमिहीन हैं. बहुत से लोगों को खनन, टाइगर रिज़र्व और अन्य विकास परियोजनाओं के नाम पर इनकी ज़मीन से बेदख़ल कर दिया गया है. एकता परिषद के राजगोपाल पी वी ने चौथी दुनिया को बताया कि नेशनल लैंड रिफॉर्म काउंसिल गठित हुए तीन साल से ज़्यादा बीत गए, लेकिन अब तक भूमि सुधार नीति के संबंध में कोई भी ठोस क़दम नहीं उठाया गया है. वह आगे कहते हैं कि इस मसले पर सरकार इतनी असंवेदनशील है कि इस काउंसिल की बैठक तक नहीं होती. इसलिए इस बार हम सरकार को चेतावनी देने आए हैं कि 2012 तक अगर नई भूमि सुधार नीति और राष्ट्रीय भूमि सुधार समिति द्वारा सुझाए गए उपायों को लागू नहीं किया गया तो हम एक लाख लोगों के साथ आएंगे और फिर यहीं बैठकर तब तक शांतिपूर्ण धरना देते रहेंगे, जब तक हमारी मांगें नहीं मान ली जाएंगी.

इस पूरे आंदोलन का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं जंगल और आदिवासी. राष्ट्रीय भूमि सुधार समिति ने अपनी एक रिपोर्ट में सरकार को वन अधिकार क़ानून (फारेस्ट राइट एक्ट) को कारगर ढंग से लागू करने की भी सलाह दी थी. समिति ने अपनी सिफ़ारिश में कहा कि आदिम जनजाति समुदायों के भूमि क़ब्ज़े को मान्यता दे दी जाए. फारेस्ट राइट एक्ट भी आदिवासियों को जंगल एवं वन भूमि पर अधिकार देने की बात करता है. बावजूद उसके आज भी लाखों आदिवासियों को जंगल पर उनके पारंपरिक अधिकार से वंचित किया जा रहा है. राजगोपाल कहते हैं कि जबसे यह एक्ट लागू हुआ है, तबसे ज़मीन के लिए लगभग 30 लाख आवेदन ग़रीब आदिवासियों की तरफ़ से आए. इन 30 लाख आवेदनों में से 19 लाख आवेदनों को वन विभाग ने निरस्त कर दिया. वन विभाग के लोग खुलेआम दादागिरी कर रहे हैं, ग़रीबों से इनकी भूमि छीनी जा रही है.

वर्ष 2007 में 25 हज़ार से अधिक ग़रीब, भूमिहीन लोगों के साथ राजधानी पहुंचे राजगोपाल से सरकार ने शीघ्र ही राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति बनाने का वादा किया था, जिससे भूमिहीनों और वनवासियों को प्राकृतिक संसाधनों पर इनके अधिकार मिल सकें, लेकिन सरकार तीन साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद समुचित क़दम नहीं उठा पाई है. यहां तक कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद की एक भी बैठक अब तक नहीं हो सकी है. इस चेतावनी रैली में आए लोगों से जब बात हुई तो सबका यही कहना था कि हम यहां अपनी रोटी–अपनी खेती के लिए आए हैं. मध्य प्रदेश के डुमरिया से आई दुअसिया देवी कहती हैं कि हम एकता परिषद से इसलिए जुड़े हैं, क्योंकि हमें ज़मीन चाहिए. कटनी की पुष्पा तो कहती हैं कि हम यहां एकता परिषद के लिए आए हैं. ज़ाहिर है, पेट के लिए रोटी और रोटी के लिए ज़मीन की यह लड़ाई एक आम आदमी की ख़ुद की पहचान से भी जुड़ी है. राष्ट्रीय भूमि सुधार समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भूमि एक ऐसी पूंजी है, जो जीवन के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तंत्र का मूल आधार है. ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन का आधार आज भी भूमि और प्राकृतिक संसाधन ही हैं. भूमि अधिकार और प्राकृतिक संसाधनों तक आम आदमी की पहुंच केवल आर्थिक अधिकार का ही प्रश्न नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में बसने वाले सभी लोगों के आत्मविश्वास से जुड़ा अधिकार है. यानी आम आदमी की पहचान और उसके आत्म विश्वास का रिश्ता ज़मीन के इस टुकड़े से भी है, जिसके लिए यह लड़ाई लड़ी जा रही है.

राजगोपाल पी वी के नेतृत्व में एकता परिषद के क़रीब 15 हज़ार कार्यकर्ताओं ने पहले 7 मार्च को राजधानी के रामलीला मैदान से संसद भवन तक रैली निकाली, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने राजगोपाल को शीघ्र ही राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद की बैठक बुलाने और भूमि नीति में सुधार की बात कही. चेतावनी रैली के अंतिम दिन यानी 8 मार्च को 15 राज्यों से आए क़रीब 15 हज़ार भूमिहीन, आदिवासी और दलित महिला–पुरुषों ने जंगल और ज़मीन की मांग के साथ भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ भी संघर्ष करने का संकल्प लिया. एकता परिषद, महिला मंच और भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ बिगुल बजाने वाले अभियान इंडिया अगेंस्ट करप्शन के संयुक्त तत्वावधान में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर राजधानी के रामलीला मैदान में आयोजित एक सभा में भूमि अधिकार के लिए संघर्ष कर सफलता हासिल करने वाली 26 महिलाओं को सम्मानित किया गया.

रैली में पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी, सीपीआई की अमरजीत कौर, जुझारू पुलिस अधिकारी सुरेंद्रजीत कौर, अनिता बस्सी, सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश, तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह, सर्व सेवा संघ की राधा भट्ट, पूर्व सांसद आरिफ़ मोहम्मद ख़ान एवं सूचना अधिकार के लिए काम करने वाले अरविंद केजरीवाल ने भूमिहीन लोगों के आंदोलन का समर्थन करते हुए भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ एकजुट होने का आह्वान किया. रैली में बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, हरियाणा, उड़ीसा, असम, मणिपुर एवं नागालैंड आदि 15 राज्यों से आए ग़रीब, भूमिहीन और आदिवासी लोग शामिल थे. बहरहाल, एकता परिषद की इस चेतावनी रैली ने इस बार कुछ नए संदेश दिए हैं. एक संदेश तो चेतावनी के रूप में सरकार को और दूसरा अलग–अलग दिशाओं में विभिन्न मांगों को लेकर चल रहे आंदोलनों के लिए है. राजगोपाल जब यह कहते हैं कि हम ज़मीन के साथ भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ भी लड़ाई करेंगे तो इसका सीधा अर्थ यही निकलता है कि अब वक़्त एक होने का है. यानी देश में जितने भी आंदोलन जनता की भलाई से जुड़े मुद्दों को लेकर चल रहे हैं, उन सभी को अब एक मंच पर आ जाना चाहिए, ताकि इस सरकार को, जो जानबूझ कर जनता की आवाज़ नहीं सुनना चाहती, नींद से जगाया जा सके.

shashishekhar@chauthiduniya.com

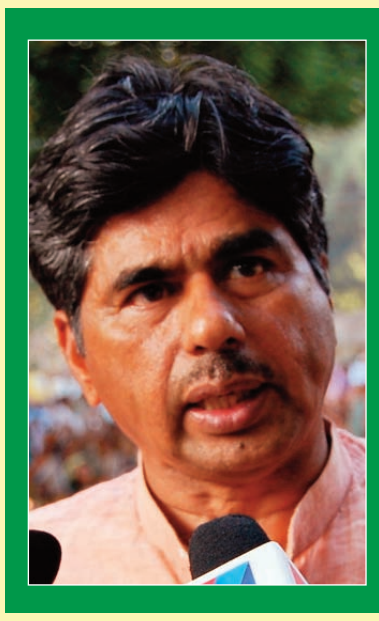

“हमें भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ भी संघर्ष करने की ज़रूरत है. हमारी लड़ाई केवल समुचित भूमि सुधार क़ानून बनवाना नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार जैसी बीमारी को भी ख़त्म करना है. जब तक भ्रष्टाचार है, तब तक कोई भी क़ानून ग़रीबों और वंचितों को उनका वाजिब हक़ नहीं दिला सकता. हम ग्रामीण आंदोलन को शहरी आंदोलन से भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं.”

–राजगोपाल पी वी, एकता परिषद

“भ्रष्टाचार का सीधा ख़ामियाज़ा ग़रीब जनता को भुगतना पड़ता है. रोज़गार, राशन और ज़मीन पर हक़ जैसे मसले सामने हैं. भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ एकता परिषद भी इस लड़ाई में हमारे साथ है. हम जन लोकपाल बिल चाहते हैं, ताकि भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो. हम लोग प्रधानमंत्री से मिले और उनसे कहा कि भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ कार्रवाई किए बिना विकास का कोई अर्थ नहीं है.”

–अरविंद केजरीवाल, सामाजिक कार्यकर्ता

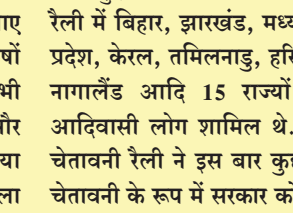

भूमि एक ऐसी पूंजी है, जो जीवन के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तंत्र का मूल आधार है. ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन का आधार आज भी भूमि और प्राकृतिक संसाधन ही हैं. भूमि अधिकार और प्राकृतिक संसाधनों तक आम आदमी की पहुंच केवल आर्थिक अधिकार का ही प्रश्न नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में बसने वाले सभी लोगों के आत्मविश्वास से जुड़ा अधिकार है.

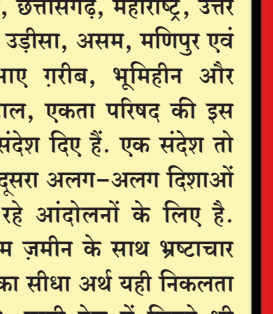

वाममोर्चा सरकार के राज्य में कृषि का काफ़ी विकास हुआ, पर बेरोज़गारों को इसमें खपाने की दर में लगातार गिरावट आ रही है.

पश्चिम बंगाल

ममता युवाओं में आस जगाएंगी

बिमल राय

गर्द के गुबार में आग की तस्वीरें धुंधली दिखती हैं, पर वह आग अगर किसी इंसान की देह में लगी हो तो किसी भी दर्शक की संवेदनाओं के कोमल तंतु को झुलसाने के लिए काफ़ी हैं. बंगाल में इस समय चुनावी गर्द का कोहरा है और प्रसून दत्ता जैसे बेरोज़गार युवक द्वारा आत्मदाह की कोशिश, वह भी बंगाल की उम्मीद ममता बनर्जी के घर के सामने, एक राष्ट्रीय मुद्दा बनती है. चुनावी मौसम में वैसे तो बहुत सारे मुद्दे एक साथ तन कर खड़े हो जाते हैं, पर प्रसून का मामला कई मायनों में अलग है.

राज्य में चुनाव की घोषणा के बाद 6 मार्च को हताश, बेरोज़गार युवक प्रसून दत्ता ममता के कालीघाट वाले घर आता है. ऑफिस के कर्मचारियों से पहले वह अपनी दीदी के बारे में पूछता है. जब उसे बताया जाता है कि वह दिल्ली में हैं तो यह सुनकर युवक ख़ुद को रोक नहीं पाता है. उसके हाथ में किरोसिन भरा जार होता है और वह वहीं अपनी देह में आग लगा लेता है. यह युवक हुगली ज़िले के बांसबेरिया का रहने वाला है. कथित तौर पर स्थानीय तृणमूल नेता सालों से उससे रेलवे में नौकरी दिलवाने का वादा कर रहे थे और वह आश्वासनों से बिल्कुल हताश हो गया था. 80 फ़ीसदी जलकर ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे दत्ता ने बंगाल के नौजवानों में व्याप्त हताशा की एक बानगी भर पेश की है. ज़ाहिर है, मामले पर राजनीति भी होगी. माकपा की युवा शाखा डीवाईएफआई ने इसके ख़िलाफ़ एक रैली भी निकाली और राज्य वाममोर्चा के चेयरमैन विमान बसु ने आरोप लगाया कि बदनामी से बचने के लिए तृणमूल के लोगों ने दत्ता को सरकारी अस्पताल से हटाकर एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया. लगे हाथ उन्होंने बंगाल के युवाओं को चेतावनी भी दी कि वे इस तरह के झांसों से सावधान रहें.

वैसे वाममोर्चा रेल मंत्री की तमाम रेलवे परियोजनाओं को एक झांसा ही बताता रहा है और उन पर पद के दुरुपयोग का आरोप भी लगाता है. हाल में उन्होंने दो सिफ़ारिशी पत्र भी पत्रकारों को दिखाए, जो युवकों में बांटे जा रहे हैं. चुनावी मौसम में आरोपों–प्रत्यारोपों का कोई माई–बाप नहीं होता, पर इसमें कोई शक नहीं कि वाममोर्चा के ख़िलाफ़ हवा बनाने में युवाओं की हताशा का एक बड़ा हाथ है. इस हताशा की सबसे बड़ी वजह बेरोज़गारी है. ज़ाहिर है, इस समस्या के सुरसा होने के लिए 34 सालों से राज कर रहा वाममोर्चा ज़िम्मेदार है. 1977 में जब वाममोर्चा सत्ता में आया तो राज्य में बेरोज़गारों की संख्या 11–12 लाख के बीच थी. साल भर पहले के आंकड़ों पर अगर ग़ौर करें तो यहां फ़िलहाल 64 लाख लोग रोज़गार कार्यालयों के बुलावे का इंतज़ार कर रहे थे. इसमें अगर अपंजीकृत बेरोज़गारों को जोड़ दिया जाए तो यह संख्या लगभग एक करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी. वैसे सरकार ने बेरोज़गारी भत्ते की व्यवस्था की है, पर यह ऊंट के मुंह में ज़ीरे के ही समान है.

श्रम राज्यमंत्री मल्लिकार्जुन खडगे ने संसद में एक सवाल के जवाब में बताया था कि 2007 से 2009 के बीच बंगाल के रोज़गार कार्यालयों ने 13 हज़ार से भी कम युवकों को रोज़गार दिया. 2008 में यह आंकड़ा 5100 और 2009 में सिर्फ़ 2600 नौकरियां युवकों को नसीब हो सकीं. इस मामले में पश्चिम बंगाल का नंबर तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों के बाद आ रहा है. नरेंद्र मोदी को सांप्रदायिक बताने वाले वाले कामरेडों को इस मामले में उनसे जलन हो सकती है. मिसाल के तौर पर वहां 2007 में 1,78,300, 2008 में 2,17,700 और 2009 में 1,53,500 लोगों को रोज़गार कार्यालयों के ज़रिए नौकरी मिली. पूछा जा सकता है राज्य में पसरा सांप्रदायिक सौहार्द क्या रोटी की जगह ले सकता है?

वाममोर्चा सरकार के राज्य में कृषि का काफी विकास हुआ, पर बेरोज़गारों को इसमें खपाने की दर में लगातार गिरावट आ रही है. 2006–07 के आर्थिक सर्वे के मुताबिक़, 1993–94 में कुल रोज़गार में कृषि का हिस्सा 61.67 प्रतिशत था, जो 1999–2000 में घटकर 54.19 प्रतिशत पर आ गया. 2006–07 के सर्वे के अनुसार, 90 के दशक में संयुक्त रूप से संगठित, सरकारी और निजी क्षेत्रों में नियोजन वृद्धि दर में भी गिरावट आई. श्रम मंत्रालय के नियोजन बाज़ार सूचना प्रणाली के तहत कवर किए गए प्रतिष्ठानों में वार्षिक नियोजन वृद्धि 1983–1994 में 1.20 प्रतिशत थी, जो 1994–2004 में घटकर 0.38 प्रतिशत हो गई. हालांकि इस दौरान राज्य सरकार के लिए एक राहत की बात यह रही कि संगठित एवं निजी क्षेत्रों में रोज़गार दर 0.44 प्रतिशत से बढ़कर 0.61 प्रतिशत हो गई. हालांकि राज्य में हर साल बेरोज़गारों की बढ़ती फ़ौज को देखते हुए यह आंकड़ा मामूली ही लगता है. ट्रांसफॉर्मिंग वेस्ट बंगाल–चेंजिंग द एजेंडा फार एन एजेंडा फार चेंज शीर्षक से विवेक देबराय और लवीस भंडारी की ओर से पेश किए गए एक शोधपत्र के मुताबिक़, 2005 में बंगाल देश में कृषि के मामले में 8वें, सबसे कम ग़रीबी के मामले में 12वें, प्रति व्यक्ति आय के मामले में 10वें और निवेश के लिए बेहतर जगह के मामले में 17वें पायदान पर था. अनुमान किया जा सकता है कि 2005 के बाद से हालात में काफ़ी बदलाव नहीं हुए हैं. विश्व बैंक की उप–राष्ट्रीय रैंकिंग में एक बेहतर माहौल में व्यवसाय करने के मानक पर कोलकाता का स्थान जयपुर, भुवनेश्वर, लखनऊ, पटना और रांची के बाद आता है.

बंगाल में अभी वोटरों की तादाद 5,60,87,187 है, जो पिछले साल से 2 प्रतिशत ज़्यादा है. इस साल शामिल किए गए वोटरों में 75 प्रतिशत यानी 11.14 लाख वोटरों की उम्र सीमा 18 से 25 साल के बीच है. राज्य में पिछले चार साल से बदलाव की हवा बह रही है और इस हिसाब से लगभग 45 लाख युवाओं का एक बड़ा हिस्सा नई सरकार की ओर उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा है. 80 फ़ीसदी जला प्रसून अगर बच जाता है तो संभव है कि वह मई में दीदी की ताजपोशी देख ले और उसे मिला आश्वासन भी पूरा हो जाए. हालांकि उसने बहुत जल्दी धैर्य खो दिया. ममता पिछले 34 सालों से इंतज़ार कर रही हैं, पर उन्हीं की पार्टी का पहरुआ साल दो साल के आश्वासन को भी क्यों नहीं झेल पाया?

feedback@chauthiduniya.com

महिला सशक्तिकरण
मिशन मंगलम् कार्यक्रम

मिशन मंगलम् योजना :
महिला सशक्तिकरण से सशक्त भारत का निर्माण

महिला सशक्तिकरण के लिए स्वसहायता समूह एवं
सखी मंडलों को अनोखा प्रोत्साहन

35 अग्रणी कंपनियों सहित फ्यूचर ग्रुप, आईटीसी, मेक्केन, अरविंद, गोदरेज, एग्रोवेट, एबलोन, फेब इंडिया, टाटा मोटर्स, नेशनल एक्सचेंज लिमिटेड ने मिशन मंगलम् कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए दिखलाई प्रतिबद्धता।

15 लाख महिलाओं को जीवन निर्वाह के लिए सहायता।

₹ 20,000 करोड़ रुपये से ज्यादा रकम के पूंजी निवेश : दो लाख सखी मंडलों का गठन

श्री नरेन्द्र मोदी
मुख्यमंत्री, गुजरात

राज्य सरकार द्वारा शीतकालीन चार धाम यात्रा शुरू करने के फ़ैसले को लोग धर्मघाती मानते हैं. उनका कहना है कि यह दुनिया भर में फैले करोड़ों सनातनधर्मियों के साथ घोर अन्याय है.

शीतकालीन चार धाम यात्रा

सनातन धर्म के साथ खिलवाड़

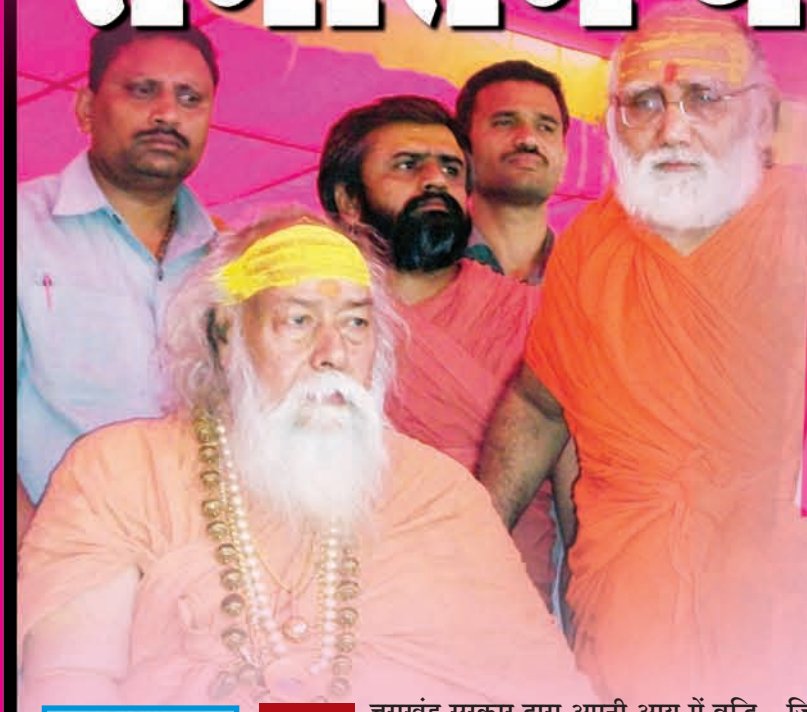

राजकुमार शर्मा

उत्तराखंड सरकार द्वारा अपनी आय में वृद्धि के लिए शीतकालीन चार धाम यात्रा को हरी झंडी दिखाने के बाद राज्य के धर्माचार्य इसे धर्म विरोधी क़दम बताते हुए इसका व्यापक विरोध कर रहे हैं. देवभूमि हिमालय में आदिकाल से चार धाम यात्रा की परंपरा चली आ रही है, जिसका संचालन प्राचीन मान्यताओं के आधार पर वैदिक रीति-रिवाज से होता चला आ रहा है. ऐसी यात्राओं का विशेष धार्मिक महत्व होता है. चार धाम यात्रा राज्य में छह माह तक ही चलती है, इसमें श्रद्धालु गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ एवं केदार नाथ की यात्रा करते हैं. हिमालयी राज्य होने के कारण उक्त सभी धाम शीतकाल में बर्फ़बारी के शिकार हो जाते हैं. मान्यता यह है कि भगवान बद्री नारायण की पूजा छह माह तक मनुष्यों द्वारा और छह माह तक देवताओं द्वारा की जाती है. इसी मान्यता के कारण आज भी जनता उत्तराखंड को देवभूमि के रूप में जानती एवं मानती है. शीतकालीन यात्रा शुरू होने के बाद अब तीर्थयात्री पांडुकेश्वर, ऊखीमठ, मुखवा एवं खरसाली में पूजा करेंगे.

सूबे की निशंक सरकार संस्कृत को द्वितीय राजभाषा के रूप मान्यता प्रदान करके ख़ुद को भारतीय संस्कृति का स्वयंभू पहरेदार समझने-मानने लगी है. इसी के चलते वह कई ऐसे फ़ैसले ले रही है, जिन्हें राज्य को समृद्धि दिलाने की दृष्टि से भले ही महत्वपूर्ण माना जा सकता है, लेकिन धार्मिक दृष्टि से उचित नहीं माना जा रहा है. इसीलिए शीतकालीन चार धाम यात्रा के निर्णय का जनता और धर्माचार्यों द्वारा व्यापक विरोध किया जा रहा है. लोग इसे सरकार का मनमाना फ़ैसला मान रहे हैं. उनका मानना है कि सरकार का यह क़दम पूरी तरह से धर्म के साथ-साथ देवभूमि की संस्कृति का भी विरोधी है. फ़ैसला लेने से पहले सरकार ने धर्माचार्यों, शंकराचार्य, विद्वत समाज और जनसामान्य से भी कोई राय-मशविरा नहीं किया, जबकि आज भी भगवान बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम को गर्मियों में खोलने की तिथियों का फ़ैसला राज्य सरकार नहीं, टिहरी के पूर्व राजघराने के प्रांगण में शिवरात्रि एवं वसंत पंचमी के दिन विद्वत समाज द्वारा लिया जाता है.

राज्य सरकार द्वारा शीतकालीन चार धाम यात्रा शुरू करने के फ़ैसले को लोग धर्मघाती मानते हैं. उनका कहना है कि यह दुनिया भर में फैले करोड़ों सनातनधर्मियों के साथ घोर अन्याय है. उनका तर्क है कि बद्रीनाथ धाम को मोक्ष धाम की मान्यता हासिल है, जहां पहुंच कर तीर्थ यात्रियों की मोक्ष की कामना पूरी होती है. कपाली एवं तप्तकुंड में स्नान और पंच बद्री-पंच केदार सहित विभिन्न देवालयों के दर्शन से उनके पितरों का उद्धार हो जाता है. शीतकालीन यात्रा में नारायण की पूजा पांडुकेश्वर में संपन्न होगी. बद्रीनाथ धाम के कई वेदपाठियों का कहना है कि सरकार ने जनता के साथ ठगी का यह नया तरीक़ा निकाला है, जिसे धर्मसम्मत नहीं कहा जा सकता. इस यात्रा को शुरू करने के पूर्व निशंक सरकार ने ख़ूब ढोल-नगाड़े पीटे. जब यात्रा जोशीमठ पहुंची तो उसे भारी विरोध झेलना पड़ा. पूरी यात्रा को कड़ी सुरक्षा के मध्य गुज़रना पड़ा. सरकार के तमाम प्रयासों को नकारते हुए जोशीमठ नगरपालिका के अध्यक्ष ऋषि प्रसाद शती ने स्थानीय लोगों के साथ अपना विरोध दर्ज कराया.

विद्वत समाज का कहना है कि सरकार चाहे तो वह इसे पर्यटक यात्रा कहकर चला सकती है, चार धाम यात्रा के नाम से नहीं. चार धाम के नाम पर यात्रा का संचालन दुनिया भर के हिंदुओं के साथ छल होगा, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. ज्योतिष पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती इस तरह की यात्रा को सरकारी फरेब मानते हैं. उन्होंने कहा कि शीतकालीन यात्रा शुरू करने से पूर्व सरकार ने धर्मगुरुओं एवं शंकराचार्यों को उनकी राय जानने के लिए आमंत्रित तक नहीं किया. इस यात्रा को शंकराचार्यों का समर्थन नहीं प्राप्त है. राज्य सरकार जिस तरह गंगा के साथ छल कर रही है, उसी तरह वह धन कमाने के लिए नर-नारायण दोनों के साथ छल करने जा रही है, यह महापाप है और सनातन धर्म विरोधी भी.

पूर्व गृह राज्यमंत्री एवं संत चिन्मयानंद सरस्वती शीतकालीन चार धाम यात्रा के संचालन, समय निर्धारण-परिवर्तन को धर्म विरोधी और संविधान के विपरीत बताते हैं. वह कहते हैं कि सरकार को धर्माचार्यों एवं पुरोहितों के अधिकार अपने हाथ में लेने से बाज आना चाहिए. सरकार का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष होता है, उसे उसी तरह का आचरण करना चाहिए. उन्होंने निशंक सरकार को अर्द्धकुंभ के समय नारायण दत्त तिवारी द्वारा यात्रा आरंभ करने के निर्णय की याद दिलाते हुए कहा कि उस समय जनता के विरोध के चलते तिवारी को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा था. राज्य के संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति रह चुके जयराम संस्थाओं के अध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी का मानना है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि. निशंक सरकार का फ़ैसला धर्म-संस्कृति के साथ खिलवाड़ है. सरकार को प्रदेश एवं देश की संस्कृति से खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जा सकती. बद्रिकाश्रम पीठ के प्रख्यात संत श्रीधरानंद ब्रह्मचारी ने यात्रा को धर्म विरोधी बताया और कहा कि इससे धर्म के सत्य तत्व की हानि होगी. इस यात्रा में भाग लेकर यात्री अपने को ठगा महसूस करेगा. जोशीमठ की जनता ने भी सड़क पर उतर कर यात्रा का विरोध किया और अफसरों का घेराव करके सरकार विरोधी नारे लगाए.

feedback@chauthiduniya.com

यमुनोत्री

पुराणों में यमुनोत्री का विशेष महत्व है. यह 3235 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है. चार धाम की यात्रा में सर्वप्रथम यमुनोत्री के ही दर्शन किए जाते हैं. यमुनोत्री में एक ओर यमुना जी की धारा और दूसरी ओर उष्ण जल के बहुत से स्रोत हैं. यहां का मुख्य मंदिर यमुना देवी को समर्पित है. वर्तमान मंदिर जयपुर की महारानी गुलेरिया ने 19वीं सदी में बनवाया था. एक बार विनाशकारी भूकंप से विध्वंस होने के बाद इसका पुनर्निर्माण 1919 में टिहरी नरेश महाराजा प्रताप शाह ने कराया. यमुनोत्री मंदिर में यमुना जी के साथ गंगा, यमराज एवं कृष्ण की प्रतिमाएं स्थापित हैं. यमुनोत्री दर्शन के लिए सड़क के रास्ते अंतिम पड़ाव हनुमान चट्टी से 13 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है.

गंगोत्री

3140 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय की गोद में बसा गंगोत्री हिंदुओं का पवित्र तीर्थ है. ऐसा माना गया है कि जिस शिला पर बैठकर राजा भागीरथ ने तपस्या की थी, उसी पर यह मंदिर बनाया गया था. उस प्राचीन मंदिर के स्थान पर आज भव्य मंदिर खड़ा है, जिसका निर्माण जयपुर के राजाओं द्वारा कराया गया था. यहां पतित पावनी गंगा की धारा का प्रवाह उत्तर दिशा की ओर मुड़ने के कारण इस स्थान का नाम गंगोत्री पड़ा.

केदारनाथ

बारह ज्योतिर्लिंगों में श्रेष्ठ केदार लिंग-केदार नाथ में साक्षात शिव निवास करते हैं. केदार उन अनगढ़ शिलाओं और शिखरों को भी कहते हैं, जिनमें भगवान शिव का निवास माना जाता है. संस्कृत में केदार शब्द का प्रयोग सेम या दलदली भूमि अथवा धन की रोपाई वाले खेत के लिए होता है. संभवतः केदार तीर्थ के कारण पड़ोस की भूमि केदार भूमि या केदार खंड कहलाई. संपूर्ण पापों का नाश करने वाली मोक्षदायिनी केदार भूमि के वर्णन से धर्मशास्त्र भरे पड़े हैं. शिव पुराण, पद्म पुराण, कर्म पुराण, स्कंद पुराण, वाराह पुराण, सौर पुराण, वामन पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण एवं लिंग पुराण आदि में केदार तीर्थ को मनुष्य के संपूर्ण पापों का नाशक और मोक्षदायक बताया गया है.

बद्रीनाथ

बद्रीनाथ धाम को भारत के चार पवित्र धामों में सबसे प्राचीन बताया गया है. शास्त्रों में सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग आदि चार युगों की जो महिमा कही गई है, उसके अनुसार उत्तर में सतयुग का बद्रीनाथ, दक्षिण में त्रेता का रामेश्वरम, पश्चिम में द्वापर की द्वारिका और पश्चिम में कलयुग का पावन धाम जगन्नाथ धाम है. उत्तर में हिमालय में गंधमादन पर्वत पर स्थित पावन तीर्थ बद्रीनाथ को विभिन्न युगों में मुक्तिप्रदा एवं बद्री विशाल आदि नामों से जाना गया. मंदिर निर्माण के संदर्भ में एक पौराणिक उल्लेख यह भी है कि ब्रह्मा आदि देवताओं ने सर्वप्रथम भगवान विश्वकर्मा से इस मंदिर का निर्माण कराया था. बाद में राजा पुरुरवा ने इसका पुनर्निर्माण कराया.

मेरी दुनिया.... रामदेव और राजनीति की क्रिकेट! ...धीर

नवाबों के दौर में पतंगबाज़ी के पेच लड़ाने के लिए बड़े-बड़े उस्ताद हुआ करते थे. आज लखनऊ और बरेली में परंपरागत रूप से मांझा बनाने वाले कारीगर दयनीय हालत में पहुंच गए हैं.

पतंगबाज़ी पर आधुनिकता की मार

सुरेंद्र अग्निहोत्री

उड़ी-उड़ी रे पतंग, उड़ी-उड़ी रे...जैसे गीत भले ही सदाबहार हों, लेकिन अब नवाबों की नगरी लखनऊ में पतंगबाज़ी की परंपरा लगभग ख़त्म होती जा रही है. पिछले दिनों यहां पतंग के मांझे से एक व्यक्ति की आंख चोटिल होने से पतंगबाज़ी के प्रति लोगों में भय व्याप्त हो गया है. रंग-बिरंगी पतंगें हमें आकर्षित करती हैं और हमारे अंदर प्रतिस्पर्धा का भाव पैदा करती हैं, लेकिन हर हालत में जीत की चाहत ने इस पाक हुनर को रक्तरंजित कर दिया है. मंझा के रूप में तार के प्रयोग ने पतंगबाज़ी को कलंकित कर दिया है. प्रति वर्ष लखनऊ महोत्सव के अंतर्गत पतंगबाज़ी कला प्रतियोगिता का आयोजन करके जहां प्रशासन अवध की इस प्राचीन परंपरा को जीवित रखने के लिए वचनबद्ध है तो दूसरी ओर स्वार्थी तत्वों के कारण पतंगबाज़ी बदनाम हो रही है. रक्षाबंधन के बाद पतंगबाज़ी का दौर क्या शुरू हुआ, मानों बिजली विभाग की शामत आ गई. अपनी पतंग कटने न पाए, इसलिए धड़ल्ले से डोर की जगह लोहे के महीन तारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो बिजली विभाग और उपभोक्ताओं के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं. पतंगबाज़ी का मौसम आते ही लोहे के महीन तार बेचने वाले सक्रिय हो गए हैं, जो ऐसे तार 10 रुपये प्रति 100 ग्राम की दर से बेच रहे हैं. पतंगबाज़ इसका इस्तेमाल करके दूसरों की पतंगों के साथ बिजली के तार भी काट रहे हैं. यह हाल तब है, जबकि तीन महीने पहले ही पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नवनीत सहगल ने ज़िलाधिकारी एवं डीआईजी को उन दुकानों की सूची सौंपी थी, जहां से ऐसे तार बेचे जा रहे हैं, लेकिन ज़िला प्रशासन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया.

बक़ौल डीआईजी, कुछ महीने पहले एक बैठक में इस तरह की बात हुई थी. इसके बाद पुराने शहर के चौक, वजीरगंज, अमीनाबाद एवं कैसरबाग सहित कई थानों को निर्देश भी जारी किए गए थे. पुलिस के इस उदासीन रवैये का ही नतीजा है कि शहर के लगभग सभी इलाक़ों में पतंग की दुकानों से ऐसे तार धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं. तार बंधी पतंगें सिर्फ़ बिजली संकट का कारण नहीं बन रही हैं, बल्कि उनसे दुर्घटना की भी आशंका बनी रहती है. वर्ष 2003 में कैसरबाग इलाक़े में विद्युत लाइन में फंसी पतंग से नीचे लटकते लोहे के महीन तार की चपेट में आकर अमीनाबाद इंटर कॉलेज के युवा शिक्षक संजीव पांडेय की मौत हो गई थी. बीते साल 25 दिसंबर को इमामबाड़ा और हनुमान सेतु पुल के पास दोपहिया वाहन से जा रहे मनकेश्वर पांडेय एवं अली जफर को भी पतंग की डोर ने गंभीर रूप से घायल कर दिया था. कभी बच्चों और युवाओं को खासी प्रिय रही पतंगबाज़ी पर उपभोक्तावादी संस्कृति की ज़बरदस्त मार पड़ी है. अब कुछ ख़ास मौक़े पर ही बच्चे, किशोर एवं इक्का-दुक्का युवक पतंगबाज़ी का लुत्फ़ उठाते हैं. लखनऊ में पतंग बनाने और मांझा सूतने का कारोबार लगभग ख़त्म होने की राह पर है. पतंग प्रतियोगिताएं तो बीते जमाने की बात हो गई हैं. पहले पतंगबाज आपस में एक-दूसरे से पेच लड़ाने की बाज़ी लगाते थे और इसके लिए बड़ी-बड़ी पतंगें, जो सही तरह से उठ सकें, ख़ुद ही तैयार करते थे. फिर इन बड़ी पतंगों को मांझे के बजाय साधारण डोर के सहारे उड़ाकर देखा जाता था.

पतंगबाज़ अपनी पतंगों के काप और टढ़े ख़ुद तैयार करते थे और उनकी पतंगों की पहचान चील, डंडा, अद्धा, गिलास एवं चांद-तारा आदि निशानों से आसमान में ही होती थी. पतंगबाज एक-दूसरे की पतंग काटने के लिए जंगलों में जाकर ख़ुद मांझा सूतते थे और विशेष लच्छी तैयार करते थे. मांझा सूतने के लिए वे सरेस, नीला थोथा, महीन कांच, लोहे का बुरादा, रंग एवं बिल्ली-बंदर का मल आदि का इस्तेमाल करते थे, ताकि हजारा नलकी की डोर पर बारीक धार रखी जा सके. दशहरा, रक्षाबंधन, 15 अगस्त, 26 जनवरी एवं मकर संक्रांति जैसे अवसरों पर पतंगबाज़ अपने हुनर का प्रदर्शन करते थे. पेच लड़ाने के दौरान चरखी पकड़ने के लिए भी बहुत सतर्क और होशियार लोग ही रखे जाते थे, जो पेच के दौरान चरखी को इस तरह पकड़ सकें कि रील कहीं अटके नहीं. लेकिन अब पतंगबाज़ी बीते ज़माने की बात हो गई है और बच्चों में ही सिमट कर रह गई है. बच्चों ने अब पन्नी की पतंग बना

ली है. अच्छन मियां कहते हैं, पतंग जैसी नाज़ुक कला भागमभाग की ज़िंदगी में तन्हा होकर ख़त्म हो रही है. बच्चों पर पढ़ाई का बोझ है और वैसे भी वीडियो गेम, टीवी के आगे सब कुछ फीका है. अब वह जमाना गया, न वैसे शौक़ीन रहे और न ख़रीददार. त्योहारों पर बच्चे छोटी पतंगें और कंपनी का बना मांझा ख़रीद कर अपना शौक़ पूरा कर लेते हैं.

नवाबों के दौर में पतंगबाज़ी के पेच लड़ाने के लिए बड़े-बड़े उस्ताद हुआ करते थे. आज लखनऊ और बरेली में परंपरागत रूप से मांझा बनाने वाले कारीगर दयनीय हालत में पहुंच गए हैं. बाज़ार में चीनी पतंगें और मांझा आ जाने के कारण वे बामुश्किल बीस-तीस रुपये रोज़ कमा पा रहे हैं. आसमान में लहराती पतंगें बनाने वाले हुनरमंद कारीगरों की मेहनत को कोई पूछने वाला नहीं है. तंग गलियों और छोटे-छोटे घरों में ज़हरीली लेई और बॉस के बुरादे के बीच लगातार काम करते पतंगसाज टीबी जैसी घातक बीमारी के शिकार होकर मौत के मुंह में जाने के लिए विवश हैं. मौलवीगंज निवासी तारिक मियां का परिवार पिछली तीन पीढ़ियों से पतंग के कारोबार से जुड़ा हुआ है. अब तारिक मियां को भी लगता है कि पतंग के दिन लदने वाले हैं. कभी जनवरी का महीना आते ही पतंगबाज़ सक्रिय हो जाते थे और पतंगों की क़ीमत भी अच्छी मिलती थी, लेकिन अब न पतंग उड़ाने वाले दिखते हैं और न पतंगसाज़. गुजरात में अपना हुनर दिखा चुके झांसी के पतंगबाज़ नीरज कहते हैं कि जिस तरह चीन और जापान में पतंगबाज़ी की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताएं होती हैं, वैसी हमारे यहां भी होनी चाहिए.

उत्तर भारत में पतंगबाज़ी का इतिहास वर्षों पुराना है, लेकिन गुजरात और विशेष रूप से अहमदाबाद इस लिहाज़ से देश भर में अव्वल है. गुजरात में तो प्रति वर्ष अंतरराष्ट्रीय पतंग उत्सव आयोजित किया जाता है. बताते हैं कि पतंग का आविष्कार लगभग 2800 वर्ष पूर्व चीन में हुआ था, जहां पतंग बनाने के लिए अच्छे काग़ज़, रेशम के कपड़े, धागे और हल्के-मज़बूत बांस आसानी से मिल जाते थे. दुनिया की सबसे बड़ी पतंग ब्रिस्टल इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल इंग्लैंड में उड़ाई गई, जिसकी लंबाई 210 फुट थी. इसे न्यूज़ीलैंड के पीटर लेन ने डिज़ाइन किया था. यह पतंग केवल 22 मिनट और 57 सेकेंड तक हवा में उड़ सकी.

सरकार का उपेक्षापूर्ण रवैया

उत्तर प्रदेश में पतंग बनाने के धंधे में लगे अधिकतर कामगार या तो मुसलमान हैं या दलित. इन दोनों ही वर्गों की स्थिति बहुत ख़राब है. पुराने लखनऊ की तंग गलियों में अंधेरे और सीलन भरे कमरों में महिलाएं रात-दिन पतंगें बनाने में लगी रहती हैं, लेकिन उनकी मज़दूरी इतनी कम है कि विश्वास ही नहीं होता. वे पतंगों का मौसम आने के छह महीने पूर्व ही इस काम में जुट जाती हैं. इन महिलाओं में युवतियां ज़्यादा हैं, जो अपने लिए ईद में नए कपड़े नहीं सिलवातीं, बल्कि अपनी कमाई के पैसे इसलिए बचाती हैं, ताकि वे उन्हें अपने विवाह में ख़र्च कर सकें. आश्चर्य की बात यह है कि एक हज़ार पतंगें बनाने पर उन्हें बतौर मज़दूरी केवल 20-30, बहुत हुआ तो 40 रुपये ही मिलते हैं. मकर संक्रांति के पर्व के एक-दो महीने पूर्व मज़दूरी में कहने भर को इज़ाफ़ा होता है, लेकिन सीजन ख़त्म होते ही हाल और भी ख़राब हो जाता है. इस व्यवसाय से जुड़ा शख्स दलित हो या मुस्लिम अथवा किसी अन्य जाति-समुदाय का, हाल कमोबेश सभी का यही है. टूटी-फूटी झोपड़ियों में रहने वाले इन फटेहाल लोगों की ओर किसी का भी ध्यान नहीं है. गुजरात और राजस्थान जैसे प्रदेशों में, जहां पतंगबाज़ी का बहुत पुराना रिवाज है, सरकार ने इस व्यवसाय को ज़िंदा रखने और इसके फलने-फूलने के लिए कई योजनाएं लागू कर रखी हैं, जिनकी वजह से आज इन राज्यों में पतंग व्यवसाय बहुत अच्छी हालत में है. लेकिन उत्तर प्रदेश में जहां मायावती का शासन है, वहां इस व्यवसाय और इससे जुड़ी ग़रीब जनता के लिए कुछ भी नहीं किया गया है. यानी उत्तर प्रदेश में इन ग़रीब लोगों की पतंग कट गई है.

feedback@chauthiduniya.com

दलित उद्यमिता का संकल्प

आशीष कुमार अंशु

सांगली से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर कावधे महान्का ताल्लुका में देवानंद लोंधे का हिंगन गांव है. वह लंबे समय तक अपने गांव से बाहर रहे. कई वर्षों तक देश से भी बाहर रहे. अच्छी नौकरी थी, लेकिन उसके बावजूद दिल में तड़प हमेशा अपने गांव लौटने की बनी रही. अपने गांव के बेरोज़गार परिवारों को रोज़गार कैसे मुहैया कराया जाए, वह हमेशा यही सोचते रहे. जब परिवार में पैसा आता है तो उसका जीवन स्तर सुधरता है, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती है. जिस गांव में बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, उस गांव की उन्नति को कोई रोक नहीं सकता.

यह लोंधे की कल्पना थी, उस समय, जब वह विद्यार्थी जीवन में थे. समय बीता और महज़ दो साल पहले इसी गांव में लोंधे ने अपनी दस्ताने की एक यूनिट लगाई. जहां उनकी दस्ताने की यूनिट है, पहले वहां कपड़े का एक कारखाना हुआ करता था, जो बाद में बंद हो गया. इस पचास हज़ार स्क्वायर फीट ज़मीन को देवानंद ने ख़रीद तो लिया, लेकिन उस समय तक वह यह तय नहीं कर पाए थे कि गांव में ली गई इस ज़मीन को कैसे इस्तेमाल करना है. कपड़े का कारखाना बंद होने के बाद गांव की अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से प्रभावित हुई थी. इसलिए लोंधे ने ज़मीन लेने के साथ ही यह तय कर लिया कि वह कोई ऐसा काम करेंगे, जिसमें उन्हें मुनाफ़ा भले ही कम मिले, लेकिन उससे गांव के अधिक से अधिक लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए.

चूंकि देवानंद लोंधे एक दलित परिवार से संबंध रखते हैं, इसलिए उन्होंने अपने आसपास भेदभाव और ग़रीबी को क़रीब से देखा है. लोंधे के शब्दों में, दलितों के साथ होने वाले भेदभाव का एक ही हल है कि उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जाए. उनकी उपेक्षा दलित होने की वजह से कम ग़रीबी की वजह से अधिक होती है. लोंधे मानते हैं कि समाज में अब उनके साथ भेदभाव नहीं है. यदि कोई करने की सोचे तो उसे संयम के साथ सही जवाब देने में वह भी सक्षम हैं. अधिक से अधिक गांव वालों को अपने साथ जोड़ने की मंशा लेकर हिंगन गांव में पायोद इंडस्ट्रीज बनी. हाथों के लिए दस्ताने का काम शुरू हुआ. मशीनें चीन से लाई गईं. मशीनें लाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि उनसे कम से कम काम करना पड़े, अधिक से अधिक काम हाथों से हो. इस तरह गांव में एक साथ डेढ़ सौ लोगों के लिए रोज़गार की व्यवस्था पायोद इंडस्ट्रीज की वजह से हुई. इसमें सिर्फ़ पांच फ़ीसदी पुरुष रखे गए, बाक़ी सभी काम महिलाएं देखती हैं.

इसके पीछे भी लोंधे की दूरदर्शिता काम कर रही थी. उनके अनुसार, पुरुष का पैसा सिर्फ़ पुरुष के लिए होता है. उस पर मालिकाना हक पुरुष का होता है, लेकिन महिलाओं के हाथ में जो पैसा आता है, वह पूरे परिवार का होता है. पुरुष के हाथ के पैसे का अधिक भाग

देवानंद लोंधे एक दलित परिवार से संबंध रखते हैं, इसलिए उन्होंने अपने आसपास भेदभाव और ग़रीबी को क़रीब से देखा है. लोंधे के शब्दों में, दलितों के साथ होने वाले भेदभाव का एक ही हल है कि उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जाए. उनकी उपेक्षा दलित होने की वजह से कम ग़रीबी की वजह से अधिक होती है. लोंधे मानते हैं कि समाज में अब उनके साथ भेदभाव नहीं है.

खाने-पीने जैसी चीजों पर ख़र्च होता है, जबकि महिलाएं बच्चों की शिक्षा और उनके स्वास्थ्य की भी अधिक चिंता करती हैं. लोंधे द्वारा बनाए गए विशेष प्रकार के दस्तानों की सौ फ़ीसदी आपूर्ति विदेशों के लिए होती है. इन दस्तानों की मांग जापान एवं चीन में अधिक है. सौ फ़ीसदी निर्यात की वजह से उन्हें बैंक से ऋण लेने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. चूंकि उनके सारे ग्राहक विदेशों में थे और दस्ताने के लिए इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल भी वह बाहर से ही मंगाते हैं. इसी वजह से कोई भी बैंक शुरुआती दौर में उन्हें ऋण देने के लिए तैयार नहीं हुआ. इसके बावजूद उन्होंने अपनी लगन की बदौलत और साथियों की मदद से कंपनी का सालाना कारोबार अस्सी लाख रुपये तक पहुंचा दिया.

बात अगर लोंधे के जीवन की करें तो उन्होंने लंबे समय तक कुछ ग़ैर सरकारी संगठनों और एजेंसियों के साथ काम किया. सुनामी के समय जब स्थानीय लोग शहर छोड़कर भाग रहे थे तो उन्होंने अपना डेरा चेन्नई में जमाया. अफ़ग़ानिस्तान से जब लोग भाग रहे थे तो वह अफ़ग़ानिस्तान में रहे. कुल मिलाकर उन्होंने इन्हीं अनुभवों से विपरीत परिस्थितियों में जीने और मुस्कराने की कला सीखी है. पायोद में काम करने वाले हर शख्स को पता है कि यहां कोई बड़ा नहीं है और किसी का पद छोटा नहीं है. पायोद परिवार का सदस्य बनाने से पहले हर शख्स को यह घुट्टी घोलकर पिलाई जाती है. यहां सबको बराबरी का दर्जा हासिल है.

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

कलाम की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी का विरोध केवल उन्हीं वामपंथी दलों द्वारा किया गया, जिन पर हमेशा भाजपा एवं उसके सहयोगी संगठन मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करने के आरोप लगाते रहते हैं.

हर साल गोदामों में लाखों टन अनाज सड़ रहा होता है और उसी दौरान भूख से लोग मर रहे होते हैं. ऐसी हालत के लिए क्या व्यवस्था सीधे तौर पर क़ुसूरवार नहीं है?

चौथी दुनिया

वास्तविक बदलाव की ज़रूरत

मेघनाद देसाई

आखिरकार बजट पेश हो गया और बजट भाषण भी बिना किसी परेशानी के पूरा हो गया. जेपीसी की मांग मान ली गई और पीएसी भी अपनी तरफ़ से जांच करेगी. अंततः सीवीसी को भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बेआबरू होकर अपने कूचे से निकलना पड़ा. राजा और कलमाड़ी पर भी शिकंजा कस दिया गया, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी सब कुछ ठीक हो जाने का एहसास नहीं हो रहा है. बजट में कुछ छोटे-छोटे प्रस्तावों को छोड़कर ऐसा कुछ भी नहीं था, जो हमारी उम्मीदों पर खरा उतर सके. आयकर सीमा को एक लाख साठ हज़ार रुपये से बढ़ाकर एक लाख अस्सी हज़ार रुपये करके यह संदेश देने की कोशिश की गई कि शहरी और ग्रामीण मध्य वर्ग को और ज़्यादा अवसर देने की योजना यूपीए सरकार के एजेंडे में शामिल नहीं है. मध्य वर्ग महंगाई के बारे में शिकायत करता रहे. फिर भी सरकार का विश्वास है कि यूपीए-2 के दौरान मध्य वर्ग ने बहुत विकास किया है और यह महंगाई से निपटने में सक्षम है. महंगाई यूपीए के लिए कोई समस्या नहीं है, जिसका समाधान निकाला जाना ज़रूरी है. यह तो यूपीए सरकार के लिए एक उपलब्धि है, क्योंकि सरकार का मानना है कि मनरेगा की वजह से ग़रीबों की आमदनी बढ़ी है और अब वे पहले से ज़्यादा खा रहे हैं तथा महंगाई की एक वजह यह भी है. हालांकि यह एक बहुत बड़ी ग़लती हो सकती है, एक बहुत ग़लत निर्णय भी.

पांच राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और जनता के फ़ैसले के बारे में हमें 13 मई तक ही पता चल सकेगा. कांग्रेस केवल असम में सत्ता में है और बड़ी पार्टी भी है. तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में उसकी स्थिति कमज़ोर है. भारतीय मतदाता किसी भी सत्तासीन पार्टी को महंगाई के लिए माफ़ नहीं करते. मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार एआईएडीएमके जीतेगी. डीएमके-कांग्रेस गठबंधन हारने से है. हालांकि इनमें से किसी भी गठबंधन में कोई भी सिद्धांत दांव पर नहीं लगा हुआ है, सिवाय धर्म निरपेक्षता के. और यह भी तमिलनाडु में कोई विभाजनकारी लकीर नहीं है, जैसा कि अम्मा और केलेनगार के बीच है. पश्चिम बंगाल में भी हिसाब से कांटे की टक्कर है. बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वहां 35 सालों तक सत्ता में रहने के बाद सीपीएम हारने जा रही है, लेकिन महंगाई और माओवादियों के साथ रिश्ते जैसे मुद्दे ममता बनर्जी को नुक़सान पहुंचा सकते हैं.

यह भी स्पष्ट नहीं है कि उनके पास पश्चिम बंगाल के लिए कोई वैकल्पिक राजनीतिक पैकेज है या नहीं. हर कोई जो यह कह रहा है कि ममता जीतेंगी, वह साथ में यह बात भी जोड़ रहा है कि पश्चिम बंगाल की स्थिति फिर भी ख़राब ही रहेगी. कांग्रेस को लेकर सबसे कठिन निर्णय यही हो सकता है कि तब क्या होगा, यदि इसे संतुलन बनाने लायक सीटें मिल जाएं. प्रणव मुखर्जी ने इशारा किया है कि उनके पास बैंकिंग और इंश्योरेंस से संबंधित कई विधेयक हैं, जो पास कराने हैं और उसके लिए उन्हें बाहर से भी समर्थन चाहिए होगा. इसका अर्थ है कि भाजपा-राजग का ही समर्थन नहीं, बल्कि लेफ्ट के भी समर्थन की ज़रूरत पड़ेगी. यहां एक बार फिर से इस बात के संकेत दिख रहे हैं कि दीदी का साथ छोड़कर वामपंथियों के साथ अपने पुराने संबंध जोड़ लिए जाएं. हालांकि प्रधानमंत्री इस संदर्भ में उस क़दम के आधार पर असहमत हो सकते हैं, जो उन्होंने संसद में न्यूक्लियर डील के समय वामपंथियों ने उठाया था, लेकिन कांग्रेस के भीतर ही कई ऐसे लोग हैं, जो अपने कामरेड दोस्तों को भूल नहीं पा रहे हैं.

बजट के माध्यम से सरकार भविष्य में उदारवादी सुधार करेगी या लोकवादी मुद्दा अपनाने जा रही है, यह संदेश स्पष्ट नहीं हुआ. इससे मुझे लगता है, कांग्रेस इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति में है कि यह भविष्य में किस दिशा की ओर आगे बढ़े. प्रधानमंत्री को उनके सहकर्मियों ने अकेला छोड़ दिया है. ख़ासकर उनकी प्रेस कांफ्रेंस के पहले और बाद में कोई भी उनकी मदद के लिए आगे आता नहीं दिख रहा है. अपनी मजबूरी को लेकर उन्होंने जो स्वीकारोक्ति की, वह उनकी पार्टी और गठबंधन के साथियों के लिए किसी प्रहार से कम नहीं थी. इसरो मुद्दे पर जब राज्यसभा में प्रधानमंत्री और अरुण जेटली के बीच बहस हो रही थी, तब उनके वाक्यों में छुपे गुस्से को देखा जा सकता था. वहां मनमोहन सिंह का वह रूप नहीं था, जो अमूमन नहीं दिखता. उनके गुस्से का कुछ हिस्सा उस दिशा के लिए भी था, जहां उनके अपने लोग होते थे.

कैबिनेट में एक और फेरबदल का वादा किया जा चुका है. कैबिनेट थकी-मांदी और बूढ़ी नज़र आ रही है. कांग्रेस में प्रतिभाशाली और 40 के आसपास के युवक-युवतियों की अच्छी-ख़ासी संख्या है और आप यह जानते हैं कि ये कौन हैं. राहुल के सहयोगियों में भी ऐसी प्रतिभाएं हैं. अगर उन्हें कम अनुभव है, तो भी मौक़ा मिलना चाहिए, ताकि वे अपनी ग़लतियों से सीख सकें. क्या सचमुच कुछ वास्तविक बदलाव होगा?

feedback@chauthiduniya.com

तुष्टिकरण और राजधर्म के तर्क

निर्मल रानी

भारतीय राजनीति में तुष्टिकरण शब्द प्रायः राष्ट्रीय स्तर पर एक गर्म बहस का मुद्दा बनता दिखाई देता है. जहां देश के अन्य राजनीतिक दल भारतीय संविधान के अनुरूप अल्पसंख्यकों, दलितों एवं पिछड़ों के लिए आरक्षण अथवा सामाजिक, सामुदायिक और आर्थिक उत्थान के पक्ष में अपना मत व्यक्त करते रहते हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुस्लिम समुदाय के हित में उठाए जाने वाले किसी भी क़दम को मुस्लिम तुष्टिकरण हेतु उठाया जाने वाला क़दम कहकर संबोधित करती है. क्यों लगाए जाते हैं तुष्टिकरण के आरोप? क्या होता है तुष्टिकरण? क्यों की जाती है तुष्टिकरण की राजनीति?

पिछले लोकसभा चुनावों से पहले समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने मुसलमानों से इस बात के लिए क्षमा मांगी कि उन्होंने ग़लती से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह से दोस्ताना बढ़ाने की कोशिश की थी. कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री रहते हुए 6 दिसंबर, 1992 के बाबरी मस्जिद विध्वंस में अहम भूमिका अदा की थी. इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुस्लिम मतदाता मुलायम सिंह के साथ हो गए थे, क्योंकि 1990 में 1992 जैसी ही परिस्थितियों में मुलायम सिंह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों एवं संविधान की रक्षा का बख़ूबी निर्वहन करते हुए अतिवादी भीड़ को इसी विवादित स्थल के समीप फटकने तक नहीं दिया था. उसी समय से मुस्लिम समुदाय मुलायम सिंह को अपने नेता के रूप में देखने लगा था. 1992 की घटना से कांग्रेस से भी मुसलमानों का विश्वास उठ गया था.

लगभग दो दशक की इस उतार-चढ़ाव भरी राजनीति के बाद पिछले संसदीय चुनावों में मुलायम सिंह एवं कल्याण सिंह ने आपस में गलबहियां कर ली थीं. यह बात मुस्लिम समाज को नागवार गुज़री और इसका ख़ामियाज़ा मुलायम सिंह को भुगतना पड़ा. इसी कारण मुलायम सिंह ने मुसलमानों से माफ़ी मांगने जैसा राजनीतिक ब्रह्मास्त्र एक बार फिर चलाया, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी थी. मुलायम सिंह के इस माफ़ीनामे पर उस समय उनके राजनीतिक विरोधियों द्वारा कहा गया कि वह तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं. भारतीय राजनीति में अक्सर राजनीतिक दल किसी न किसी पर तुष्टिकरण का आरोप लगाते रहते हैं. राष्ट्रीय स्तर पर यह आरोप भारतीय जनता पार्टी एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा कांग्रेस, वामपंथी दलों एवं धर्मनिरपेक्षता पर विश्वास करने वाले अन्य राजनीतिक संगठनों पर मुस्लिम समाज को लेकर लगाया जाता है. इनका आरोप है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करने वाले अधिकांश राजनीतिक संगठन मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं. दूसरी ओर धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक संगठनों का मानना है कि उनके द्वारा उठाए गए ऐसे क़दम, जिससे अल्पसंख्यकों या मुस्लिम समाज का कल्याण होता हो, वे पूरे देश की अर्थव्यवस्था एवं विकास के लिए लाभकारी होते हैं. सवाल यह है कि देश में क्या कोई ऐसा राजनीतिक संगठन भी है, जो मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने या किसी धर्म, जाति अथवा वर्ग विशेष के मतों को प्राप्त करने के लिए तुष्टिकरण की राजनीति न करता हो? भाजपा द्वारा ही गुजरात दंगों के ठीक बाद राष्ट्रपति पद हेतु डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के नाम का प्रस्ताव किया गया था. भाजपा इस प्रस्ताव द्वारा अपना कथित धर्मनिरपेक्ष चेहरा दुनिया को दिखाना चाहती थी, लेकिन यदि यह प्रस्ताव कांग्रेस, वामपंथी दलों, समाजवादी पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल द्वारा पेश किया जाता तो भाजपा या उसके सहयोगी संगठन यह कहते देर नहीं लगाते कि यह मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति है.

कलाम की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी का विरोध केवल उन्हीं वामपंथी दलों द्वारा किया गया, जिन पर हमेशा भाजपा एवं उसके सहयोगी संगठन मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करने के आरोप लगाते रहते हैं. क्या यह नहीं कहा जा सकता कि भाजपा द्वारा कलाम का नाम राष्ट्रपति पद के लिए प्रस्तावित करना केवल मुसलमानों के तुष्टिकरण के लिए उठाया गया क़दम था? भाजपा का यह भी दावा है कि उसने केंद्र में सत्तारूढ़ रहने के दौरान मुस्लिम अल्पसंख्यकों के हितों के लिए कई महत्वपूर्ण क़दम उठाए. भारतीय मुस्लिम राजनीति में अपनी अहम पहचान रखने वाले आरिफ़ मोहम्मद ख़ां एवं नजमा हेपतुल्ला जैसे नेताओं को भाजपा द्वारा अपनी पार्टी में आमंत्रित किया गया था. भाजपा ने ही अपने शासनकाल में हज यात्रियों के लिए कई स्थानों से विशेष विमानों की व्यवस्था की थी.

दो दशकों से लखनऊ में बंद पड़ा ऐतिहासिक मोहर्रम का जुलूस राज्य की भाजपा सरकार ने ही पुनः निकलवाना शुरू किया था. भाजपा द्वारा इस्लामी विद्वान मौलाना वहीदुद्दीन को न सिर्फ़ पद्मश्री से नवाज़ा गया, बल्कि उन्हें वोट मांगने के लिए भी प्रयोग में लाया गया.

दो दशकों से लखनऊ में बंद पड़ा ऐतिहासिक मोहर्रम का जुलूस राज्य की भाजपा सरकार ने ही पुनः निकलवाना शुरू किया था. भाजपा द्वारा इस्लामी विद्वान मौलाना वहीदुद्दीन को न सिर्फ़ पद्मश्री से नवाज़ा गया, बल्कि उन्हें वोट मांगने के लिए भी प्रयोग में लाया गया. बशीर बद्र जैसे मशहूर शायर को भाजपा द्वारा मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी का सचिव बनाया गया. उसी दौरान अटल हिमायती कमेटी नामक एक मुस्लिम ग्रुप तैयार किया गया और उसे मुस्लिम क्षेत्रों में भेजकर पार्टी हेतु वोट मांगे गए. वाजपेयी एवं आडवाणी जैसे वरिष्ठ पार्टी नेताओं को रोज़ा इफ्तार पार्टियों का आयोजन करते और उनमें शरीक होते भी देखा गया. पार्टी ने भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा आख़िर किस उद्देश्य से गठित कर रखा है? बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का बार-बार यह बयान देना कि राज्य में मुस्लिम हितों को ध्यान में रखकर राजग सरकार ने लालू-राबड़ी सरकारों से अधिक कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, का क्या अर्थ है? आख़िर भाजपा द्वारा मुस्लिमों के प्रति दिखाई देने वाले इस प्रेम, हमदर्दी या दरियादिली को क्या नाम दिया जाए? तुष्टिकरण, राजधर्म या धर्मनिरपेक्षता?

वास्तव में यह तो नेताओं की अपनी स्वार्थपूर्ण मंशा पर निर्भर है कि वे कब किसी समाज के पक्षधर बन बैठें और कब किसके किन क़दमों को तुष्टिकरण के क़दम बताने लग जाएं. दरअसल यह सारा खेल वोट इकट्ठे करने का है. प्रत्येक राजनीतिक दल किसी न किसी वर्ग विशेष के तुष्टिकरण में लगा हुआ है. अब चाहे इसे देश एवं समाज के हितों के चश्मे से देखा जाए अथवा समाज में वैमनस्य फैलाने वाले शब्द तुष्टिकरण के चश्मे से.

m_awdhesh@chauthiduniya.com

जब तोप मुक़ाबिल हो

देश का राजनीतिक ढांचा बचाने की ज़रूरत

संतोष भारतीय

सारे देश में अपने अपहरण से मशहूर हुए देश के प्रथम आईएएस अधिकारी विनील कृष्णा ने बयान दिया है कि अगर विकास का ढांचा नहीं सुधारा गया और लोगों तक विकास का नाम नहीं पहुंचा तो वह दिन दूर नहीं, जब अधिकारी या सत्ता में बैठे लोग, जनता के गुस्से का शिकार होंगे. उनका यह बयान उस वास्तविकता की ओर इशारा करता है, जिसे सत्ता में बैठे लोग नहीं समझ पा रहे हैं. जब कृष्णा छूटकर आए, उस समय उड़ीसा सरकार ने हवा फैलाई कि कृष्णा नक्सलवादियों से मिले हुए हैं और उनका अपहरण दोनों का मिला हुआ खेल था. पर इस चीज को कोई मानने के लिए तैयार नहीं होता. कृष्णा उन अधिकारियों में थे, जो मोटरसाइकिल पर गांव का दौरा करते थे, क्योंकि वहां जीप जाने के लिए सही रास्ता नहीं था और वह नक्सलवादियों का आसान निशाना बन गए. पर हमारा उद्देश्य इस घटना को और विस्तार से बताना नहीं है, बल्कि हम वह कहना चाहते हैं, जो कृष्णा ने कहा कि अगर व्यवस्था नहीं सुधरी तो इस मुल्क में सत्ताधीशों के सामने मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं. जो आज कृष्णा ने कहा, वही बंगाल के बुद्धिजीवियों ने महाश्वेता देवी के नेतृत्व में तीन साल पहले कहा था. और जब उन्होंने यह बात कही, तब बंगाल की मार्क्सवादी सरकार इन बुद्धिजीवियों के पीछे पड़ गई. इन्हें गिरफ्तारी का भय दिखाने लगी. उसका कहना था कि ये लोग इस तरह का बयान देकर नक्सलवादियों को बढ़ावा दे रहे हैं, उनका मन बढ़ाते हैं और इसका मतलब है कि परोक्ष रूप से ये नक्सलवादियों के साथ हैं. यही भाषा छत्तीसगढ़ में रमन सिंह बोल रहे हैं. उनका कहना है कि जो भी नक्सलवादियों के समर्थन में बात करेगा, वह उनसे जुड़ा हुआ माना जाएगा.

राजनेता अक्ल की बातें अक्सर करते हैं, अक्सर नहीं करते. अब इन दोनों परस्पर विरोधी विचारधाराओं वाली पार्टियों के नज़रिए में कहां साम्यता है, कहां नहीं, यह आप तय करें. पर मुझे लगता है कि ये दोनों आम आदमियों को लेकर बिल्कुल एक जगह खड़ी हैं. पश्चिम बंगाल को ले लें. वहां चुनाव होने वाले हैं. वहां 35 साल से सरकार की रीढ़ का काम करने वाली जमात, जिसका नाम मुसलमान है, वह अब 60 से 70 प्रतिशत सीपीएम से अलग हो गई है, क्योंकि जितने वायदे मुसलमानों से किए गए थे, वे आज तक पूरे नहीं हुए. सीपीएम ने मुसलमानों को मज़दूर के रूप में नहीं देखा, सर्वहारा वर्ग के रूप में नहीं देखा और आम जनता के एक शक्तिशाली वर्ग के रूप में भी नहीं देखा. इसीलिए इतने साल आजादी के बीतने के बाद या 35 साल सीपीएम के शासन के बीतने के बाद जितने वायदे उन्होंने मुसलमानों से किए, उनमें से दस प्रतिशत भी आज तक पूरे नहीं किए. इसका गुस्सा बंगाल के मुसलमानों में है. साफ तौर पर यह गुस्सा देखा जा सकता है. इस समय बंगाल के मुसलमानों का कहना है कि सीपीएम को इस बार हारना चाहिए, क्योंकि अगर सीपीएम नहीं हारी तो वह सबक नहीं लेगी और इस बार अगर जीत गई तो बंगाल के मुसलमानों को कुछ नहीं मिलने वाला. बंगाल में मुसलमानों की संख्या 20 प्रतिशत से ज़्यादा है, कुछ लोगों का कहना है कि 24 प्रतिशत है. मान लें कि उन्नीस-बीस प्रतिशत है और यह बहुत बड़ा वोट होता है. पर दुर्भाग्य यह है कि बंगाल या असम में मुसलमान एकजुट नहीं हैं. एकजुट होना ताकत की सांप्रदायिकता है, लेकिन वह चीज अल्पसंख्यकों पर लागू नहीं होती, क्योंकि वे अगर एकजुट नहीं होते तो उन्हें उनकी रोजी-रोटी, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं इन क्षेत्रों में मिलने वाली नहीं थीं. मुसलमानों के बीच यह बड़ी विडंबना है कि वे आपस में अपने हितों को लेकर न तो दिमाग से साथ हैं, न वे एक साथ मिलकर एक्शन करना चाहते हैं, जिससे उनके वोटों से सत्ता में गिराया हुआ दल उनके लिए कुछ कर सके. होता यह है कि ऐन मौके पर मुसलमानों के वोटों का सौदा करने वाले खड़े हो जाते हैं. अभी बंगाल में खड़े हो रहे हैं और विभिन्न पार्टियों से सहायता ले रहे हैं मुसलमानों से वोट दिलवाने के नाम पर. नतीजे के तौर पर जब जीत कर वह पार्टी आती है तो वह फिर उनकी बात नहीं सुनती. कहती है कि हमने तो कीमत दे दी है आपको इसकी.

बंगाल की एक और चीज, एक नया तत्व, जमाते इस्लामी बंगाल में चुनाव लड़ने जा रही है. मैं कुछ दिनों पहले कोलकाता में था तो मैंने कोशिश की कि वहां के मुसलमानों से जानूं कि जमाते इस्लामी को कितने वोट मिलेंगे, उसका भविष्य क्या होगा चुनाव में. अभी हम और आप आपस में बात कर रहे हैं. बंगाल में जमाते इस्लामी को वोट देने का उत्साह मुसलमानों में नहीं दिखाई दे रहा है. हो सकता है कि जमाते इस्लामी को वोट मिल जाएं, हो सकता है न भी मिलें. अगर आज की स्थिति को देखें तो हमें जमाते इस्लामी को वोट मिलते नहीं दिखते. बल्कि उसकी वजह से कांग्रेस और ममता बनर्जी का स्कोप कहीं न कहीं थोड़ा सा कम होगा. बंगाल में दूसरी स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है. वह बंगाल में हर सीट पर चुनाव लड़ रही है, जबकि उसके पास इतना भी जनाधार नहीं है कि वह हर सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा कर सके. पर वह चुनाव लड़ रही है तो उम्मीदवार कहां से आएंगे उसके पास? जैसा कि मुस्लिम नेताओं ने कहा है कि भाजपा के पास उम्मीदवार मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से आएंगे. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का यह इंटरेस्ट है कि भाजपा जितनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी, ममता बनर्जी और कांग्रेस गठबंधन के जीतने के अवसर उतने ही कमजोर होंगे. अगर हम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की बात पर भरोसा न करें तो भी भाजपा हर सीट पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी. ऐसा करके वह अपनी पार्टी बनाने की बात भले ही करे, लेकिन उसकी पार्टी कितनी बनेगी, यह पता नहीं, पर वह कांग्रेस और ममता बनर्जी के भविष्य पर थोड़ी सी धुंध जरूर खड़ी कर देगी.

सीपीएम ने मुसलमानों को मज़दूर के रूप में नहीं देखा, सर्वहारा वर्ग के रूप में नहीं देखा और आम जनता के एक शक्तिशाली वर्ग के रूप में भी नहीं देखा. इसीलिए इतने साल आजादी के बीतने के बाद या 35 साल सीपीएम के शासन के बीतने के बाद जितने वायदे उन्होंने मुसलमानों से किए, उनमें से दस प्रतिशत भी आज तक पूरे नहीं किए. इसका गुस्सा बंगाल के मुसलमानों में है. साफ तौर पर यह गुस्सा देखा जा सकता है. इस समय बंगाल के मुसलमानों का कहना है कि सीपीएम को इस बार हारना चाहिए, क्योंकि अगर सीपीएम नहीं हारी तो वह सबक नहीं लेगी और इस बार अगर जीत गई तो बंगाल के मुसलमानों को कुछ नहीं मिलने वाला.

अब ये जो चुनाव हो रहे हैं, खासकर बिहार के बाद, ये बहुत साफ बताते हैं कि अगर हमने आम लोगों के हितों की चिंता नहीं की और उनके दुःख-दर्द को नहीं समझा, अगर अमेरिकी मॉडल पर चलते रहे, अब मैं मार्क्सवादी भाषा में उसे साम्राज्यवादी मॉडल कहूं या न कहूं, कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर हम उस मॉडल पर चलते रहे, जिसमें वे शोषक हैं, हम शोषित हैं. वे कमाने वाले, हमको दया करके खिलाने वाले हैं, तो अब निश्चित मान लें कि इस मुल्क में ऐसा बवंडर खड़ा होगा, जो इसकी पूरी राजनीति को निगल जाएगा. यह बवंडर न खड़ा हो और चुनाव में लोग सही ढंग से फैसला करें, इसके लिए ज़रूरी है कि सारे दल बंगाल के मुसलमानों, दरिद्रों और पिछड़ों के बारे में अपनी राय स्पष्ट करें.

बंगाली मानसिकता एग्रेसिव मानसिकता है. वे किसी भी चीज़ में गहरे घुसकर विरोध करते हैं, प्रतिरोध करते हैं. यह विरोध और प्रतिरोध वैचारिक भी होता है, एक्शन में भी होता है. वे अगर राजनीतिक सिस्टम के ख़िलाफ़ विद्रोह करते नज़र आएं और अगर ऐसे लोग जीत भी जाएं तो मानना चाहिए कि जनता का यह फैसला गलत नहीं है, बल्कि उसके गुस्से का फैसला है, जो वह राजनीतिक दलों को दिखाना चाहती है. आज ममता बनर्जी लोगों की नजरों में मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनसे मुसलमानों या लोगों का रिश्ता कैसे बनेगा, यह सवाल बंगाल में तैर रहा है. इस सवाल का जवाब खुद ममता को तलाशना पड़ेगा कि वह जनता से कितना मिलती हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि जब वह अपने एमएलए या एमपी से नहीं मिलतीं तो हम लोगों से कैसे मिलेंगी? इसका जवाब किसी को नहीं, बल्कि ममता को खुद देना है. दूसरे, अपनी पार्टी में ममता बनर्जी अकेली नेता हैं, दूसरा कोई नेता है नहीं. न कोई मुस्लिम फेस है, न कोई दलितों का फेस और न कोई पिछड़ों का फेस. वहां पर दलित हैं तो ममता, मुसलमान हैं तो ममता, पिछड़े हैं तो ममता. इस स्थिति से स्थानीय नेतृत्व नहीं हो पाता. स्थानीय नेतृत्व बनाएं और उन सवालों के जवाब तलाशें, जो उड़ीसा के जिलाधीश रहे और अब जिन्हें देश का प्रथम अगुवा आईएएस कहा जा सकता है, ने उठाए हैं. उन सवालों के जवाब अगर तलाशने की कोशिश नहीं होगी तो देश के सामने मुश्किल खड़ी हो सकती है. ये सवाल हमें महात्मा गांधी की एक सूक्ति याद दिलाते हैं, जिसे सरकार भूल गई है, बाहर की कंपनियां तो बिल्कुल भूल गई हैं, जिन्हें मल्टीनेशनल कहते हैं. गांधी जी ने कहा था कि जब भी आप कोई चीज़ तय करें तो सबसे पहले यह देखें कि जो आपकी नज़र में सबसे कमज़ोर आदमी है, उसे इस चीज़ से फ़ायदा होने वाला है या नहीं, ख़ासकर आर्थिक नीति से. अगर उसे फ़ायदा नहीं होने वाला है तो यह बेकार है. अगर उससे फ़ायदा होने वाला है तो उसका प्रयोग ज़रूर करना चाहिए. गांधी जी की यह सूक्ति किसी भी उभरते हुए देश के लिए गीता, बाइबिल या पुराण का वाक्य बन जानी चाहिए, ताकि हम जो भी फैसला करें, ख़ासकर सत्ता में बैठे हुए लोग, यह देखें कि उस फ़ैसले का प्रभाव या फ़ायदा सबसे कमज़ोर आदमी को कितना मिलता है, जिसे वह जानता है. अगर इसे हमने अपना लिया तो इस देश में विकास का पूरा मॉडल ही बदल जाएगा, लेकिन कोई इसे बदलना ही नहीं चाहता. अगर हम विकास के इस मॉडल को नहीं बदलेंगे तो फिर गांधी नहीं, नक्सलवादी आएंगे और हमें यह सोचने पर विवश करेंगे कि हम कहीं ग़लत तो नहीं हैं. गांधी की यही ताक़त है और कमज़ोरी भी. गांधी की ताक़त को लोग कमज़ोरी समझ लेते हैं. इस मुल्क में यह कमज़ोरी कब दूर होगी, जनता के पास इसका जवाब है. जिस दिन यह कमज़ोरी दूर हो गई, उस दिन इस देश का राजनीतिक ढांचा लड़खड़ा जाएगा. उस ढांचे को बनाए रखने की ज़िम्मेदारी आज के राजनीतिक दलों की है, जो अपने रास्ते से भटक गए हैं, अपने विचारों से भटक गए हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि वे आम आदमी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से दूर हो गए हैं. यही ख़तरा सारे देश के सामने मंडरा रहा है कि हमारी सारी राजनीतिक व्यवस्था अप्रासंगिक होती जा रही है, क्योंकि हम उन सवालों को छूना ही नहीं चाहते, जो इस मुल्क के सवाल हैं.

संपादक
editor@chauthiduniya.com

सरकार जीने का हक़ दे या फिर मौत

फ़िरदौस ख़ान

अरुणा शानबाग के बहाने देश में इच्छा मृत्यु के मुद्दे को लेकर बहस शुरू हो गई है, मगर क्या कभी सरकार ने यह सोचा है कि भ्रष्टाचार और प्रशासनिक कोताही के कारण कितने लोग नारकीय जीवन जीने पर मजबूर हैं. ये लोग किससे इच्छा मृत्यु की फ़रियाद करें. अगर सरकार इन लोगों को जीने का हक़ मुहैया नहीं करा सकती तो बेहतर है कि लाल क़िले में फांसी के लिए तख्त ही लगा दिए जाएं, जहां झूलकर ये लोग अपनी बदहाल ज़िंदगी से निजात तो पा सकें. देश में हर रोज़ क़रीब साढ़े तीन सौ लोग आत्महत्या करते हैं और दिनोंदिन यह तादाद बढ़ रही है. हर साल लाखों लोग भूख और बीमारी की वजह से मर जाते हैं. देश में हर रोज़ आठ करोड़ 20 लाख लोग भूखे पेट सोते हैं. 46 फ़ीसदी बच्चे कुपोषण का शिकार हैं. देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं, जो फ़सल काटे जाने के बाद खेत में बचे अनाज और बाज़ार में पड़ी गली-सड़ी सब्जियां बटोर कर किसी तरह उससे अपनी भूख मिटाने की कोशिश करते हैं. महानगरों में भी भूख से बेहाल लोगों को कूड़ेदानों में से रोटी या ब्रेड के टुकड़ों को उठाते हुए देखा जा सकता है. रोज़गार की कमी और ग़रीबी की मार के चलते कितने ही परिवार चावल के मुट्ठी भर दानों को उबाल कर पीने को मजबूर हैं. देश में एक तरफ़ अमीरों के वे बच्चे हैं, जिन्हें दूध में भी बोर्नविटा की ज़रूरत होती है तो दूसरी तरफ वे बच्चे हैं, जिन्हें पेट भर चावल का पानी भी नसीब नहीं हो पाता और वे भूख से तड़पते हुए दम तोड़ देते हैं. इतना ही नहीं, हर साल गोदामों में लाखों टन अनाज सड़ रहा होता है और उसी दौरान भूख से लोग मर रहे होते हैं. ऐसी हालत के लिए क्या व्यवस्था सीधे तौर पर क़ुसूरवार नहीं है?

अरुणा की तरफ़ से अदालत में याचिका दाख़िल करके कहा था कि पिछले 37 सालों से वह मुंबई के अस्पताल में लगभग मृत अवस्था में पड़ी है. इसलिए उसे दया मृत्यु की इजाज़त दी जाए. इस बारे में सरकार का कहना है कि अभी तक भारतीय संविधान में इच्छा मृत्यु देने का कोई प्रावधान नहीं है. अस्पताल ने इच्छा मृत्यु देने का सख्त विरोध किया है. जिस देश में पैसे न होने पर अस्पताल प्रशासन गंभीर मरीज़ों को बाहर निकाल फेंकता है, उसी देश में एक अस्पताल एक ज़िंदा लाश को संभाल कर रखना चाहता है. क्या यह अस्पताल उन गंभीर मरीज़ों के प्रति इतनी ही मानवता दिखाएगा, जिन्हें इलाज की बेहद ज़रूरत है और उनके पास पैसे नहीं है.

देश में आज़ादी के बाद से अब तक ग़रीबों की भलाई के लिए योजनाएं तो अनेक बनाई गईं, लेकिन लालफ़ीताशाही के चलते वे महज़ काग़ज़ों तक ही सिमट कर रह गईं. पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने तो इसे स्वीकार करते हुए यहां तक कहा था कि सरकार की ओर से चला एक रुपया जनता तक पहुंचते-पहुंचते 15 पैसे ही रह जाता है. यानी देश का प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार को क़ुबूल कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भ्रष्टाचार के ख़ात्मे के लिए कोई सख्त क़दम नहीं उठाया जाता. इसके लिए क्या सरकार सीधे तौर पर ज़िम्मेदार नहीं है? अव्यवस्था के कारण देश के अन्नदाता किसान ख़ुदकुशी कर रहे हैं. एक तरफ़ सरकार खाद्य सुरक्षा की बात करती है और दूसरी तरफ़ किसानों को बदहाली में मरने के लिए छोड़ दिया जाता है. बेरोज़गारी से परेशान युवा आत्महत्या कर रहे हैं. इन सबके अलावा लचर क़ानून व्यवस्था भी आम आदमी की मौत की वजह बन रही है. हर साल कितनी ही लड़कियां और महिलाएं बलात्कार का शिकार होने पर अपनी जान दे देती हैं, क्योंकि वे जानती हैं कि पहले तो पुलिस आरोपी को पकड़ेगी नहीं. अगर पकड़ भी लिया तो मामला अदालत में बरसों लटका रहेगा और इस दौरान उसे ही बार-बार अदालत में आपत्तिजनक सवालों से दो-चार होना पड़ेगा. रुचिका गिरहोत्रा के मामले को ही लीजिए. यह मामला क़रीब दो दशक से अदालत में चल रहा है. दिसंबर 2009 में अदालत ने आरोपी हरियाणा पुलिस के पूर्व महानिदेशक एवं लॉन टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष शंभू प्रताप सिंह राठौर को महज़ छह माह क़ैद और एक हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई. केंद्रीय गृहमंत्री पी चिदंबरम ने राठौर को मिली सज़ा पर प्रतिक्रिया ज़ाहिर करते हुए कहा था कि बतौर गृहमंत्री मैं कोई फ़ैसला तो नहीं दे सकता, लेकिन जिस तरह इस मामले में आरोप निर्धारित हुए और आरोपी को सज़ा सुनाई गई, उससे मैं बहुत नाख़ुश हूं. पंचकुला में 14 वर्षीय रुचिका के साथ 12 अगस्त, 1990 को राठौर ने छेड़छाड़ की थी. मामले की शिकायत करने पर रुचिका और उसके परिवारीजनों को प्रताड़ित किया गया और आख़िर तंग आकर उसने 28 दिसंबर, 1993 को आत्महत्या कर ली.

भारत एक ऐसा देश है, जहां पर क़ानून का फ़ायदा मज़लूमों के बजाय ज़ालिम ही ज़्यादा उठाते हैं. अरुणा शानबाग के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ. उसके साथ बलात्कार कर उसकी ज़िंदगी तबाह करने वाला वहशी महज़ सात साल की क़ैद काटकर आज़ाद हो गया, लेकिन पिछले 37 सालों से ज़िंदा लाश बनी अरुणा को मांगे से मौत भी नहीं मिल पा रही है. 27 नवंबर, 1973 को मुंबई के किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल की नर्स अरुणा शानबाग के साथ इसी अस्पताल के सफ़ाईकर्मी सोहनलाल ने बलात्कार किया था. बलात्कार से पहले उसने अरुणा के गले को लोहे की ज़ंजीर से कस दिया था. इसकी वजह से उसके दिमाग़ तक ख़ून पहुंचाने वाली नसें फट गईं और वह एक ज़िंदा लाश बनकर रह गई. हादसे के कुछ दिनों बाद पुलिस ने सोहनलाल को गिरफ्तार कर लिया. हैरत की बात तो यह है कि पुलिस ने सोहनलाल पर अरुणा को जान से मारने की कोशिश करने और कान की बाली लूटने का मामला दर्ज किया. उस पर यौन शोषण से संबंधित कोई धारा नहीं लगाई गई. आख़िर अदालत ने उसे महज़ सात साल क़ैद की सज़ा सुनाई. उसने सज़ा काटी और कुछ वक्त बाद दिल्ली के एक अस्पताल में नौकरी कर ली. बाद में एड्स से उसकी मौत हो गई. सुप्रीम कोर्ट ने अरुणा शानबाग को इच्छा मृत्यु की इजाजत देने संबंधी याचिका को ख़ारिज कर दिया, मगर अदालत ने यह भी कहा कि कुछ परिस्थितियों में पैसिव यूथनेशिया की अनुमति दी जा सकती है. साथ ही अदालत ने पैसिव यूथनेशिया के लिए दिशा-निर्देश भी तय करते हुए कहा कि इस मामले में हाईकोर्ट की मंज़ूरी ज़रूरी है. लेखिका पिंकी विरानी ने दिसंबर 2009 में अरुणा की तरफ़ से अदालत में याचिका दाख़िल करके कहा था कि पिछले 37 सालों से वह मुंबई के अस्पताल में लगभग मृत अवस्था में पड़ी है. इसलिए उसे दया मृत्यु की इजाज़त दी जाए. इस बारे में सरकार का कहना है कि अभी तक भारतीय संविधान में इच्छा मृत्यु देने का कोई प्रावधान नहीं है. अस्पताल ने इच्छा मृत्यु देने का सख्त विरोध किया है. जिस देश में पैसे न होने पर अस्पताल प्रशासन गंभीर मरीज़ों को बाहर निकाल फेंकता है, उसी देश में एक अस्पताल एक ज़िंदा लाश को संभाल कर रखना चाहता है. क्या यह अस्पताल उन गंभीर मरीज़ों के प्रति इतनी ही मानवता दिखाएगा, जिन्हें इलाज की बेहद ज़रूरत है और उनके पास पैसे नहीं है. हालांकि केंद्रीय क़ानून मंत्री एम वीरप्पा मोइली ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को सही क़रार देते कहा है कि क़ानून के बिना सिर्फ़ न्यायिक आदेश पर इस तरह के फ़ैसले लागू नहीं किए जा सकते. यहां बात सिर्फ़ अरुणा को इच्छा मृत्यु देने की नहीं, बल्कि उस व्यवस्था की हो रही है, जिसके कारण एक जीती-जागती लड़की इस हालत में पहुंची. क्यों इस देश में तमाम क़ानून होने के बावजूद वहशी दरिंदों को खुला छोड़ दिया जाता है.

feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

झूठ का पुलिंदा कौन?

विगत एक दशक से रामदेव बाबा देश-विदेश में योग गुरु के रूप में लोगों के दिलों पर छाए हुए हैं. किसी ने बाबा के ख़िलाफ़ एक शब्द भी नहीं बोला, लेकिन जबसे बाबा ने देश में बढ़ते भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ और काले धन की वापसी के लिए जनजागरण किया है, तबसे लोगों की नींद हराम होती जा रही हैं. जबसे बाबा ने राजनीतिक पार्टी की घोषणा की है, तबसे उनके विरोध में मोर्चे खोले जा रहे हैं. जिन लोगों ने कभी बाबा के विरुद्ध एक शब्द नहीं कहा, आज वही लोग उन्हें झूठ का पुलिंदा कह रहे हैं.

संतोष मालवीय प्रेमी, *मालवीय गंज, इटारसी, मध्य प्रदेश*

लेखों के साथ तारीख़ दें

चौथी दुनिया के लेख और तेवर बहुत अच्छे लगे. मुझे लगता है कि इस देश में जनसरोकार की पत्रकारिता की जगह दिनोंदिन सिमट रही है. चौथी दुनिया जैसे संस्थानों ने इसे बचाकर रखा है. बिहार में जो पत्रकारिता हो रही है, वह अपने आप सब बयान कर देती है. एक गुजारिश यह है कि लेखों के साथ उनकी तिथि भी ज़रूर दें. ऐसा होने से उनकी उपयोगिता और बढ़ जाएगी.

दुर्गेश ठाकुर, *ई-मेल से*

सर्वश्रेष्ठ पत्र

काले धन का सदुपयोग

दिल्ली में अपने एक मित्र के घर चौथी दुनिया अख़बार देखा. अच्छा साप्ताहिक है. ऑनलाइन अख़बार भी सराहनीय है. आपके पत्र के माध्यम से काले धन के बारे में कुछ विचार लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं. वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी ने वर्ष 2011-12 का आम बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि काला धन बनाना और उसका इस्तेमाल करना गंभीर चिंता का विषय है. इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने एक पांच सूत्रीय कार्ययोजना लागू की है. काले धन के विरुद्ध वैश्विक संघर्ष में साथ देना, उपयुक्त क़ानूनी ढांचा तैयार करना, अनुचित तरीक़ों से कमाए गए धन से निपटने के लिए संस्थाएं स्थापित करना, क्रियान्वयन के लिए प्रणालियां विकसित करना और लोगों को कौशल का प्रशिक्षण देना इसमें शामिल है. वित्त मंत्रालय ने बेहिसाबी आय और देश के बाहर एवं देश में रखे गए धन के संबंध में एक अध्ययन शुरू किया है. अगर विदेशों से काला धन लाकर उसे देश के विकास में लगाया जाए तो कितना अच्छा होगा.

नवीन प्रकाश, *खरोरा, रायपुर, छत्तीसगढ़*

चौथी दुनिया प्रगति करे

मैं चौथी दुनिया परिवार को बधाई देता हूं, वह मातृभाषा हिंदी को बढ़ावा दे रहा है. चौथी दुनिया अच्छा अख़बार है, इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए, कम है. आपका अख़बार दिनोंदिन प्रगति करे.

हवा सिंह, *गुड़गांव, हरियाणा*

सवर्ण आयोग का गठन

बिहार सरकार ने सवर्ण आयोग का गठन करके एक बड़ा अभूतपूर्व कार्य किया. इससे ग़रीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे सवर्णों के हितों की रक्षा हो सकेगी. ग़रीबी रेखा से नीचे गुज़र-बसर करने वाले बिहारियों में सवर्णों की संख्या कम नहीं है. ऐसे में इस आयोग के माध्यम से सभी ज़रूरतमंद लोगों को सरकार से मिलने वाली सभी सुविधाएं बिना भेदभाव के मिल सकेंगी. आशा है कि यह आयोग सरकार और सवर्णों के बीच सेतु का काम करेगा.

डॉ. रवींद्र कुमार सिंह, *सहरसा, बिहार*

सराहनीय प्रयास

पिछले दिनों चौथी दुनिया पढ़ने का अवसर मिला. अख़बार अच्छा और प्रेरणादायी आकर्षक ख़बरों से परिपूर्ण है. आपका प्रयास सराहनीय है.

शिव मंगल चव्हाण, *अमरावती (विदर्भ), महाराष्ट्र*

सूचना

राजकमल प्रकाशन
नयी दिल्ली पटना इलाहाबाद

अब चौथी दुनिया में सप्ताह के सर्वश्रेष्ठ पत्र को राजकमल प्रकाशन की तरफ़ से 700 रुपये की किताबें पुरस्कार के रूप में दी जाएंगी. पाठक पत्र में अपना पूरा नाम, पता एवं फ़ोन नंबर अवश्य लिखें.

आप अपने स्वतंत्र विचार तथा प्रतिक्रियाएं हमें इस पते पर भेजें. संपादक, चौथी दुनिया, एफ़-2, सेक्टर-11 नोएडा, (उत्तर प्रदेश) पिन-201301
ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

ख़ास बात है कि यह घटना उस समय नहीं हो पाती है, जब मां सामान्य तौर पर सांस ले रही हो.

सूचना का अधिकार – चौथी दुनिया की पहल

ऐसे ख़त्म होगी पेंशन की टेंशन

वृद्धों और विधवाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं, जिनमें से एक है वृद्धावस्था-विधवा पेंशन योजना. इसके तहत एक पंचायत में जितने भी वृद्ध या विधवाएं हैं, उन्हें एक ख़ास रक़म प्रति माह के हिसाब से दी जाती है. इस योजना के क्रियान्वयन में पंचायत की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. पंचायत ही वह संस्था है, जो किसी योजना के तहत लाभार्थियों का चयन करती है. यहां तक तो सब कुछ ठीकठाक चलता है, लेकिन जैसे ही बात लाभार्थियों के चयन की आती है, पक्षपात शुरू हो जाता है. अक्सर ऐसे आरोप लगाए जाते रहे हैं कि पंचायत प्रतिनिधि चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरतते. बहरहाल, इस अंक में एक ऐसा ही आवेदन प्रकाशित किया जा रहा है, जिसके इस्तेमाल से आप पेंशन योजना के लिए चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बना सकते हैं.

पाठकों के पत्र

बैंक मैनेजर परेशान करता है

बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खगड़िया शाखा में मेरी पत्नी के नाम से एक खाता है. 14 अप्रैल, 2010 को पत्नी का स्वर्गवास हो गया. जब मैंने बैंक में जाकर उसके खाते से पैसे निकालने की बात की तो मैनेजर द्वारा ज़रूरी काग़ज़ात मांगे गए. मैंने सारे काग़ज़ात जमा करा दिए, लेकिन मुझे बार-बार परेशान किया जाता है. आठ महीने हो गए, लेकिन अब तक पैसा नहीं मिल सका है.

अनिल प्रसाद सहनी, खगड़िया, बिहार

इस मामले में आप एक शिकायत संबंधित शाखा में जमा करें. दस दिनों बाद अपनी शिकायत पर बैंक द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में सूचना क़ानून के तहत एक आवेदन संबंधित शाखा के लोक सूचना अधिकारी के पास जमा कराएं. आवेदन में आप अपने शिकायत पत्र पर अब तक की गई कार्रवाई के बारे में सीधे सवाल पूछें.

नाम गुप्त रख सकते हैं?

मैं आपके अख़बार की सहायता से निरंतर आरटीआई का इस्तेमाल कर रहा हूं और भ्रष्टाचार के विरुद्ध इसका उपयोग कर रहा हूं. कृपया शिक्षा, पंचायत और अल्पसंख्यक विभाग से सूचना मांगने के लिए आवेदन प्रकाशित करें. क्या हम अपना नाम गुप्त रखकर भी सूचना मांग सकते हैं?

अब्दुल कादिर, गोंडा, उत्तर प्रदेश.

हम इस कॉलम में लगातार विभिन्न विषयों पर आवेदन प्रकाशित करते हैं. दरअसल, आरटीआई आवेदन का स्वरूप एक ही होता है. सिर्फ़ विभाग के पते और अपने सवाल बदल दें. जहां तक नाम गुप्त रखकर सूचना मांगने की बात आपने पूछी है, वह क़ानूनन सही नहीं है. आरटीआई क़ानून के मुताबिक़ आवेदन में अपना नाम और पूरा पता देना अनिवार्य है.

समय पूर्व अनिवार्य सेवानिवृत्ति

मध्य प्रदेश सरकार एवं सड़क परिवहन विभाग द्वारा केंद्रीय क़ानूनों का उल्लंघन करते हुए कर्मचारियों को समय पूर्व अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है. इस संबंध में मध्य प्रदेश राज्य निगम मंडल कर्मचारी महासंघ ने आरटीआई के तहत भारत सरकार के श्रम मंत्रालय से कुछ सूचनाएं मांगी थीं. आवेदन बीती 25 जनवरी को भेजा गया था, लेकिन अब तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है.

राम सिंह बघेल, रीवां, मध्य प्रदेश

आप इस मामले में श्रम मंत्रालय में ही आरटीआई क़ानून के तहत प्रथम अपील कर सकते हैं. यदि प्रथम अपील के बाद भी सूचना नहीं मिलती है, तब आप केंद्रीय सूचना आयोग में द्वितीय अपील कर सकते हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है :

चौथी दुनिया

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन -201301
ई-मेल : rti@chauthiduniya.com

आवेदन का प्रारूप

(वृद्धावस्था/विधवा पेंशन का विवरण)

सेवा में,
लोक सूचना अधिकारी
(विभाग का नाम)
(विभाग का पता)

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन

महोदय,

मैं वृद्धावस्था/विधवा पेंशन धारक/धारिका हूं. मेरा खाता नंबर........ है, लेकिन............के बाद से अब तक मुझे पेंशन नहीं मिली है. कृपया इस संबंध में सूचना के अधिकार के तहत निम्नलिखित सूचनाएं प्रदान करें:

1. विभाग/कार्यालय के रिकॉर्ड के अनुसार पिछले एक साल में मेरे नाम पर कब-कब और कितनी बार वृद्धावस्था/विधवा पेंशन का भुगतान किया गया? इसका मासिक विवरण निम्नलिखित ब्योरों के साथ दें:
   क. भुगतान की राशि
   ख. भुगतान की तारीख
   ग. रजिस्टर के उन पन्नों की प्रमाणित प्रति दें, जहां मेरे भुगतान का विवरण दर्ज हो.

2. आपके रिकॉर्ड के अनुसार.............में कुल कितने लोगों को वृद्धावस्था/विधवा पेंशन योजना के तहत पेंशन की राशि का भुगतान किया जा रहा है? उनकी सूची निम्नलिखित विवरणों के साथ उपलब्ध कराएं:
   क. पेंशन धारक का नाम एवं पता
   ख. पेंशन धारक की उम्र
   ग. भुगतान की जा रही राशि
   घ. भुगतान का माध्यम (नगद या बैंक खाते के माध्यम से)
   ड. भुगतान किए जाने से संबंधित रजिस्टर की पिछले एक साल की प्रमाणित प्रति दें.

3. पेंशन के भुगतान के लिए ज़िम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम एवं पद बताएं.

4. वृद्धावस्था/विधवा पेंशन का भुगतान वर्ष में कितनी बार किया जाता है? यह भुगतान किस तिथि तक कर दिया जाना चाहिए? वर्ष........में कब-कब इसका भुगतान किया गया?

5. अगर..........के दौरान मुझे पेंशन का भुगतान नहीं किया गया है तो इसके लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी ज़िम्मेदार हैं? उन अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम, पद एवं पते बताएं.

6. अपना काम ठीक से न करने और जनता को परेशान करने वाले इन अधिकारियों/कर्मचारियों के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की जाएगी? यह कार्रवाई कब तक की जाएगी?

मैं आवेदन शुल्क के रूप में.......रुपये अलग से जमा कर रहा/रही हूं.
या
मैं बीपीएल कार्डधारक हूं, इसलिए सभी देय शुल्कों से मुक्त हूं. मेरा बीपीएल कार्ड नंबर..........है.

यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित न हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन संबंधित लोक सूचना अधिकारी को पांच दिनों की समयावधि के अंतर्गत हस्तांतरित करें. साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम और पता अवश्य बताएं.

भवदीय

नाम...................
पता...................
फोन नंबर.............

संलग्नक..........
(यदि कुछ हो तो)

साथ धड़कते हैं दिल

मां और बच्चे का रिश्ता वैसे तो अनोखा होता ही है, लेकिन गर्भावस्था में शिशु का दिल मां के दिल के साथ धड़कता है. इस बात का ख़ुलासा वैज्ञानिकों ने किया है. उनका मानना है कि जब गर्भवती महिला लयबद्ध ढंग से सांस लेती है तो उसका और भ्रूण का दिल साथ-साथ धड़कता है. ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ एबरडीन के वैज्ञानिकों का दावा है कि इस शोध से एक नई तकनीक की खोज का मार्ग प्रशस्त होता है. इस तकनीक की मदद से गर्भावस्था के दौरान भ्रूण विकास संबंधी समस्याओं का पता लगाने में मदद मिलेगी. वैज्ञानिकों ने बताया कि अगर दोनों के दिलों का धड़कना साथ-साथ न हो तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं कोई दिक्कत है. ऐसे में गर्भवती मां को डॉक्टरी सलाह की ज़रूरत होगी.

वैज्ञानिकों के दल में शामिल डॉ. मार्को थील ने कहा, गर्भवती महिलाएं अक्सर अपने बच्चे के साथ भावनात्मक संबंध की जानकारी देती हैं, लेकिन अभी तक इस बात का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं था कि यह जुड़ाव एक साथ दिल की धड़कन में दिखाई देता है. उन्होंने कहा, हमारे नतीजों से पता चलता है कि मां और भ्रूण के दिल एक साथ धड़कते हैं, लेकिन यह तभी होता है, जब मां लयबद्ध तरीक़े से सांस ले रही हो. डॉ. थील ने कहा, इन सबके बीच ही भ्रूण अपने दिल की धड़कन के साथ समायोजन बैठाता है. ख़ास बात है कि यह घटना उस समय नहीं हो पाती है, जब मां सामान्य तौर पर सांस ले रही हो. अध्ययन के नतीजों का इस्तेमाल अब जर्मनी के ग्रोनीमेयर इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रो थेरेपी में गर्भवती महिलाओं के इलाज में किया जा रहा है. उम्मीद जताई जा रही है कि इससे रिश्तों के नए आयाम खुलेंगे.

भालू की टेस्ट ड्राइव

जानवरों में सबसे शरारती कौन है, अगर यह पूछा जाए तो सभी लोग बंदर का नाम लेंगे, लेकिन यह शरारत बंदर नहीं, भालू कर रहा है. हम अक्सर जानवरों की अजीबो-ग़रीब हरकतों को सुनकर मज़े लेते हैं. अगर बात भालू की हो तो मामला और भी रोचक बन जाता है. ऐसा ही अमेरिका के कोलोराडो शहर में उस समय देखने को मिला, जब एक भालू ने कार की ड्राइविंग का जमकर लुत्फ़ उठाया. हुआ यूं कि कोलोराडो शहर में एक भालू ख़ाली कार में घुस गया. इसके बाद चालक की सीट पर बैठकर उसने हॉर्न बजाया और कार को पहाड़ी से नीचे गिरा दिया. इसके बावजूद वह डरा हुआ कार के अंदर बैठा रहा. कार के मालिक ने उस भालू की तस्वीर भी ली. भालू ने भागने की कोशिश में कार का भीतरी हिस्सा नष्ट कर दिया. इसके बाद पुलिस ने एक रस्सी के सहारे कार का दरवाज़ा खोला और भालू को मुक्त कराया. कार की पिछली सीट पर एक सैंडविच रखा था. माना जाता है कि भालू सैंडविच पाने की कोशिश में कार के अंदर चला गया. मामला कुछ यूं हुआ. सुबह के समय जब भालू 2008 मॉडल की टोयोटा कोरोला कार के अंदर दाख़िल हुआ, उस समय कार में लॉक नहीं लगा था. कार मालिक बेन और उसका परिवार सोया हुआ था. उसने डेनवर न्यूज़ चैनल को बताया कि हो सकता है, भालू से कार का गियर दब गया हो, जिससे वह न्यूट्रल में आ गई और 125 फ़ीट नीचे सरकते हुए झाड़ियों में आ गिरी. कार मालिक ने कहा, लगता है कि जो कुछ हो रहा था, भालू को पता था. वह लगातार कार का हॉर्न बजाता रहा. दरवाज़ा बंद होने के बाद भालू कार के अंदर फंस गया. उसने बताया कि कार पूरी तरह नष्ट हो गई. भालू का आकार अच्छा-ख़ासा था. कार के अंदर कुछ भी नहीं बचा था. भालू ने कार के अंदर के पूरे हिस्से की तहक़ीक़ात की थी. आख़िर में उसे जंगल में भागते हुए देखा गया. कोलोराडो के वन्य जीव विशेषज्ञ टाइलर बास्कफ़ील्ड ने बताया कि भोजन की तलाश में भालू कारों और घरों में घुस जाते हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

राशिफल

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल)
किसी शुभचिंतक या पारिवारिक मित्र से आर्थिक सहायता मिलने से आपका मनोबल बढ़ जाएगा. ख़र्च की अधिकता के बावजूद समय पर उसकी आपूर्ति भी हो जाएगी. वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, नहीं तो दुर्घटना हो सकती है.

वृष (21 अप्रैल से 20 मई)
इस सप्ताह के मध्य तक जहां आपके धन कोष में वृद्धि होगी, वहीं कुछ ज़रूरी ख़र्च भी आप अपने रहन-सहन के लिए कर सकते हैं. शिक्षा के क्षेत्र में किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सफलता के योग बने हुए हैं.

मिथुन (21 मई से 20 जून)
मित्रों और शुभचिंतकों का सहयोग भी आपके लिए प्रेरणास्रोत बनेगा. कार्यक्षेत्र में अच्छी प्रगति होने से आपको इसका लाभ भी तत्काल मिल सकता है. सप्ताहांत में पदोन्नति या पद वृद्धि की संभावना रहेगी.

कर्क (21 जून से 20 जुलाई)
आपके सहयोगी, मित्र और परिवारीजन आपसे बहुत प्रभावित रहेंगे. सप्ताहांत में ख़र्च में कुछ वृद्धि हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल अपनी साख बचने के लिए ऐसा करना बहुत ज़रूरी है. स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें.

सिंह (21 जुलाई से 20 अगस्त)
कार्यक्षेत्र में बदलाव करने या कामकाज के नए तौर-तरीक़े अपनाने से आपको प्रत्यक्ष रूप से तत्काल लाभ हो सकता है. माता-पिता या मित्रों का सहयोग फ़िलहाल मिलता रहेगा.

कन्या (21 अगस्त से 20 सितंबर)
किसी नए उपक्रम या कार्यक्षेत्र में प्रवेश करने की योजना बन सकती है. सप्ताहांत तक किसी भोज या दावत में शामिल हो सकते हैं. पेट से संबंधित कोई शिक़ायत हो सकती है. व्यय पर नियंत्रण बनाए रखें.

तुला (21 सितंबर से 20 अक्टूबर)
कोई निवेश करने से पहले बुज़ुर्गों की सलाह अवश्य लें तो बेहतर होगा. सामाजिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्र में वृद्धि होगी. इस सप्ताह कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम बनाएंगे. नेत्र संबंधित तकलीफ़ हो सकती है, डॉक्टर को दिखाने में कोताही न बरतें.

वृश्चिक (21 अक्टूबर से 20 नवंबर)
सप्ताह के मध्य में परिवार के किसी छोटे सदस्य या संतान पक्ष की ओर से कोई चिंता परेशानी का कारण बन सकती है. वाणी में मधुरता बनाए रखें, नहीं तो विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है.

धनु (21 नवंबर से 20 दिसंबर)
आपके परिवारीजनों और शुभचिंतकों का मूड कुछ ख़राब नज़र आएगा. संतान पक्ष की ओर से वाद-विवाद की आशंका रहेगी. घर का कोई बुज़ुर्ग आपके निर्णय से सहमत नहीं होगा. स्वास्थ्य ठीक रहेगा.

मकर (21 दिसंबर से 20 जनवरी)
यदि आप अपने काम से काम रखें और तत्परता से अपने कारोबार पर ध्यान दें तो सप्ताहांत में आपके भौतिक सुख-साधनों में वृद्धि होगी. आर्थिक क्षेत्र में किया जा रहा प्रयास सफल होगा.

कुंभ (21 जनवरी से 20 फरवरी)
मांगलिक कार्यों के लिए किया जा रहा प्रयास सफल साबित होगा. अचानक किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है. किसी के लड़ाई-झगड़े में न पड़ें, वरना आप ही फंस सकते हैं. आय के नए रास्ते खुलेंगे.

मीन (21 फरवरी से 20 मार्च)
रचनात्मक क्षेत्र में किया जा रहा प्रयास सफल साबित होगा. यात्रा पर जाते समय अपने सामान के प्रति सचेत रहें. संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा. काफ़ी लंबे समय से अधूरा पड़ा कार्य पूरा हो जाएगा.

पंडित सुदर्शन
feedback@chauthiduniya.com

आज भारत विश्व शक्ति बनकर उभरने का दावा कर रहा है, फिर भी देश में हर चौथा व्यक्ति भूखा है. भारत में अनाज की उपलब्धता पर जारी एक रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया है.

महंगाई पर मांग और आपूर्ति की मार

राजीव रंजन तिवारी

महंगाई ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है. अब जो सबसे बड़ा सवाल है, वह यह है कि एक प्रमुख अर्थशास्त्री डॉ. मनमोहन सिंह के हाथों में देश की कमान होते हुए भी इस समस्या का निदान क्यों नहीं हो रहा है. हालत यह है कि देश के मध्यम एवं निम्न वर्ग के लोगों की ज़िंदगी की गणित गड़बड़ा गई है. विशेषज्ञ बताते हैं कि मनुष्य की मूलभूत ज़रूरतों की मांग और आपूर्ति के बीच के फासले से ही महंगाई ने उग्र रूप धारण किया है, जिसके हाल-फ़िलहाल में ठीक होने की उम्मीद कम है. दुनिया भर से एकत्र किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि चीन, वियतनाम, श्रीलंका एवं ब्राज़ील सरीखे देशों में भी खाद्य पदार्थों की क़ीमतें लगातार बढ़ रही हैं. अल्ज़ीरिया में तो खाद्य सामग्री को लेकर दंगे हुए हैं. रूस जैसे बड़े गेहूं उत्पादक देश में मौसम की मार के कारण इस वर्ष गेहूं के उत्पादन में पांच फ़ीसदी गिरावट आने का अनुमान है. हाल में भारत आए चीन के प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ ने भी स्वीकारा था कि उनका देश भी महंगाई से परेशान है. और तो और, अमेरिका की कहानी भी बिगड़ रही है.

महंगाई ने दुनिया को इस कदर परेशान कर दिया कि बीते वर्ष प्रमुख औद्योगिक देशों (अमेरिका, कनाडा, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और जापान) के वित्त मंत्रियों ने कनाडा में एक बैठक की, जिसमें केंद्रीय बैंकों के प्रमुखों ने हिस्सा लिया. बैठक में महंगाई और मंदी से निपटने के लिए तमाम मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा हुई, लेकिन नतीजा कुछ ख़ास नहीं निकला. बैठक के बाद कनाडा के वित्तमंत्री जिम फ्लेहर्टी ने कहा कि वैश्विक आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है. हालांकि अब तक सुधार की प्रक्रिया मज़बूत नहीं हुई है. आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) विकसित देशों का संगठन है, जिसमें अमेरिका और जापान जैसे देश शामिल हैं. वैश्विक उत्पादन में इन देशों का 60 फ़ीसदी से अधिक योगदान है, लेकिन ओईसीडी के हाल के आंकड़े बताते हैं कि इन देशों में बेरोज़गारी उच्च स्तर पर है. स्पेन में सर्वाधिक बेरोज़गारी दर 20.6 फ़ीसदी रही. इसके बाद क्रमश: स्लोवाक रिपब्लिक (14.5 फ़ीसदी) और आयरलैंड (13.9 फ़ीसदी) का स्थान रहा. जर्मनी में बेरोज़गारी दर 6.7 फ़ीसदी देखी गई. कनाडा, फिनलैंड, कोरिया और स्वीडन में बीते नवंबर महीने में बेरोज़गारी दर में हल्की कमी दर्ज की गई है. जबकि ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, फ्रांस, हंगरी और लक्जमबर्ग में वृद्धि दर्ज की गई.

आम तौर पर आयात और निर्यात के बीच बेहद चौड़ी खाई को घरेलू स्तर पर आयातित उत्पादों की मांग घटाकर पाटा जाता है. इसके लिए मुद्रा की क़ीमत महंगी की जाती है. क़र्ज़ की मांग घटाने के लिए भी केवल यही रास्ता बचता है. फ़िलहाल क़र्ज़ की मांग 24 फ़ीसदी की दर से बढ़ रही है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक 20 फ़ीसदी तक लाना चाहता है. वैश्विक बाज़ारों में जिंसों की बढ़ती क़ीमतों की चुनौती अभी बरक़रार है. यह एक बड़ा कारण है, जिसके चलते रिज़र्व बैंक स्थानीय स्तर पर क़ीमतों को थामने के लिए अपनी नीतियां सख्त करेगा. वह बैंक दरों में 25 आधार अंकों की बढ़ोत्तरी कर सकता है. बैंकों को इस वर्ष

बीते वर्ष प्रमुख औद्योगिक देशों (अमेरिका, कनाडा, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और जापान) के वित्त मंत्रियों ने कनाडा में एक बैठक की, जिसमें केंद्रीय बैंकों के प्रमुखों ने हिस्सा लिया. बैठक में महंगाई और मंदी से निपटने के लिए तमाम मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा हुई, लेकिन नतीजा कुछ ख़ास नहीं निकला. बैठक के बाद कनाडा केवित्तमंत्री जिम फ्लेहर्टी ने कहा कि वैश्विक आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है.

नीतिगत दरों में भी इज़ाफ़ा करना होगा, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे यहां मुद्रा स्फीति की चुनौती की वजह मौद्रिक विस्तार कतई नहीं है. चूंकि मुद्रा स्फीति पर पड़ रहे तमाम दबाव मांग के कारण नहीं हैं. अत: रिज़र्व बैंक इससे निपट सकता है, क्योंकि नीतियां सख्त करने से विकास पर विपरीत असर पड़ेगा.

पिछले दिनों केंद्र सरकार के मंत्री समूह की बैठक हुई, जिसमें महंगाई से निपटने के उपायों पर विचार हुआ. कहा गया कि सरकार महंगाई से लड़ना चाहती है, लेकिन विकास की क़ीमत पर नहीं. सरकार खाद्य सुरक्षा विधेयक संसद में पेश करने के लिए प्रतिबद्ध है, इससे बढ़ती महंगाई पर नियंत्रण में मदद मिलेगी. संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि दुनिया भर में एक अरब से अधिक लोग हर दिन भूखे रह जाते हैं और विश्व की जनसंख्या का छठा हिस्सा भूखा सोता है. कोई भी देश इससे अछूता नहीं है. खाद्यान्नों की उत्तरोत्तर कमी होती जा रही है. इस वक़्त दुनिया में उपलब्ध कृषि योग्य ज़मीन बढ़ती आबादी के लिए खाद्यान्न पैदा करने की दृष्टि से अपर्याप्त है. 2050 तक खाद्यान्न उत्पादन में कम से कम 70 फ़ीसदी की वृद्धि की आवश्यकता होगी, क्योंकि अनुमान है कि अगले चार दशकों में दुनिया की आबादी बढ़कर नौ अरब हो जाएगी. संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि दुनिया की वर्तमान कृषि योग्य ज़मीन की पैदावार अगर बढ़ाई जाती है तो भी 2050 तक कम से कम 37 करोड़ लोग भुखमरी के शिकार होंगे.

आज भारत विश्व शक्ति बनकर उभरने का दावा कर रहा है, फिर भी देश में हर चौथा व्यक्ति भूखा है. भारत में अनाज की उपलब्धता पर जारी एक रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया है. रिपोर्ट के अनुसार, आबादी के हिसाब से दुनिया के दूसरे सबसे बड़े देश में तक़रीबन 21 करोड़ से अधिक लोगों को भर पेट भोजन नहीं मिल पाता है. संख्या के अनुपात में यह अफ्रीका के सबसे ग़रीब देशों से भी ज़्यादा है. सच तो यह है कि एक आम आदमी को प्रति वर्ष मिलने वाली खाद्य सामग्री पिछले 10 वर्षों के भीतर 34 किलो कम हो गई है. वैश्विक आर्थिक संभावनाएं-2011 शीर्षक से प्रकाशित अपनी ताजा रिपोर्ट में विश्व बैंक ने कहा है कि विश्व की अर्थव्यवस्था वर्ष 2011 और 2012 में धीमी गति के साथ, लेकिन मज़बूती से बढ़ने की दिशा में है. अनुमान है कि इस दौरान वैश्विक आर्थिक वृद्धि में क़रीब आधा योगदान चीन और भारत का होगा. विश्व बैंक ने अपने अनुमान में कहा है कि वैश्विक जीडीपी 2010 के 3.9 प्रतिशत के मुक़ाबले 2011 में घट कर 3.3 प्रतिशत रहेगी. 2012 में इसके फिर से 3-6 प्रतिशत तक पहुंचने की संभावना है. रिपोर्ट के अनुसार, 2010 में विकाशील देशों की वृद्धि दर सात प्रतिशत रही. 2011 और 2012 में इसके 6 प्रतिशत रहने की संभावना है. उधर भारतीय वित्त मंत्रालय उम्मीद कर रहा है कि देश आगामी वित्तीय वर्ष से 9 फ़ीसदी से अधिक विकास दर हासिल कर लेगा. हालांकि इस दर को प्राप्त करने की राह उतनी आसान भी नहीं होगी, क्योंकि पश्चिम एशिया में व्याप्त अस्थिरता, वैश्विक अर्थव्यवस्था के वापस पटरी पर लौटने को लेकर जताई जा रही अनिश्चितता और कई अन्य कारक भारत की उम्मीदों पर पानी फेर सकते हैं.

feedback@chauthiduniya.com

देश का पहला इंटरनेट टीवी

हर दिन 50,000 से ज़्यादा दर्शक

- दो टूक-संतोष भारतीय के साथ
- ब्लैक एंड व्हाइट रोज़ाना 1 बजे
- पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया
- स्पेशल रिपोर्ट
- नायाब हैं हम-उर्दू के मशहूर शायरों, गीतकारों के साथ मुलाक़ात
- साई की महिमा

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301 www.chauthiduniya.tv

हमें भी अपने जीवन में यह देखने की ज़रूरत है कि हमने किस सीमित सोच की बेड़ियों में ख़ुद को बांध रखा है?

हम सीमित सोच की बेड़ियों में बंधे हैं

ऑसिम खेत्रपाल

आज एक कहानी से बात की शुरुआत करते हैं. एक बार एक व्यक्ति को हाथी ख़रीदना था, वह महावत के पास पहुंचा. वहां कई बड़े-बड़े हाथी बंधे खड़े थे, लेकिन उस व्यक्ति को बहुत हैरानी हुई कि उन हाथियों को बांधने वाली वे बेड़ियां लोहे की नहीं, बल्कि पतली रस्सी की थीं, जिन्हें वे हाथी कभी भी तोड़ सकते थे. उस व्यक्ति ने महावत से पूछा, ये इतनी पतली रस्सियों से कैसे टिके रहेंगे? तब महावत ने बताया, जब ये हाथी छोटे थे, बच्चे थे, इन्हें इन्हीं रस्सियों से बांधा जाता था और ये इन बेड़ियों को तोड़ नहीं पाते थे, तबसे इनके मन में बैठ गया है कि ये ज़ंजीरें टूट नहीं सकतीं. बड़े होने के बाद इन्हें तोड़ पाने की क्षमता होने के बावजूद इनके मन में बैठा यह विश्वास कि ये रस्सियां टूट नहीं सकतीं, इन्हें इन रस्सियों को तोड़ने नहीं देता.

हमें भी अपने जीवन में यह देखने की ज़रूरत है कि हमने किस सीमित सोच की बेड़ियों में ख़ुद को बांध रखा है? वह बिलीव सिस्टम, जिसमें एक ही ढर्रे पर ज़िंदगी चल रही है. अपने सीमित परिवार, अपनी सीमित सोच के दायरे से परे वृहद को स्वीकारें. बूंद अपना अस्तित्व इसलिए नहीं छोड़ना चाहती कि वह चाहे बूंद ही है, पर है तो. लेकिन समुद्र में मिलते ही क्यों न सोचे कि यह समुद्र ही वह हो गई. आप सर्कस में भी देखें, एक्रोबेट्स जब अपना हाथ छोड़कर अपने साथी का हाथ पकड़ते हैं तो एक पल के लिए वे बिल्कुल हवा में अकेले होते हैं, लेकिन उनका संपूर्ण विश्वास कि उनका साथी हाथ ज़रूर पकड़ लेगा, उन्हें उस पल से बाहर निकालता है. उसी तरह परमात्मा के साथ का विश्वास आपको भी मुश्किलों से बाहर निकलने का साहस देता है. आप पुरानी सोच की बेड़ियों को तोड़कर नई सोच और जीवन के नए अध्याय के लिए तैयार हो सकते हैं. अगर जीवन के किसी भी मोड़ पर लगे कि कोई रुकावट है, सब रास्ते बंद हो गए हैं, घुटन हो रही हैं, ज़िंदगी थक सी गई है, तब शायद यह देखने की ज़रूरत है कि कौन सी बेड़ियां हैं, जो हमें बांधे हैं और शायद जिन्हें हम बहुत मज़बूत समझ रहे हैं, वे एक झटके में टूट सकती हैं. एक विश्वास और भी रखें कि जब भी आप कुछ नया करने के लिए, कुछ सकारात्मक करने के लिए किसी बेड़ी को तोड़ेंगे तो सृष्टि की सारी ताक़त आपका साथ देने के लिए तैयार मिलेगी. ज़रूरत होगी एक क़दम हिम्मत के साथ बढ़ाने की. आप अगर विश्वास और आस्था की डोर थामकर यह क़दम उठा पाते हैं तो सौ क़दम कुदरत के आपको मिलते हैं. हां, यह भी तय है कि नकारात्मक ऊर्जा भी इतनी ही प्रबल होगी आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए, लेकिन अगर आस्था का दीपक हाथ में हो तो कोई भी अंधेरा आपको डरा न पाएगा. ज्ञान और विश्वास के तेल से इस दीपक को जलाए रखें, उजाले कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे.

ओम साई राम.

feedback@chauthiduniya.com

पहेली का उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोग साई सच्चरित्र का पाठ करें. सात दिन के अंदर इसका संपूर्ण पाठ करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी.

इस बार का प्रश्न है-शिरडी के साई बाबा अपना गुरु किसे माना था? क्या वह गुरु बनने के लायक़ थे?

सही जवाब भेजने वाले तीन विजेता पाठकों को फाउंडेशन की ओर से आकर्षक ईनाम मिलेंगे. आप अपने जवाब हमें भेज सकते हैं इस पते पर

शिरडी साई बाबा फाउंडेशन,
एच 252, कैलाश प्लाजा, संत नगर, ईस्ट ऑफ कैलाश
नई दिल्ली- 110065
आप अपने जवाब **info@ssbf.in** भी पर भी भेज सकते हैं.
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें. 011-46567351, 46567352

ज्ञानोदय

असफलता केवल यही सिद्ध करती है कि सफलता के लिए पूरे प्रयास नहीं किए गए. *स्व. मालती कपूर*

मां होने के कारण नारी का स्थान भगवान से भी ऊंचा है. *प्रेमचंद*

विचारों को दबाया नहीं जा सकता. एक दिन विचार कंदरा फोड़ कर संसार पर छा जाते हैं. *स्व. तारा चंद्र मेहरोत्रा*

श्री सद्गुरु साई बाबा के ग्यारह वचन

1. जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा.
2. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर.
3. त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा.
4. मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस.
5. मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो.
6. मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए.
7. जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का.
8. भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा.
9. आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर.
10. मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया.
11. धन्य धन्य व भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य.

ग्यारह वचन

१. जो शिरडी आएगा। आपद दूर भगाएगा।
२. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर। पैर तले दुःख की पीढ़ी पर।
३. त्याग शरीर चला जाऊँगा। भक्त हेतु दौडा आऊँगा।
४. मन में रखना दृढ़ विश्वास। करे समाधी पूरी आस।
५. मुझे सदा जीवित ही जानो। अनुभव करो सत्य पहचानो।
६. मेरी शरण आ खाली जाए। हो कोई तो मुझे बताए।
७. जैसा भाव रहा जिस मन का। वैसा रुप हुआ मेरे मन का।
८. भार तुम्हारा मुझ पर होगा। वचन न मेरा झूठा होगा।
९. आ सहायता लो भरपूर। जो माँगा वह नही है दूर।
१०. मुझ में लीन वचन मन काया। उसका ऋण न कभी चुकाया।
११. धन्य धन्य व भक्त अनन्य। मेरी शरण तज जिसे न अन्य।

संपर्क करें:
शिरडी साईं बाबा फाउन्डेशन
252-H, LGF कैलाश प्लाज़ा, सन्तनगर, ईस्ट अफ़ कैलाश, मेन रोड, नई दिल्ली-110065.
Tel./Fax: 91-11-46567351/52
web: www.ssbf.in

कृष्ण की नगरी में आपका अपना घर!

Giriraj Sai Hills

Sai Vihar Township
Spiritual home... away from home

- Fully Furnished and Spacious studio Apartments.
- One Bedroom Apartments.
- Two bedroom Apartments.
- Fully Furnished Villas.

STARTING FROM RS. 9.65 LAKHS*

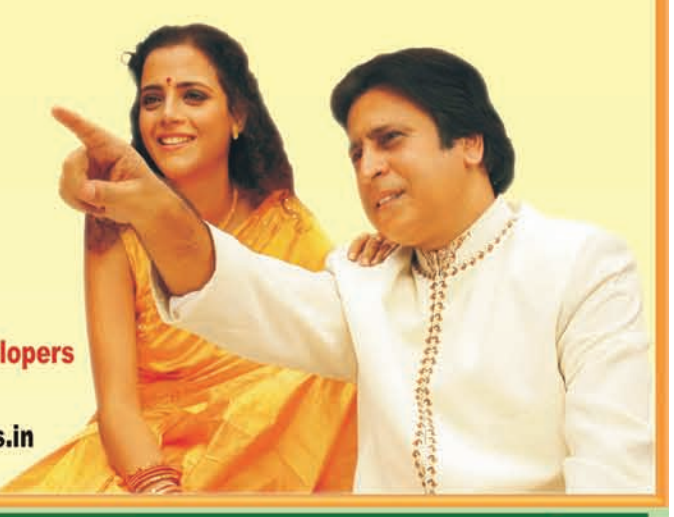

AUM Infrastructure & Developers
Aum Infrastructure & Developers
Email: info@ssbf.in
Website: www.girirajsaihills.in

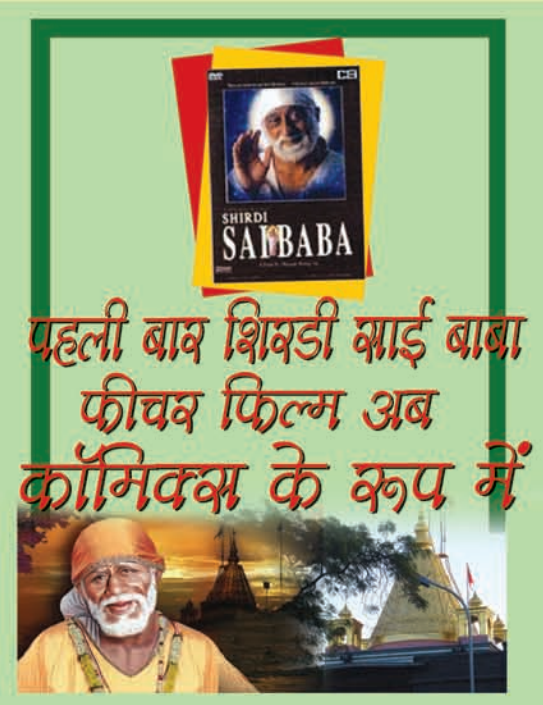

पहली बार शिरडी साई बाबा फीचर फिल्म अब कॉमिक्स के रूप में

सभी साई भक्तों को विनम्रता से सूचित किया जाता है कि आप अपने साई अनुभव, साई उत्सवों आदि की विस्तृत सूचना, फाउंडेशन में सदस्यता के लिए info@ssbf.in पर मेल या 011-46567351/52 पर संपर्क कर सकते हैं.

शारदा सिन्हा ने स्वयं कई गीत लिखे. भोजपुरी कोकिला, बिहार रत्न, भोजपुरी एवं मिथिला विभूति आदि उपाधियों से सम्मानित शारदा सिन्हा को वर्ष 1991 में पद्मश्री सम्मान मिला.

अनंत विजय

लोक से दूर होती कविता

एक दिन दफ्तर के साथियों से कविता पर बात शुरू हुई. मेरे मन में सवाल बार-बार कौंध रहा था कि अब कोई दिनकर, बच्चन या श्याम नारायण पांडे जैसी कविताएं क्यों नहीं लिखता. आज जिस तरह की कविताएं लिखी जा रही हैं, वे सिर्फ़ कुछ ख़ास लोगों की समझ में आती हैं और एक सीमित दायरे में ही उन्हें प्रचार-प्रसार और सम्मान मिलता है. लोक के बीच न तो उन्हें प्रियता हासिल होती है और न ही वे लोगों की ज़ुबान पर चढ़ पाती हैं. कविता के मामले में मेरी जानकारी न के बराबर है, लेकिन बहुधा मन में यह सवाल उठता है कि छंद वाली कविता या फिर जोश या जुनून पैदा करने वाली कविता क्यों नहीं लिखी जा रही है. आज दिनकर की रे रोक युधिष्ठिर को न यहां जाने दे उसको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा लौटा दे अर्जुन भीम वीर या फिर बच्चन की बैर बढ़ाते मंदिर-मस्जिद, मेल कराती मधुशाला या फिर श्याम नारायण पांडे की रण बीच चौकड़ी भर-भरकर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था जैसी कविताएं क्यों नहीं लिखी जा रही हैं.

मेरे इन सवालों पर मेरे एक मित्र ने कहा कि प्रगतिवादियों के विकास और साहित्य पर वामपंथियों के दबदबे ने इस तरह की कविता को बहुत नुक़सान पहुंचाया. मैंने जब इसका विरोध किया तो वह और मज़बूती से अपनी बात कहने लगे. उनका तर्क था कि जिस तरह से हिंदी में एक ख़ास तरह की विचारधारा वाली कविता का दौर शुरू हुआ और मार्क्सवादी आलोचकों ने उसे जिस तरह से उठाया, उसने कविता का बड़ा नुक़सान किया. उनका तर्क था कि मार्क्सवादी आलोचकों ने विचारधारा वाली कविता को श्रेष्ठ साबित करने के लिए छंद में कविता लिखने वालों को मंचीय कवि कहकर मज़ाक उड़ाना शुरू कर दिया. पूरे हिंदी साहित्य में ऐसा परिदृश्य निर्मित कर दिया गया कि अगर आप छंदबद्ध कविता करते हैं और मंच पर सुर में कविता पाठ करते हैं तो आप प्रतिष्ठित कवि या गंभीर कवि नहीं हैं. उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि इस दुष्प्रचार का नतीजा यह हुआ कि आगे आने वाली पीढ़ी ने छंद वाली कविता लिखना बंद कर दिया, मंच पर जाना बंद कर दिया. कविता का जो संवाद लोक से होता था, वह बंद हो गया. मंच पर होने वाली कवि गोष्ठी से लोगों में पढ़ने का जो एक संस्कार बनता था,

वह ख़त्म हो गया. किसी कवि की अगर कोई रचना लोगों को पसंद आती थी तो वे उसकी किताब ढूंढते थे और खोज कर उसे न केवल ख़रीदते थे, बल्कि पढ़कर उस पर चर्चा करते थे. इस तरह से समाज में कवि और कविता को लेकर एक संस्कार, एक समझ विकसित होती थी. लेकिन कवि गोष्ठी के ख़त्म होने या फिर कमरों में सिमट जाने से कवियों का जो एक वृहत्तर संवाद होता था, उसका दायरा भी सिमट गया. इसका नतीजा यह हुआ कि पाठकों में भी कमी आई, रचना का प्रचार-प्रसार कम से कमतर होता चला गया. पाठकों को नई रचनाओं के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई, जिसके चलते कविता संग्रह या तो प्रकाशकों के पास सालों साल पड़े रहे या फिर सरकारी ख़रीद के बूते लाइब्रेरी की शोभा बढ़ाते रहे.

मेरे मित्र अपनी बातें इस मज़बूती से कह रहे थे कि हम तीन लोग भावविभोर होकर उन्हें सुन रहे थे. बीच-बीच में टोकाटाकी उन्हें और मज़बूती प्रदान कर रही थी, लेकिन उनके तर्कों में ताक़त थी, जिस वजह से हम उन्हें सुनना चाह रहे थे. नई पीढ़ी के कवियों के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि नए लड़कों को लगने लगा कि अगर वे विचारधारा की या आम आदमी की यथार्थवादी कविता नहीं लिखेंगे तो हिंदी साहित्य में उनकी नोटिस नहीं ली जाएगी, उनकी पहचान नहीं बन पाएगी, उन्हें पुरस्कार आदि नहीं मिल पाएगा. यह उस माहौल का नतीजा था, जो मार्क्सवादी आलोचकों और उस दौर के कर्ताधर्ताओं ने बनाया था. लेकिन जिस यथार्थवाद और आम आदमी की आड़ में पूरा आंदोलन चल रहा था, वही कविता से दूर होता चला गया. हम काफी देर तक उनकी बातें सुनते रहे, लेकिन अचानक मेरे दूसरे मित्र ने हस्तक्षेप किया और उन्हें रोकते हुए कहा कि वह जिस तरह से पूरे परिदृश्य का सरलीकरण या सामान्यीकरण कर रहे हैं, वह उचित नहीं है. अब दोनों थोड़े भिड़ने के अंदाज़ में बहस करने लगे. दूसरे मित्र का तर्क था कि बाद के दिनों में माहौल बदला और समाज के सामने कोई चुनौती नहीं थी, कोई बड़ा लक्ष्य नहीं था. जोश और जुनून वाले दौर में देश की आज़ादी और उसके बाद की स्थितियां ज़िम्मेदार थीं. बाद में जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया तो भी वीर रस से सराबोर कविताएं लिखी गईं. उसके बाद इमरजेंसी के दौर में नागार्जुन ने भी कई लोकप्रिय कविताएं लिखीं, जो केवल जनता की ज़ुबान पर ही नहीं चढ़ीं, बल्कि जयप्रकाश आंदोलन के दौर में आंदोलनकारियों के लिए प्रेरक भी साबित हुईं. कविता पर अच्छी बहस चल रही थी, जिसमें मैं अपनी अज्ञानता की वजह से कोई ख़ास हस्तक्षेप नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी बार-बार मेरे मन में यह सवाल उठ रहा था कि आज की कविता जनता से दूर क्यों हो गई है. इस बहस के कुछ दिनों बाद कवि मित्र तजेंद्र लूथरा का संदेश मिला कि वह अपने घर पर एक कवि गोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं, जो अनौपचारिक होगी, जिसमें कुछ कवि मित्र अपनी रचनाएं सुनाएंगे और मिल-बैठकर बातें करेंगे. कवि गोष्ठी में मेरी कभी कोई दिलचस्पी नहीं रही, लेकिन कुछ दिनों पहले कविता पर हो रही बहस और कवि मित्रों से मिलने के लोभ ने मुझसे हां करा लिया. दिल्ली के ट्रैफिक से जूझता जब मैं उनके घर पहुंचा तो कवि गोष्ठी शुरू हो चुकी थी और युवा कवि राजेंद्र शर्मा अपनी कविता का पाठ कर रहे थे. श्रोताओं में कवयित्री शबनम, बिपिन चौधरी, गोल्डी मल्होत्रा, लक्ष्मी शंकर वाजपेयी, ममता जी, बरखा सिंह, मदन कश्यप, मिथिलेश श्रीवास्तव और वरिष्ठ कवि विष्णु नागर मौजूद थे. जो श्रोता थे, वही कवि भी थे. मेरे जैसे दो लोग और थे, जो विशुद्ध रूप से श्रोता थे. वहां भी साफ़ तौर पर छंद वाली कविता और यथार्थवादी कविता का फ़र्क़ मुझे दिखा, लेकिन जिस तरह की कविताएं शबनम, गोल्डी मल्होत्रा, ममता जी और लक्ष्मी शंकर वाजपेयी ने सुनाईं, वे समस्या प्रधान होने के साथ-साथ कर्णप्रिय भी थीं. उस दिन मुझे जो एक ख़ास बात नज़र आई, वह यह कि कविता में अब आरटीआई से लेकर पीआईएल जैसे शब्दों का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है. मौजूद सभी कवियों को तीन-तीन कविताएं सुनाने की छूट थी. तजेंद्र शर्मा की कविता शब्द से बातचीत मुझे बेहद पसंद आई, दूसरी कविता लुहार का डर समाज की कई प्रवृत्तियों पर चोट करती प्रतीत हुई. इस अनौपचारिक गोष्ठी का संचालन पत्रकार, कवि एवं उपन्यासकार अरुण आदित्य कर रहे थे. उनकी कविताएं एक फूल का बायोडाटा और काग़ज़ का आत्मकथ्य बड़े सवाल तो खड़े कर ही रही थीं, समाज को हक़ीक़त का आईना भी दिखा रही थीं. दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष बरखा सिंह ने भी कुछ ग़ज़लें गाकर सुनाईं. विष्णु नागर और मदन कश्यप ने भी गंभीरता से अपनी बात अपनी कविता में कही. उसी कवि गोष्ठी के बाद राजेंद्र शर्मा ने एक छोटी सी पुस्तिका-गाथा पांवधोई की मुझे दी. घर आकर जब उसे पलटा तो जानकर ख़ुशी हुई कि सहारनपुर में स्थित पांवधोई नदी, जो कि नाले में तब्दील हो गई थी, उसका जीर्णोद्धार ज़िलाधिकारी आलोक कुमार ने स्थानीय जनता की मदद से कराया. उत्तर प्रदेश में यह अपने तरह की अनोखी पहल थी, जहां प्रशासन ने जन सहयोग से जनहित के एक काम को अंजाम देकर अपनी ऐतिहासिक विरासत को संवारा. इस एक छोटी सी घटना से अगर उत्तर प्रदेश में प्रशासन और जन सहयोग का नया अध्याय शुरू हो सके तो सूबे के लोगों के लिए बेहतर होगा.

(लेखक आईबीएन-7 से जुड़े हैं)
anant.ibn@gmail.com

शारदा सिन्हा

25 हज़ार का पुरस्कार 27 साल से इंतज़ार

अफ़ज़ल इमाम मुन्ना

मशहूर लोकगीत गायिका पद्मश्री शारदा सिन्हा को बिहार सरकार द्वारा 27 वर्ष पहले घोषित पच्चीस हज़ार रुपये की पुरस्कार राशि का आज तक बेसब्री से इंतज़ार है. सुशासन के नाम पर दूसरी पारी खेलने वाले वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस ओर अब तक ध्यान नहीं दिया है. जबकि निर्वाचन आयोग ने गत बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए शारदा सिन्हा को अपना ब्रांड एंबेसडर बनाया था. परिणाम यह हुआ कि महिलाओं ने राज्य में अमन-चैन और विकास के लिए मतदान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. नीतीश कुमार को दोबारा मुख्यमंत्री बने तीन महीने से ज़्यादा हो गए, लेकिन उन्होंने भी इस ओर अब तक कोई ध्यान नहीं दिया है.

शारदा सिन्हा ने पारंपरिक लोकगीत-संगीत को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. बल्कि उसे लोकप्रिय बनाकर मौलिक संगीत के मामले में बिहारवासियों को धनवान होने का एहसास भी कराया. शारदा सिन्हा ने स्वयं कई गीत लिखे और उन्हें अपनी आवाज़ दी. भोजपुरी कोकिला, बिहार रत्न, भोजपुरी एवं मिथिला विभूति आदि उपाधियों से सम्मानित शारदा सिन्हा को वर्ष 1991 में पद्मश्री सम्मान मिला. राजश्री प्रोडक्शन की सुपरहिट हिंदी फ़िल्म मैंने प्यार किया और हम आपके हैं कौन, भोजपुरी फिल्म सुहागन बनाम सजना हमार, माई, बोलबम एवं गंगा मइया तोहे पियरी चढ़ईबे के गीतों को उन्होंने अपनी आवाज़ दी. हाल में पटना स्थित ऐतिहासिक गांधी मैदान में महुआ चैनल द्वारा आयोजित नेस्ले सुर संग्राम-2 के मंच पर भी उन्होंने अपना कार्यक्रम पेश किया. उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है. पति डॉ. ब्रजकिशोर सिन्हा झारखंड के देवघर स्थित गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के प्राचार्य रह चुके हैं. शारदा सिन्हा देश-विदेश में सम्मान पाकर भी अपने गृह प्रदेश में ख़ुद को अपमानित महसूस कर रही हैं. साढ़े सत्ताइस वर्ष पूर्व तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्र ने उन्हें 25 हज़ार रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की थी, लेकिन नौकरशाही की अड़ंगेबाज़ी के कारण यह पुरस्कार राशि उन्हें आज तक नहीं मिल सकी. अगर यह रकम समय पर मिल गई होती और इसे उन्होंने बैंक में फिक्स डिपोज़िट कर दिया होता तो आज यह रकम लगभग दस लाख रुपये से ज़्यादा होती. शारदा सिन्हा ने कहा कि बिहार सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति के कारण राज्य के लोकगीत गायकों को बढ़ावा नहीं मिल रहा है, जबकि यहां प्रतिभाओं की कमी नहीं है. उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि लोक संगीत को बढ़ावा देने के लिए देश भर में कार्यशालाओं का आयोजन हो और अभिलेखागार खोला जाए. शारदा सिन्हा ने उभरते कलाकारों को आगाह किया कि सस्ती और तात्कालिक लोकप्रियता के लिए वे सांस्कृतिक विरासत की अनदेखी न करें. उन्होंने कहा कि लोक गायकों का दायित्व है कि वे अपनी संस्कृति को समृद्ध बनाएं. उन्हें प्रयोगधर्मी तो होना चाहिए, पर संस्कृति के भीतर के प्रदूषण को ख़त्म करने के लिए भी कोशिश करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि टीवी चैनलों की बाढ़ और कैसेट कंपनियों की गलाकाट प्रतियोगिता के चलते गायकों को न प्रशिक्षण मिल रहा है और न उनमें धैर्य है. गीतकार भी अपनी सांस्कृतिक विरासत के प्रति संजीदा नहीं रहे और वे पैरोडी पर गीत लिख रहे हैं.

ज्ञात हो कि एचएमवी कंपनी ने शारदा सिन्हा की आवाज़ में श्रद्धांजलि नामक एक एलपीजी रिकार्ड तैयार किया था, जिसमें महाकवि विद्यापति के गीत हैं. इस रिकार्ड की लोकप्रियता से प्रभावित होकर 6 जुलाई, 1983 को पटना स्थित भारतीय नृत्य

कला मंदिर में आयोजित एक समारोह में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्र ने उन्हें राज्य सरकार की ओर से 25 हज़ार रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की थी. घोषणा के कुछ ही दिनों बाद डॉ. मिश्र को मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा. डॉ. मिश्र के बाद चंद्रशेखर सिंह, बिंदेश्वरी दुबे, भगवत झा आज़ाद, सत्येंद्र नारायण सिन्हा मुख्यमंत्री बने. इसके बाद कांग्रेस की हुकूमत चली गई. वर्ष 1990 में जनता दल की सरकार बनी और भोजपुरी भाषा बोलकर लोकप्रियता हासिल करने वाले लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री के रूप में पंद्रह वर्षों तक बिहार में शासन किया, लेकिन सचिवालय की अड़ंगेबाज़ी के कारण शारदा सिन्हा पुरस्कार राशि नहीं पा सकीं. अब देखना यह है कि सुशासन के नाम पर दोबारा सत्ता हासिल करने और सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री का खिताब पाने वाले नीतीश कुमार शारदा सिन्हा की उक्त पुरस्कार राशि कब तक उनके हाथों में पहुंचा पाते हैं.

feedback@chauthiduniya.com

इस मोबाइल में चाइल्ड पोजिशनिंग इंक्वायरी, इमरजेंसी कॉल टू फादर, सिक्यूरिटी फायरवाल एवं कॉल्स एंड मैसेज कंट्रोलिंग जैसे फीचर्स जोड़े गए हैं.

न्यू ब्लैकबेरी 4-जी प्लेबुक टेबलेट्स

टेबलेट्स की दुनिया में रिम ने किया है धमाकेदार आगाज़. पॉपलुर एप्पल आईपैड से प्रतिस्पर्धा की जंग में टेबलेट बाज़ार दिन-प्रतिदिन निखरता जा रहा है. फीचर रिच गिज्मोज की मांग को ध्यान में रखते हुए रिम ने दो नए ब्लैकबेरी 4-जी प्लेबुक टेबलेट्स भारतीय बाज़ार में उतारने की घोषणा की है. ये टेबलेट्स एलटीई और एचएसपीए + हाईस्पीड वाइड एरिया वायरलेस नेटवर्क्स को सपोर्ट करती हैं. बेहद आकर्षक अल्ट्रा पोर्टेबल डिज़ाइनों में ये ब्लैकबेरी टेबलेट्स ख़ास हैं. मल्टी टास्किंग एवं मल्टी प्रोसेसिंग के साथ इसमें उम्दा स्तर के सिक्योरिटी फीचर्स भी हैं. एडोब फ्लैश को सपोर्ट करने वाली ये टेबलेट्स उच्च एवं विश्वसनीय वेब ब्राउजिंग के साथ एचडी मल्टीमीडिया को सपोर्ट करने का भरोसा भी देती हैं. बिजनेस प्रोफेशनल्स के लिए इसमें ख़ास 4-जी नेटवर्क की सुविधा भी है. ये टेबलेट्स ब्लूटुथ टीथरिंग, मोबाइल हॉट स्पॉट और ब्लैकबेरी ब्रिज को भी सपोर्ट करती हैं. इनके छह महीने के अंदर बाज़ार में आने की संभावना है.

लैपटॉप में सिम कार्ड

भारत में पहली बार पॉकेट इंटरनेट सर्विस उपलब्ध कराने वाली यह कंपनी अब कुछ लैपटॉप और टेबलेट कंप्यूटर बनाने वाली कंपनियों से इस सिलसिले में बातचीत कर रही है. एयरसेल ने इन कंपनियों से कहा है कि वे लैपटॉप और टेबलेट में सिम कार्ड लगाने की सुविधा उपलब्ध कराएं.

अब तक आप केवल मोबाइल फोन में ही सिम कार्ड का इस्तेमाल करते रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में आप लैपटॉप में भी इसका इस्तेमाल कर सकेंगे. दरअसल भारत में मोबाइल फोन सर्विस देने वाली कंपनी एयरसेल जल्द ही अपना सिम कार्ड लैपटॉप तक पहुंचाने वाली है. भारत में पहली बार पॉकेट इंटरनेट सर्विस उपलब्ध कराने वाली यह कंपनी अब कुछ लैपटॉप और टेबलेट कंप्यूटर बनाने वाली कंपनियों से इस सिलसिले में बातचीत कर रही है. एयरसेल ने इन कंपनियों से कहा है कि वे लैपटॉप और टेबलेट में सिम कार्ड लगाने की सुविधा उपलब्ध कराएं. दरअसल एयरसेल चाहती है कि उसके 3-जी सिम कार्ड के ज़रिए लैपटॉप में आसानी से इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराई जा सके. एयरसेल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर गुरदीप सिंह ने बताया कि इस सिलसिले में कई कंपनियों से बातचीत चल रही हैं. उम्मीद है कि जल्द ही यह सर्विस शुरू हो जाएगी. कंपनी को भारत में कुल 13 सर्किलों में 3-जी सेवा के लिए लाइसेंस हासिल हुआ है. ज़्यादातर शहरों में एयरसेल की 3-जी सर्विस की शुरुआत हो चुकी है. कंपनी का कहना है कि बचे हुए शहरों में भी यह सर्विस आने वाले दो हफ्तों में शुरू कर दी जाएगी.

होंडा की नई कार एकॉर्ड

डिज़ाइन, आराम एवं अन्य कई मामलों में यह संस्करण बेमिसाल है. लांच के बाद अब तक भारत में 25,000 एकॉर्ड कारें बिक चुकी हैं.

भारत में लग्जरी कारों में एक बड़ा नाम है होंडा. प्रीमियम कार निर्माता कंपनी होंडा सिएल कार्स इंडिया (एचएससीआई) ने अपनी लग्जरी कार एकॉर्ड सिडान का उन्नत संस्करण लांच किया है. 2.4 एवं 3.5 लीटर इंजन विकल्पों में इसकी क़ीमत 19.60-25.41 लाख रुपये रखी गई है. एचएससीआई के सीईओ तकाशी नगाई के अनुसार, ग्राहकों से मिली प्रतिक्रियाओं के आधार पर हम अपने मॉडलों में लगातार सुधार करते रहते हैं. एकॉर्ड का यह नया संस्करण उसी की एक कड़ी है. डिज़ाइन, आराम एवं अन्य कई मामलों में यह संस्करण बेमिसाल है. लांच के बाद अब तक भारत में 25,000 एकॉर्ड कारें बिक चुकी हैं. कंपनी ने मई 2009 में 2.4 एवं 3.5 लीटर इंजन विकल्पों में एकॉर्ड का आठवां संस्करण लांच किया था. जापान की ऑटो दिग्गज होंडा और भारत के सिएल ग्रुप के संयुक्त उपक्रम के तहत कंपनी ने अब तक 1620 करोड़ रुपये का निवेश किया है. बड़ी कार पसंद करने वालों के लिए यह बहुत शानदार विकल्प है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

बच्चों पर नज़र रखेगा मोबाइल

सीटूएक्स कम्युनिकेशंस नामक कंपनी ने बाज़ार में एक बेहद ख़ास मोबाइल फोन लांच किया है, जिसका नाम बेबी सेक्यूरिटी मोबाइल. कंपनी का दावा है कि इस मोबाइल के ज़रिए आप आसानी से अपने बच्चों पर नज़र रख सकते हैं. इसमें चाइल्ड पोजिशनिंग इंक्वायरी, इमरजेंसी कॉल टू फादर, सिक्यूरिटी फायरवाल एवं कॉल्स एंड मैसेज कंट्रोलिंग जैसे फीचर्स जोड़े गए हैं.

कंपनी का कहना है कि यह मोबाइल अगर आपके बच्चे के पास होगा तो इन फीचर्स के ज़रिए आप आसानी से किसी भी वक़्त यह पता लगा सकते हैं कि वह कहां हैं. यही नहीं, अगर आपका बच्चा किसी मुश्किल में फंस जाए तो उसके द्वारा सिर्फ़ एक बटन दबाते ही आपके पास कॉल आ जाएगी. इस ख़ास मोबाइल हैंडसेट के अलग-अलग मॉडलों की क़ीमत 1799 से लेकर 3499 रुपये तक है. कंपनी का मानना है कि इन हैंडसेट्स की क़ीमत काफी कम रखी गई है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनका फ़ायदा उठा सकें.

भारत ने 49 ओवरों में सात विकेट पर 216 रन बनाए थे और पाकिस्तान के लिए लक्ष्य हासिल करना ज़्यादा मुश्किल नहीं था.

विश्वकप और कुछ खट्टी-मीठी यादें

राजेश एस कुमार

भारत में क्रिकेट को वह दर्जा हासिल है, जो किसी भी देश के राष्ट्रीय खेल को हासिल नहीं होता. जब बात विश्वकप की हो तो यह किसी महाकुंभ से कम नहीं होता. एक ऐसा महाकुंभ, जिसमें दुनिया भर की टीमें ज़रूर शामिल होती हैं, लेकिन जो क्रेज़ भारतीय दर्शकों में दिखाई देता है, वह कहीं और नहीं. ज़ाहिर है, इतने बड़े महाकुंभ के आगाज़ से लेकर अंजाम तक कई दिलचस्प बातें हमें देखने-सुनने को मिलती हैं, लेकिन कुछ यादें ऐसी भी होती हैं, जो क्रिकेट प्रेमियों के जेहन में ऐसे निशान छोड़ जाती हैं, जो शायद ही कभी मिटते हों. कुछ यादें गुदगुदाती हैं तो कुछ चेहरे पर शिकन छोड़ जाती हैं. इस अंक में हम आपको अब तक हुए सभी विश्वकप की कुछ ऐसी ही रोचक और कड़वी यादों से रूबरू करा रहे हैं.

आपको जानकर ताज्जुब होगा कि लॉयड ने मैच जीतने के लिए कैच छोड़ा था. वेस्टइंडीज़ ने इंग्लैंड के सामने 293 रनों का लक्ष्य रखा था. रिचर्ड्स ने आख़िरी गेंद पर छक्का लगाया था. इंग्लैंड ने जवाब में धीमी शुरुआत की और बॉयकॉट ने दोहरे अंक तक पहुंचने के लिए 17 ओवर ले लिए. एक बार वह रिचर्ड्स की गेंद पर शॉट लगाने के लिए बाहर निकले तो ग़लत खेल गए और कप्तान लॉयड ने उस आसान से कैच को छोड़ दिया. उससे पहले दूसरी तरफ़ खेल रहे ब्रियरली का कैच भी वह छोड़ चुके थे. रिचर्ड्स को लॉयड ने जब बताया कि उन्होंने जानबूझ कर कैच छोड़ा था तो उन्हें चैन मिला. लॉयड के मुताबिक़, हम दिन भर उन दोनों को खेलते देख सकते थे, क्योंकि जितने ओवर वे खेल रहे थे, उतनी कीलें उनके ताबूत में लग रही थीं. बहरहाल लॉयड ने बाद में कहा कि उन्होंने जानबूझ कर कैच नहीं छोड़ा था, क्योंकि यह मैच जीतने की एक ख़राब तकनीक थी.

ऐसी ही एक और दिलचस्प घटना पहले विश्वकप की है. पाकिस्तान और वेस्टइंडीज़ के बीच मैच था. पाकिस्तान ने सात विकेट पर 266 रन बनाए थे. माजिद ख़ान, मुश्ताक़ मोहम्मद और वसीम राजा ने अर्द्ध शतक लगाए थे. जब वेस्टइंडीज़ की पारी शुरू हुई तो सरफ़राज़ नवाज़ की तूफ़ानी गेंदबाज़ी के सामने वेस्टइंडीज़ का कोई खिलाड़ी जमकर नहीं खेल सका. 166 रनों पर वेस्टइंडीज़ का आठवां विकेट गिर चुका था. वेस्टइंडीज़ लगभग मैच हार चुकी थी. अपील पर अपील जारी थी कि 203 रनों पर नवां विकेट गिर गया और होल्डर का विकेट भी सरफ़राज़ ने ले लिया. सातवें नंबर पर बल्लेबाज़ी करने आए डेरेक मरे सिर्फ़ टिके हुए थे और उनका साथ दे रहे थे एंडी रॉबर्ट्स और दोनों ने मिलकर आख़िरी विकेट के लिए 64 रनों की नाबाद पारी खेली. इस तरह से पाकिस्तान सेमी फ़ाइनल में प्रवेश करने से रह गया और वेस्टइंडीज़ ने आगे चलकर विश्वकप में ख़िताबी जीत हासिल की. डेरेक मरे की वह पारी वनडे में उनकी बेहतरीन पारी रही और दसवें विकेट की वह विश्वकप की सबसे बड़ी साझेदारी रही, लेकिन पाकिस्तान को दो गेंद रहते इस मैच का हारना बहुत दिनों तक सालता रहा.

1992 के विश्वकप में पहली बार दक्षिण अफ्रीका की टीम प्रतिबंध के बाद उतरी थी, जिससे क्रिकेट जगत में एक नया उत्साह था और दूसरी टीमों में एक तरह का संकोच भी था कि न जाने उनकी टीम कैसी है. दक्षिण अफ्रीका ने धमाकेदार खेल दिखाया और सेमी फ़ाइनल में प्रवेश किया. विवाद की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के मौसम और क्रिकेट के डकवर्थ लुइस नियम ने दक्षिण अफ्रीका को जो नुक़सान पहुंचाया, उसे कोई नहीं भूला. इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका का मैच था. खेल 10 मिनट देर से शुरू हुआ और लंच में से यह समय काट लिया गया, लेकिन कोई ओवर नहीं काटा गया. उसके बाद स्थानीय समयानुसार जब इंग्लैंड की पारी 6.10 तक ख़त्म नहीं हो सकी तो उसकी पारी में से ओवर कम कर दिए गए और मैच हो गया 45 ओवरों का, जिसमें इंग्लैंड ने 252 रन बनाए. दक्षिण अफ्रीका ने खेल शुरू किया और वह 42.5 ओवरों में छह विकेट के नुक़सान पर 231 रनों पर पहुंच गया. लेकिन फिर डकवर्थ लुइस नियम लागू हुआ और जब दोबारा खेल शुरू हुआ तो दक्षिण अफ्रीका को एक गेंद पर 21 रन बनाने थे और स्कोर बोर्ड पर जब यह लिखा आया तो पता चला कि दक्षिण अफ्रीका मैच हार चुका है, बस औपचारिकता ही बची है. दक्षिण अफ्रीका इतिहास रचने से वंचित हो चुका था.

एक और घटना. जावेद मियांदाद और विवाद एक-दूसरे के पर्याय बन चुके थे. बात है 1992 के विश्वकप में भारत-पाकिस्तान मैच की. यह एक तथ्य है कि विश्वकप में पाकिस्तान भारत से कभी नहीं जीता, हालांकि ज़्यादा मैच जीतने का रिकार्ड पाकिस्तान के नाम है. जब इन दोनों देशों के बीच मैच हो रहा होता है तो खिलाड़ी ज़बरदस्त दबाव में रहते हैं. यहां तक कि दर्शकों में भी यह दबाव महसूस किया जाता है. यह विश्वकप का 16वां मैच था. भारत ने 49 ओवरों में सात विकेट पर 216 रन बनाए थे और पाकिस्तान के लिए लक्ष्य हासिल करना ज़्यादा मुश्किल नहीं था. आमिर सुहैल और जावेद मियांदाद ने पाकिस्तान का स्कोर दो विकेटों के नुक़सान पर 100 के पार पहुंचा दिया था, फिर अचानक पाकिस्तान के विकेट गिरने शुरू हो गए. मोरे विकेट के पीछे बार-बार उछल-उछल कर अपील कर रहे थे. मियांदाद पर दबाव बढ़ता जा रहा था और उसे ख़त्म करने के लिए अचानक मियांदाद ने मोरे से कुछ कहा और फिर मोरे की तरह कूद कर नक़ल उतारने लगे. ऐसा दृश्य पहले किसी ने नहीं देखा था. पश्चिमी मीडिया ने दूसरे दिन जंपिंग जावेद के नाम से ख़बर छापी. 1996 का विश्वकप भी कई मायनों में विवादों भरा रहा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने सुरक्षा कारणों से श्रीलंका जाने से इंकार कर दिया और श्रीलंका को बिना मैच खेले ही विजयी घोषित कर दिया गया. बहरहाल श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया की फ़ाइनल में लाहौर में भिड़ंत हुई और श्रीलंका ने आसानी के साथ विश्वकप जीत लिया.

बात 1999 के विश्वकप की. दक्षिण अफ्रीका ने भारत के विरुद्ध अपने पहले मैच में रेडियो सिस्टम का प्रयोग किया. उसके कप्तान और तेज़ गेंदबाज़ एलन डोनाल्ड के पास माइक्रोफ़ोन थे और वह पवेलियन में मौजूद अपने कोच बॉब वूल्मर के साथ जुड़े हुए थे. बॉब उन दोनों को ड्रेसिंग रूम से ही गाइड कर रहे थे. पानी के लिए हुए ब्रेक में मैच रेफ़री बीच में आया और बाद में आईसीसी ने उस तरीक़े को अपनाने का विरोध कर उससे खड़े विवाद को ख़त्म कर दिया. 2007 का विश्वकप क्रिकेट की सबसे दुखद घटना का साक्षी है. पाकिस्तान के दक्षिण अफ्रीकी कोच बॉब वूल्मर होटल में अपने कमरे में मृत पाए गए और वह भी पाकिस्तान की शर्मनाक हार और विश्वकप से विदाई की रात को. इससे पहले ही पाकिस्तान पर मैच फ़िक्सिंग का आरोप था और कई खिलाड़ियों को सज़ा भी दी गई थी. जमैका पुलिस ने हत्या का संदेह ज़ाहिर किया, पाकिस्तानी खिलाड़ियों के मैच फ़िक्सिंग में फंसे होने की आशंका जताई जाने लगी और उनसे अलग-अलग पूछताछ होने लगी. दूसरी ओर भारत भी बांग्लादेश से मैच हारकर विश्वकप के पहले दौर से ही बाहर हो गया और वह भी ऐसे समय में, जबकि उसे विश्वकप का दावेदार माना जा रहा था. बहरहाल पाकिस्तानी खिलाड़ियों को इस मामले में क्लीन चिट दे दी गई और जमैका पुलिस ने यह कहकर मामला बंद कर दिया कि बॉब वूल्मर की मौत सामान्य थी और उनकी हत्या नहीं की गई थी. तरह-तरह की अफ़वाहें फैलीं और पूरे उपमहाद्वीप की दिलचस्पी क्रिकेट विश्वकप में कम हो गई, क्योंकि पसंद की टीमें तो बाहर ही हो चुकी थीं. फिर भी जब कभी 2007 के विश्वकप की बात होगी, लोगों के मन में यह सवाल ज़रूर उभरेगा कि भारत और पाकिस्तान की टीमों ने कहीं मैच तो नहीं फ़िक्स किया था.

rajeshsy@chauthiduniya.com

टॉप टेन फ्लैशबैक

1. विश्वकप की शानदार पारियों में से एक 1983 में कपिल देव की 175 रनों की नाबाद पारी की न वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है और न ऑडियो कमेंट्री. बताते हैं कि कैमरामैन हड़ताल पर थे.
2. विश्वकप में सबसे स्लो स्पीड से रन बनाने का रिकॉर्ड सुनील गावस्कर के नाम है. उन्होंने वर्ष 1975 के पहले विश्वकप में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 174 गेंदों का सामना करते हुए सिर्फ़ 36 रन बनाए थे. इसमें उनका सिर्फ़ एक चौका शामिल था. उस समय 60-60 ओवरों का मैच होता था.
3. एक ही विश्वकप में सबसे ज़्यादा शून्य पर आउट होने का (चार बार) रिकॉर्ड एबी डीवेलियर्स (दक्षिण अफ्रीका) के नाम है.
4. पहले तीनों विश्वकप इंग्लैंड में आयोजित हुए थे.
5. विवियन रिचर्ड्स ऐसे अकेले क्रिकेटर हैं, जिन्होंने विश्वकप क्रिकेट के साथ-साथ विश्वकप फुटबॉल में भी हिस्सा लिया. वह विश्वकप फुटबॉल में एंटिगा की ओर से खेले थे.
6. 1996 के विश्वकप में ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज़ ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए श्रीलंका में खेलने से इंकार कर दिया. ये दोनों मैच श्रीलंका के हक़ में गए. इसी विश्वकप के सेमी फ़ाइनल में भारत और श्रीलंका के बीच मुक़ाबला हुआ, लेकिन दर्शकों के ख़राब व्यवहार केकारण यह मैच भी श्रीलंका की झोली में गया. हालांकि श्रीलंका का उस समय जीतना तय था.
7. एंडरसन कमिंस ने वर्ष 1992 में वेस्टइंडीज़ और वर्ष 2007 में कनाडा की ओर से विश्वकप खेला. उनसे पहले कैपलर वेसल्स ने वर्ष 1983 में ऑस्ट्रेलिया और 1992 में दक्षिण अफ्रीका की ओर से विश्वकप के मैच खेले.
8. किसी भी विश्वकप में सबसे ज़्यादा बार शून्य पर आउट होने का रिकॉर्ड न्यूज़ीलैंड के नाथन एस्टल और एजाज़ अहमद के नाम दर्ज है. दोनों खिलाड़ी पांच-पांच बार शून्य पर आउट हो चुके हैं.
9. दक्षिण अफ्रीका के हर्शेल गिब्स विश्वकप के एक मैच में एक ओवर में छह छक्के मारने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं. यह कारनामा उन्होंने 2007 के विश्वकप में नीदरलैंड के ख़िलाफ़ किया था.
10. इतिहास में सबसे कम स्कोर वाला विश्वकप वर्ष 1979 का था. इसमें सिर्फ़ दो शतक लगे थे.

Now, mixing business with pleasure makes perfect business sense.

FORTUNE Inn Grazia BY WELCOMGROUP Noida

Welcome to Fortune Inn Grazia, Noida - an elegant, upscale, full-service business hotel. It is strategically located in the heart of the city and in close proximity to Sector 18, the commercial and shopping hub of Noida. The hotel offers everything from contemporary accommodation and exciting dining options to, of course, comprehensive facilities for business and leisure. All to meet the growing needs of the new-age business traveller.

Block-I, Plot No. 1A, Sector-27, Noida - 201301, Uttar Pradesh, India. Tel: 0120-3988444, Fax: 0120-3380144, E-mail: grazia@fortunehotels.in, Website: www.fortunehotels.in

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. DELHIN/2009/30467

स्टाइल, आउटफ़िट और अपीयरेंस के ज़रिए युवाओं में कांफिडेंस भरने का श्रेय बॉलीवुड को दिया जाना चाहिए. दौर कोई भी हो, बॉलीवुड ने फ़ैशन ट्रेंड सेट करने का काम हमेशा से किया है.

सोनम का रॉक स्टार लुक

हर तरह के जॉनर पर काम कर चुकी सोनम अब रॉक स्टार लुक में नई फिल्म करने वाली हैं. फिल्म में उनके साथ होंगी बिपाशा बसु. फिट बॉडी, सेंसुअल लुक्स और किलिंग एटीट्यूड लेकर बिपाशा बेशक इस तरह के लुक को जस्टिफाई करती हैं, लेकिन द स्वीट गर्ल सोनम कपूर को बहुत सारी तैयारी करनी होगी इस तरह के क्रेजी लुक को अपनाने के लिए. वैसे तो सोनम मेहनती हैं और इस लुक के लिए वह मेहनत भी कर रही होंगी, लेकिन क्या है इनकी मेहनत, क्या-क्या तैयारी की है उन्होंने शूट के लिए? सबसे अहम सवाल यह है कि बिपाशा की अथेटिक बॉडी को किस तरह से मैनेज करेंगी? दरअसल यह लुक सोनम अपना रही हैं अब्बास मस्तान की फिल्म प्लेयर्स में, जिसमें उनके कुछ एक्शन सीन हैं और उन्हें कोरियोग्राफ किया है अल्लाह अमीन ने. इस फिल्म में उन्होंने स्पीडिंग बोट और स्पीडिंग कार में भी शूट किया है. इसके लिए सोनम पिछले कुछ महीनों से यास्मीन कराचीवाला से ट्रेनिंग ले रही थीं. सुनने में आया है कि सोनम अपनी ट्रेनिंग के लिए इतनी सीरियस थीं कि वह अपने ट्रेनर को भी शूटिंग पर गोवा ले गई थीं. इस फिल्म में उनके साथ होंगे अभिषेक बच्चन, नील नितिन मुकेश और बॉबी देओल. जल्द ही सोनम कॉमेडी करती हुई अनीस बज्मी की फिल्म थैंक्यू में भी नज़र आएंगी. इसमें एवरग्रीन रेखा पर फिल्माए गए गीत प्यार दो प्यार लो के रीमिक्स वर्जन में अक्षय कुमार, बॉबी देओल, इरफ़ान ख़ान और सुनील शेट्टी नज़र आएंगे. थैंक्यू रोमांटिक कॉमेडी है, जिसमें सोनम प्ले कर रही हैं एक युवा टेनिस प्लेयर का किरदार, जो एक प्लेब्वॉय अक्षय कपूर के प्यार में पड़ जाती है. इसके अलावा सोनम शाहिद कपूर के साथ पंकज कपूर की फिल्म मौसम में नज़र आने वाली हैं.

बॉलीवुड ही फैशन का ट्रेंड बदलता है

रीतिका सोनाली

स्टाइल, आउटफ़िट और अपीयरेंस के ज़रिए युवाओं में कॉफिडेंस भरने का श्रेय बॉलीवुड को दिया जाना चाहिए. दौर कोई भी हो बॉलीवुड ने फ़ैशन ट्रेंड सेट करने का काम हमेशा से किया है. पिछले कई दशकों से सिनेमा फ़ैशन का ट्रेंड सेट करता रहा है. जहां अमर प्रेम की पुष्पा यानी शर्मिला टैगोर के पफ़ स्लीव ब्लाउज़ और मुमताज़ के साड़ी पहनने के ख़ास अंदाज़ ने फ़ैशन को हिंदुस्तानी रूप दिया तो परवीन बॉबी और ज़ीनत अमान के ग्लैमरस स्टाइल में पाश्चात्य रंग दिखा. सिर्फ़ कपड़े ही नहीं हेयर स्टाइल का भी फ़ैशन फ़िल्मों के हिसाब से ही लोगों के सिर चढ़ता है, चाहे वह शम्मी कपूर का मोप स्टाइल हो या साधना कट हो. बॉलीवुड के ये फ़ैशन ट्रेंड सितारों द्वारा लोगों तक पहुंचाए जाते रहे हैं, जो फ़िल्म स्टार जितना लोकप्रिय होता है उतना ही ज़्यादा लोकप्रिय उसका स्टाइल होता है. लेकिन जिस डिज़ाइनर या स्टाइलिस्ट की वजह से ट्रेंड इतना लोकप्रिय होता है, उसका नाम लोगों की ज़ुबां से ग़ायब रहता है. शायद ही कोई यह बता पाए कि बहुत ही लोकप्रिय शर्मिला टैगोर के चिड़िया का घोंसला हेयर स्टाइल किसने बनाया था. हरे रामा-हरे कृष्णा गीत में ज़ीनत के जिस रूप ने कॉलेज में युवाओं के बीच धमाल मचा दिया था, वह किस मेकअप आर्टिस्ट ने स्टाइल किया था. देश में धूम मचाने वाले डिज़ाइनर्स को फ़िल्म के क्रेडिट लाइन के अलावा कहीं भी जगह नहीं दी जाती थी. मनी रबादी, लीना दारू और भानु अथैया को कितने लोग जानते होंगे. भानु अथैया को 1982 में अटर्नबॉरो की फ़िल्म गांधी के कॉस्टयूम डिज़ाइनिंग के लिए ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था, लेकिन यह कम ही लोग जानते होंगे कि बॉबी की चेक्स वाली फ्रॉक्स भी उन्होंने ही डिज़ाइन की थी. भानु फ़िल्म इंडस्ट्री की सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित और पुरानी कॉस्टयूम डिज़ाइनर हैं. 1953 में राज कपूर एवं गुरुदत्त से लेकर आशुतोष गोवारीकर तक वह स्टार्स के लिए कॉस्टयूम डिज़ायन करती आई हैं. ऐसे कई नाम हैं जिनके डिज़ाइन तो काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं, लेकिन उनके साथ उनका नाम नहीं जुड़ा है. अन्ना सिंह द्वारा डिज़ाइन किए गए हम आपके हैं कौन फ़िल्म में माधुरी दीक्षित द्वारा पहनी गई ब्लू साड़ी और ग्रीन व्हाइट के कॉम्बिनेशन की घाघरा चोली शादियों में देखने को मिलने लगी, लेकिन इसकी डिज़ाइनर को शायद ही कोई जानता होगा. लेकिन अब नीता लुल्ला, मनीष मल्होत्रा, अर्जुन भसीन और भी कितने डिज़ाइनर्स हैं जिनकी लोकप्रियता लोगों के सर चढ़कर बोल रही है. दरअसल 1990 के बाद फ़ैशन और फिल्म इंडस्ट्री ने करवट ली है. 80 के दशक के अंतिम वक़्त में फ़ैशन डिज़ाइनर का उदय भारत में हुआ. इस दौर में सोसायटी मैग्ज़ीनों में अब तक केवल सितारों के लिए रिज़र्व सेलेब्रिटी स्टेटस पाकर रोहित खोसला, अबु जानी, संदीप खोसला और हेमंत त्रिवेदी जैसे डिज़ाइनर्स काफ़ी प्रसन्न हुए, तभी इस क्षेत्र में कैरियर पर ध्यान दिया गया और सन 1987 में दिल्ली में पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ फ़ैशन टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई. इसके बाद उदारवाद ने विदेशी सौंदर्य प्रसाधन बनाने वाली कंपनियों को भारत आने का मौक़ा दिया और विदेशी कंपनियों ने भारत में छिपे फ़ैशन के बाज़ार को पहचाना. इसके बाद ऐश्वर्य राय और सुष्मिता सेन के मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स बनने पर दुनिया में भारतीय सौंदर्य की पहचान हुई. 1990 में देश में केबल टेलीविज़न आने से हॉलीवुड सिनेमा, सिकॉम, एमटीवी, संटा बार्बरा, द बोल्ड एंड ब्यूटीफुल जैसे टीवी शोज़ के ग्लैमर से आकर्षित होते दर्शकों को देखकर फ़िल्म इंडस्ट्री पर भी अपनी साख बचाने का ज़िम्मा आ गया. 90 के दशक में फ़िल्मों में गाने एक छोटे फ़ैशन शो की तरह होते थे, जिसमें ढेर सारे कॉस्टयूम, अलग-अलग मेकअप, स्टाइल आदि होता था. इसके बाद करण जौहर की फ़िल्मों ने फ़ैशन, स्टाइल और ट्रेंड का नया स्टेटस लोगों के सामने रखा. निफ्ट में एडमिशन नहीं पा सकने वाले मनीष मल्होत्रा ने फ़िल्मों में कंटीन्यूटी ऑफ़ लुक का मंत्र डाला और तब से ही वह इस इंडस्ट्री के बेताज बादशाह हो गए. अब फ़िल्म इंडस्ट्री फ़ैशन डिज़ाइनर पर इस क़द्र आश्रित है कि डिज़ाइनर फ़िल्म के डायरेक्टर के साथ बैठकर स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और हर कैरेक्टर को कपड़ों के ज़रिए सटीक दिखाने की कोशिश करते हैं. सब्या साक्षी मुखर्जी, तरूण तहिलानी, शांतनु व निखिल, रॉकी एस., विक्रम फ़डनीस, सुरीली गोयल, रीतु बेरी जैसे डिज़ाइनर्स मेन स्ट्रीम सिनेमा में अपनी धाक जमा चुके हैं. सिर्फ़ फिल्मी कैरेक्टर ही नहीं फ़िल्म इंडस्ट्री में स्टार्स हर मौक़े पर पहनने के लिए अपनी रीयल लाइफ़ में ड्रेस डिज़ाइन करवाने के लिए फ़ैशन डिज़ाइनर रखते हैं. चाहे कोई पार्टी हो या पब्लिक इवेंट, कोई शो हो या फ़ैमिली ओकेज़न, स्टार्स अपने डिज़ाइनर के डिज़ाइन किए हुए कपड़े ही पहनते हैं. यही वजह है कि फ़ैशन के हर प्लेटफ़ॉर्म पर जहां भी नज़र जाए, एक मुस्कराता हुआ बॉलीवुड का चिर परिचित चेहरा चमकता हुआ दिखाई देता है. फ़ैशन शो, फ़ैशन मैग्ज़ीन, मैग्ज़ीन कवर, स्टेज शो, रैंप शो जिधर भी निगाहें जाती हैं कोई न कोई बॉलीवुड स्टार किसी न किसी डिज़ाइनर के लिए रैम्प पर जलवे बिखेरता नज़र आता है. इन स्टार्स के ज़रिए डिज़ाइनर्स अपने लेटेस्ट फ़ैशन ट्रेंड को लोकप्रिय बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बॉलीवुड और इसके सितारे बाज़ार के हर वर्ग पर क़ब्ज़ा करने में कामयाब हैं.

ritika@chauthiduniya.com

प्रीव्यू

हैप्पी हसबैंड्स

सामाजिक पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म हैप्पी हसबैंड्स कहानी है पतियों की, पति होने पर जीवन के प्रति उनके दर्शन की. शादी के बाद अपने व्यक्तिगत स्तर पर वे किन हालात का सामना करते हैं. स्लैपस्टिक कॉमेडी न होकर यह जीवन का फ़लसफ़ा है. कुछ पति जीवन से प्यार करते हैं और कुछ अपनी पत्नी से, लेकिन जो खुशमिज़ाज पति होते हैं, वे अपनी पत्नी और जीवन दोनों से प्यार करते हैं. पतियों के बारे में यह एक शानदार फिल्म है. इसका ट्रीटमेंट शानदार और दिलचस्प है. सभी उम्र के दर्शक आसानी से फिल्म के साथ खुद को रिलेट कर सकेंगे. यह फिल्म फिनोमेनल क्राफ्ट्स बैनर के तली बनी है, जिसके प्रोड्यूसर हैं सुरेश शर्मा. फिल्म का निर्देशन किया है अनय ने, जो फिल्म में लीड कैरेक्टर में नज़र आएंगे. अनय के अलावा फिल्म में कुरूश देबु, मोहित घई, अहवान एवं अर्चना भी हैं. संगीत निर्देशन, संवाद लेखन, स्क्रीन प्ले एवं कॉस्टयूम डिजायनिंग आदि जिम्मेदारी खुद अनय ने संभाली है. फिल्म के साउंड डिजायनर बूटा सिंह हैं, जबकि गीतों को अपनी आवाज से सजाया है अनय, सुनिधि चौहान, जावेद अली, नरेश अय्यर, हमजा फरोखी एवं यर्ल ने. फिल्म के सिनेमेटोग्राफर श्रीकांत नरोज हैं. फिल्म निर्माण की ज़िम्मेदारी अनय ने खुद काफ़ी मेहनत करके पूरी की है. हालांकि इस क्षेत्र में अनय का काम नया है, लेकिन अच्छी स्क्रिप्ट और अच्छे प्रस्तुतिकरण की वजह से यह फिल्म लोगों को पसंद आ सकती है. बॉलीवुड के इतिहास में ऐसे कई उदाहरण देखने को मिले हैं.

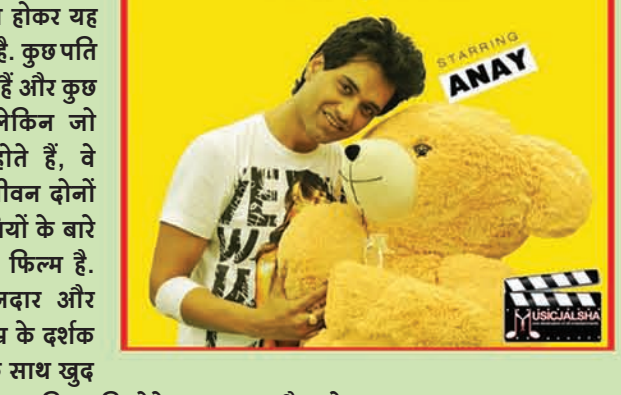

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

Your prosperity
Our guarantee

Highest NAV of 100 months guaranteed*

*Highest NAV over the first 100 months or NAV at maturity, whichever is higher
• Premium Paying Term: Single or 5 years • Policy Term: 10 years
• Age at entry: 8 yrs to 65 yrs • Partial withdrawal facility available
Available for maximum 3 months only from the date of launch

LIC's Samridhi PLUS
UIN: 512L265V01 Table No.804
UNIT LINKED INSURANCE PLAN

LIC
भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

Contact your nearest Branch or LIC agent for more information.
www.licindia.in

LIC/10-11/43

The premiums paid in Unit Linked Insurance Policies are subject to investment risks associated with capital markets and the NAV of the units may go up or down based on the performance of the fund and factors influencing the capital market and the insured is responsible for his/her decisions. The Life Insurance Corporation of India is only the name of the insurance company and Samridhi Plus is only the name of the unit linked insurance contract and does not in any way indicate the quality of the contract, its future prospects or returns. Past performance may not be an indicator of the future performance. In this policy the investment risk in investment portfolio is borne by the policyholder. For more details on risk factors, terms and conditions, please read sales brochure carefully before concluding a sale. A charge of 0.40% p.a. of the fund value shall be levied for the cost of investment guarantee. Insurance is the subject matter of solicitation.

चौथी दुनिया

बिहार झारखंड

दिल्ली, 21 मार्च-27 मार्च 2011

www.chauthiduniya.com

"संजीवनी का है ऐलान,
झारखण्ड-बिहार में हो सबका मकान"

Website : sanjeevanibuildcon.in

PLOT

BUNGALOW

DUPLEX

AISHWARIYA RESIDENCY
Argora-Kathalmore Road, Ranchi
PLOT 6 LAC | DUPLEX 18 LAC

SANJEEVANI HIGHWAY
Ranchi Patna Highway Road
PLOT 3 LAC | BUNGLOW 10 LAC

THE DYNASTY
Sidhu Kanhu Park, Kanke Road
PLOT 13 LAC | DUPLEX 25 LAC

SANJEEVANI TOWNSHIP
4 Lane, Kanke Road, Ranchi
PLOT 3 LAC | BUNGLOW 10 LAC

9973959681
9471356199
9431190351
9472727767
9471527830

स्वामी सहजानंद सरस्वती जयंती समारोह

कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना

सरोज सिंह

स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती के बहाने ब्रह्मर्षि समुदाय से आने वाले राजनीतिक प्राणियों के बीच अपनी सियासी औक़ात प्रदर्शित कर अपना उल्लू सीधा करने की होड़ मच जाती है. किसी को भी यह सुनहरा मौक़ा ज़ाया होने देना गवारा नहीं होता है. इसलिए स्वामीजी के नाम पर तरह-तरह के संगठन कुकुरमुत्ते की तरह रातों-रात उग जाते हैं. इसके बैनर तले भीड़तंत्र का भौंडा प्रदर्शन कर मज़ाक़िया अंदाज़ में लोकतंत्र का मज़ा लूटने में सियासी पाठशाला के नौसिखिया से लेकर धुरंधर तक पूरी तरह मशगूल नज़र आने लगते हैं. जातीय मठाधीशी हासिल करने की नीयत से स्वामी सहजानंद सरस्वती के सपनों को साकार करने की क़समें खाई जाती हैं. हालांकि उनके सपनों से सियासी बहुरूपियों का कोई सरोकार नहीं है. आम राय है कि ऐसे सियासतदां को स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में पूरी जानकारी भी नहीं है. प्रख्यात जनकवि आलोक धन्वा कहते हैं कि स्वामी जी की विपरीत विचारधारा के लोग उनकी जयंती मना, उनके साथ अपनी तस्वीर लगा अपना निजी स्वार्थसिद्ध कर रहे हैं. यह स्वामी जी का अपमान है.

कुछ लोग तो ऐसे हैं, जो पेशेवराना अंदाज़ में उनकी जयंती और पुण्यतिथि मनाते रहे हैं. वे काफ़ी शिद्दत से इन कार्यक्रमों से जुड़े रहे हैं. कांग्रेस के दिग्गज महाचंद्र प्रसाद सिंह, नीतीश कुमार के पुराने चाणक्य पूर्व सांसद डॉ. अरुण कुमार, लालू प्रसाद के बह्मर्षि सिपहसालार डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह वग़ैरह की सियासी उड़ान में स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती-पुण्यतिथि का बड़ा योगदान रहा है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में सिर्फ़ उन्हें भुनाने की ही नीयत रही. इस बिनाह पर सत्ता-समीकरण के तहत राजनीतिक हैसियत हासिल करने के बाद स्वामी सहजानंद सरस्वती के ये स्वयंभू अनुयायी बड़े ही सुविधाभोगी एवं अवसरवादी तथा पदलोलुप साबित हुए. जदयू के प्रदेश महासचिव चंद्रभूषण राय कहते हैं कि स्वामी जी जीवनभर ज़मींदारों के अन्याय के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते रहे. दलित दमित और पिछड़े तबक़े को इस अन्याय से मुक्ति दिलाने के लिए संघर्षरत रहे, लेकिन आज ज़मींदारों से भी अत्याचारी नवधनाढ्य माफ़िया स्वामीजी की जयंती मनाता है, यह हस्यास्पद ही है. उनकी मानें तो नीतीश कुमार ही स्वामी सहजानंद सरस्वती के सच्चे वारिस हैं, जिनके कार्यकाल में उनकी आदमक़द प्रतिमा पटना में लगी. वहीं वह स्वामीजी के सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए पीड़ित रैयत महादलित, अतिपिछड़ा एवं निर्धन सवर्ण की पीड़ा के निवारण के लिए समग्र प्रयास कर रहे हैं.

कांटी विधानसभा क्षेत्र के जदयू विधायक अजीत कुमार ने इस बार जयंती पर राजनीतिक जलसा आयोजित करने के सिलसिले का आगाज़ किया. उन्होंने सर गणेशदत्त सेवा संस्थान नामक सामाजिक संगठन के बैनर तले इसका आयोजन किया. इस कार्यक्रम की धुरी थे राज्य के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री भाजपा नेता चंद्रमोहन राय और प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता सुधीर शर्मा. इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की उपस्थिति महत्वपूर्ण थी. जानकारों की राय है कि अजीत कुमार ने अपनी राजनीतिक दुकान को चमकाने की नीयत से यह दरियादिली दिखाई थी. जदयू के राजनीतिक पटल से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ललन सिंह और प्रभावशाली पूर्व सांसद डॉ. अरुण कुमार के पटाक्षेप के बाद उन्हें अपने लिए अवसर नज़र आ रहा है. हालांकि जदयू के विधान पार्षद नीरज कुमार ऐसा प्रयास कर चुके हैं, लेकिन इनकी मंशा फलीभूत नहीं हुई थी. उल्लेखनीय है कि नीतीश सरकार के प्रथम कार्यकाल में जब अजीत कुमार को मंत्रिपरिषद से बाहर किया गया था, तब वह ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से व्यवस्था की चूलें हिलाने का दावा कर अपने बाग़ी तेवर का इज़हार करते थे. अब वही अजीत कुमार ऐसे ही आयोजन में नीतीश गुणगान में पूरी तरह डूबे दिखाई दिए. पार्टी जनों की राय है कि इसका फल कम से कम मंत्री पद के रूप में मिलने की उन्हें आस है.

एक दूसरा आयोजन प्रदेश भाजपा द्वारा किया गया. पार्टी सूत्रों की मानें तो आधिकारिक तौर पर भाजपा की ओर से पहली बार यह आयोजन किया गया था. इस कवायद के पीछे मंशा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ. सीपी ठाकुर के पुत्र विवेक ठाकुर को सियासत में स्थापित करना बताया जाता है. राज्य में भाजपा के एक ओहदेदार की मानें तो गत विधानसभा चुनाव के वक्त पुत्र विवेक ठाकुर को बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से पार्टी टिकट दिलवाने के नाम पर बड़ा बवाल खड़ा हुआ था. उस वक्त डॉ. सीपी ठाकुर ने भी प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफ़ा देकर अपनी नाराज़गी का इज़हार किया था, तब केंद्रीय नेतृत्व ने उनके पुत्र विवेक ठाकुर को चुनाव बाद विधान पार्षद मनोनीत करने का भरोसा दिलाया था. अब जबकि विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा काफ़ी मज़बूत होकर उभरी है, तब कई दिग्गज एमएलसी बनने की लाइन में लग गए हैं. इसमें कभी डॉ. सीपी ठाकुर के प्रियपात्र रहे प्रदेश प्रवक्ता सुधीर शर्मा भी हैं. ऐसे में अपनी सियासी शक्ति के प्रदर्शन के लिए सहजानंद जयंती का इस्तेमाल किया गया. इस समारोह में मंच की अध्यक्षता प्रदेशाध्यक्ष कर रहे थे, वहीं उनके पुत्र विवेक ठाकुर स्वागताध्यक्ष थे. इस आयोजन में राज्य भाजपा के कई वरीय नेता उपस्थित थे. इसके बावजूद किसी सांगठनिक पद पर पदारूढ़ न होने के बाद भी विवेक ठाकुर को ख़ासा महत्व दिया गया था, जबकि वहां मंचस्थ कई दिग्गज नेताओं एवं पार्टी सांसदों को इतनी महत्ता नहीं मिली थी. नवादा के सांसद ओजस्वी वक्ता भोला सिंह, कटिहार के सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री निखिल कुमार चौधरी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राधामोहन सिंह एवं स्वयं प्रदेश भाजपा के भीष्म पितामह कैलाशपति मिश्रा आदि कई वरीय नेताओं की मौजूदगी के बावजूद माना जा रहा है कि यह कार्यक्रम पूरी तरह विवेक ठाकुर को समर्पित था. इस आयोजन में डॉ. सीपी ठाकुर के पीछे लामबंद थे पार्टी के प्रदेश महामंत्री रजनीश कुमार. पांच साल पहले भाजपा में क़दम रखने वाले रजनीश कुमार इन्हीं की कृपा से एक झटके में इतनी लंबी छलांग लगाने में सफल रहे. बेगूसराय स्थानीय निकाय क्षेत्र से विधान पार्षद रजनीश वहां के चर्चित बाहुबली रतन सिंह के दामाद हैं. एक दिग्गज भाजपाई कहते हैं कि मात्र बेगूसराय इकाई में पंचायतीराज सेल के अध्यक्ष रहे व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष ने एक झटके में प्रदेश संगठन का महामंत्री बना दिया. प्रदेश अध्यक्ष की मनमानी का परिणाम था कि बग़ैर किसी आधार के उनके पुत्र विवेक ठाकुर बांकीपुर से चुनाव लड़ने को उतारू हो गए थे, जबकि उन्हीं की ज़िद के कारण नवंबर 2005 के चुनाव ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र से निष्ठावान एवं दमदार प्रत्याशी नर्मदेश्वर तिवारी का टिकट कटवा कर विवेक ठाकुर चुनाव लड़ गए थे और इस सीट से पार्टी को हाथ धोना पड़ा था.

इस बीच एक और आयोजन स्वामी सहजानंद जयंती के अवसर पर हुआ. यह लोजपा का कार्यक्रम था. इसके शिल्पी थे छात्र लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोहित कुमार सिंह. इस कार्यक्रम में शरीक हुए थे लोजपा सुप्रीमो रामविलास पासवान, पूर्व सांसद सूरजभान और युवा लोजपा नेता सिद्धार्थ. वैसे सिद्धार्थ भी चर्चित शिशुरोग विशेषज्ञ डॉ. उत्पलकांत के चश्मे-चिराग़ हैं. स्पष्ट है कि यह महानुभाव किस मंशा से कैसी जयंती मनाते होंगे. हालांकि रोहित कुमार सिंह इसका प्रतिवाद करते हुए कहते हैं कि रामविलास पासवान ही वह नेता हैं, जिन्होंने बतौर केंद्रीय संचार मंत्री पहली बार स्वामी सहजानंद सरस्वती पर डाक टिकट जारी कर उनके प्रति वास्तविक श्रद्धा और सम्मान प्रदर्शित किया, जबकि पूर्व सांसद सूरजभान सच्चे समाजसेवी के रूप में स्वामी जी के पदचिन्हों पर चल रहे हैं. अपनी राजनीतिक रेटिंग बढ़ाने के लिए ये भले जो दावे करें, लेकिन यह सही है कि भूमिहार समाज के महत्वाकांक्षी तबक़े को इसका बख़ूबी अहसास हो गया है कि रामाश्रय प्रसाद सिंह, भोला सिंह, अरूण कुमार, महाचंद्र सिंह, अखिलेश सिंह आदि राजनीतिक अवसान की ओर तीव्रता के साथ अग्रसर हैं. इनका अवसान ही इस वर्ग को अवसर प्रदान करेगा. लिहाज़ा उन्हें स्वामी सहजानंद सरस्वती को सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल करने से गुरेज़ नहीं है.

feedback@chauthiduniya.com

धनुडीह से आग का प्रकोप इस ओर बढ़ रहा है. इस कारण गैस और धुंए के बादल निकल रहे हैं. डोजर और हॉलपैक से भराई का कार्य भी असफल रहा.

नेपालिया ट्रेन के नाम से मशहूर जयनगर से जनकपुर रेलमार्ग पर चलने वाली नैरो गेज की इस ट्रेन ने अपने 8 दशक के सफ़र में कई उतार-चढ़ाव देखे हैं.

एक नज़र

श्रम विभाग की उदासीनता से मज़दूर बेहाल

ज़िले की हसनपुर चीनी मिल में कार्यरत मज़दूरों को न्यूनतम मज़दूरी एक्ट के तहत मज़दूरी का भुगतान नहीं हो पा रहा है, जबकि श्रम विभाग के अधिकारी जिनको मिल की बराबर जांच करते हुए यह देखना है कि कहीं मज़दूरों के साथ ज्यादती तो नहीं हो रही है, वे अपना काम नहीं कर रहे हैं. समस्तीपुर के श्रम अधीक्षक एवं उप श्रमायुक्त, दरभंगा स्वयं या अपने अधिकृत पदाधिकारी को मिल की जांच पड़ताल में भेजते हैं. वह मिल के अतिथिगृह में शाही मेहमान बनकर अपने कर्तव्यों की खानापूर्ति कर जाते हैं. अंजाम होता है कि श्रम अधिनियम की एक्ट फाइलों एवं किताबों में ही रह जाती है. मज़दूरों के हित में इसका उपयोग नहीं किया जाता है.

महिला दिवस पर 20 महिलाएं सम्मानित

अंतराष्ट्रीय महिला दिवस पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए रेलवे इन्द्रालय समस्तीपुर में आधी आबादी को सम्मानित किया गया. इस अवसर पर 20 महिलाओं को स्मृति चिन्ह प्रमाण पत्र व शाल प्रदान किया गया. डॉ. प्रभात दास फाउंडेशन के तत्वधान में आयोजित कार्यक्रम को मंडल रेल प्रबंधक सत्यप्रकाश द्विवेदी ने कहा कि यदि महिलाएं कमज़ोर बनी रहेंगी तो राष्ट्र का विकास नहीं होगा. फाउंडेशन के निदेशक व अप्रवासी भारतीय डॉ. प्रभात दास ने कहा कि महिलाओं को आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी बनना चाहिए. इसके लिए फाउंडेशन से हर संभव मदद मिलेगी. मौके पर सीनियर डीसीएम जफ़र आज़म प्रियरंजन प्रियदर्शी आदि भी उपस्थित महिलाओं की हौसला अफ़ज़ाई कर रहे थे. मंच संचालन अमृता ने किया.

मार्केटिंग शेड का निर्माण कार्य अधूरा

अररिया के रानीगंज प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में बनने वाली मार्केटिंग शेड का निर्माण कार्य दो वर्षों से अधूरा पड़ा है. बसैटी, बौसी आदि पंचायतों में दो वर्ष पूर्व मार्केटिंग शेड का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, परंतु आज तक पूरा नहीं हुआ. ग्रामीणों की मानें तो विभागीय अधिकारियों व अभिकर्ता की मिलीभगत से राशि का उठाव कर लिया गया है. मज़े की बात तो यह है कि मार्केटिंग शेड परिसर में न तो कोई बोर्ड लगाया गया है और न ही प्राक्कलित राशि अंकित की गई है. बौसी पंचायत के मुखिया राज किशोर यादव ने कहा कि कई बार अभिकर्ता को निर्माण कार्य पूरा करने के लिए कहा गया है, परंतु कार्य पूरा नहीं किया गया है. वही ग्रामीण, मुन्ना स्वर्णकार, चंदन कुमार, विकास आर्य, दिनेश कुमार आदि ने ज़िला प्रशासन से मार्केटिंग निर्माण कार्य पूरा करने की मांग की है.

पेड़-पौधों से सेवा की सीख लें

अररिया के सदर अस्पताल के कर्मी मरीज़ों की सेवा करने की सीख पेड़ पौधों से ले रहे हैं. यह बात ज़िलाधिकारी एम. सरवणन ने अस्पताल में वृक्षारोपण के मौके पर कही. डीएम ने अपने हाथों से कई वृक्ष लगाए. उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण करने से पर्यावरण को शुद्ध किया जा सकता है. इस मौक़े पर उन्होंने वृक्षारोपण कार्यक्रम की तस्वीर व लोगों द्वारा हस्ताक्षरित पृष्ठ बोर्ड बनाकर परिसर में लगाने के निर्देश सीएस को दिए. अस्पताल परिसर, पुराना सीएम आवास के आसपास गंदगी देख डीएम ने नाराज़गी जताई. इसके अतिरिक्त उन्होंने परिसर में ख़राब व जर्जर वाहन को नीलाम कराने का निर्देश सीएम को दिया. इस मौक़े पर सिविल सर्जन डॉ. सीके सिंह, सदर एसडीओ डॉ. विनोद कुमार, डीएस डॉ. हुस्नआरा सहित कई अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे.

कल्पना टीटी की चैम्पियन

दरभंगा के एमआरएम कॉलेज की कल्पना कुमारी सिंह टेबल टेनिस प्रतियोगिता की चैंपियन बन गईं. इस कॉलेज के नाम पर कल्पना ने हर दिन सीएम कॉलेज के कॉमन रूम में प्रेक्टिस की थी. पीटीआई सीएम कॉलेज के श्याम किशोर राय ने इसमें सहयोग दिया. इस कॉलेज में टेबल टेनिस बोर्ड तो छोड़िए, इसका बैट भी नहीं है. इसके बावजूद कल्पना ने दूसरी बार यह ख़िताब जीतकर एमआरएम कॉलेज का नाम ऊंचा किया. कल्पना के इस जीत का श्रेय उप विजेता अदिति को दिया, जिन्होंने अभ्यास में उसका पूरा साथ दिया था. कल्पना ने बताया कि गत वर्ष कॉलेज से एक टीटी का बैट मिला था, पर इस बार तो वह भी नहीं मिला.

नियोजन कार्यालय खंडहर में तब्दील

कहने को तो दरभंगा नियोजनालय बेरोज़गारों को रोज़गार तलाशने में सरकारी मदद करने वाला महकमा है, लेकिन ख़ुद की हालात ऐसी कि कहीं से भी लगता ही नहीं कि यह कोई सरकारी दफ्तर है. दरभंगा के ज़िला नियोजक कार्यालय से इसका दर्जा बढ़ाकर अवर प्रादेशिक नियोजनालय कर दिया गया, लेकिन दर्जा बढ़ने के साथ ही दर्द भी बढ़ता गया. यहां न तो हाकिम मिलेंगे और न ही बड़े बाबू. ऐसा नहीं है कि लोग दफ्तर नहीं आते. हक़ीक़त यह है कि यहां लगभग पद ख़ाली है. वैसे तो यह अवर नियोजन कार्यालय है. इसके कारण यहां पदाधिकारी के तीन पद हैं, जिसमें संयुक्त निदेशक एवं उपनिदेशक का पद प्रभार के भरोसे है तो ज़िला नियोजन पदाधिकारी का पद ख़ाली है. दीवालों में दरार आ गई है. यहां तक कि इसकी छत और दीवारों पर पीपल व बरगद के पेड़ भी उग गए हैं.

इस बार हैट्रिक की तैयारी : सावित्री देवी

पंचायत [illegible] बिहार-झारखंड की सीमा रेखा पर अवस्थित चकाई का [illegible] पंचायत अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग बाहुल्य पंचायत है [illegible] मुखिया सावित्री देवी हैं [illegible] लगातार दो [illegible] तैयारी में [illegible] स्वास्थ्य [illegible] समाजसेवी [illegible]

–चौथी दुनिया ब्यूरो

PATALIPUTRA SCHOOL OF FIRE & SAFETY MANAGEMENT

Only one Institute of Bihar & Jharkhand, which is Govt. of India registered, Regd. No. 03-09284 of 2000-2001.
ISO 9001:2000 certified, Regd. No. CCPL/QMS/C1487
Only one Institute of Bihar & Jharkhand, where Practicals are conducted.
Only one Institute of Bihar & Jharkhand, where one full paper of 100 marks on petroleum is taught.
Only one Institute of Bihar & Jharkhand, where students of Industrial Safety Management Course of Patna University & Magadh University get Practical Training.

FREE Demo-Classes in the Morning & Evening from Monday to Friday

Excellent Placement with Handsome Salary

Website : www.psfsm.com
410, Ashiana Galaxy, Exhibition Road, Patna-800 001
Ph : 0612-6455919, Mob. : 9334107607, 9835042835, 9234729075

पंचायत चुनाव पर माओवादियों का साया

सुनील सौरभ

हर बार की तरह इस बार भी पंचायत चुनाव आते ही प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा, माओवादी ने चुनाव बहिष्कार का फ़रमान जारी कर संभावित उम्मीदवारों को परिणाम भुगतने की चेतावनी दे दी है. [illegible]

[illegible] हज़ार ग्रामीणों को आवागमन की सुविधा मिल जाएगी. ग्रामीणों ने कहा कि यह पुल हम लोगों के लिए ख़ुशहाली लेकर आएगा. बताया जाता है कि इस मामले को लेकर जहां नक्सली गंभीर हो गए हैं, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण भी इस पुल के निर्माण को जीवन-मरण का प्रश्न बना चुके हैं. इतना तो तय है कि पंचायत चुनाव में नक्सलियों को पुलिस प्रशासन के साथ-साथ अब ग्रामीणों की चुनौती का भी सामना करना पड़ेगा. गया ज़िले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव दस चरणों में संपन्न होगा. इसके लिए पूरे ज़िले के प्रखंडों में 4573 मतदान केंद्र के साथ 46 सहायक मतदान केंद्र बनाए गए हैं. गया ज़िले में ज़िला पार्षद के 46, मुखिया के 332, सरपंच के 332, पंचायत समिति सदस्य के 459, पंच के 4573, वॉर्ड सदस्य के 4573 पदों पर चुनाव होने हैं. पिछले विधानसभा चुनाव में अपने मंसूबे पर पानी फिरने के बाद नक्सलियों ने पंचायत चुनाव में अपना मतलब साधने

और चुनाव को रक्तरंजित करने के तैयारी में पूरा ज़ोर लगा दिया है. मतदान के दौरान माओवादी अपनी कार्रवाई में सफल नहीं हो पाए तो इसके बाद वे वोट बहिष्कार का फ़रमान न मानने वाले प्रत्याशियों पर निशाना साध सकते हैं. इसी बात को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी दहशत हैं. माओवादी भी पंचायत चुनाव में ग्रामीणों के बदलते तेवर को देखकर अपनी रणनीति बदलने तथा वोट बहिष्कार के लिए अधिक से अधिक समर्थन प्राप्त करने के लिए नई-नई कार्य योजना बनाने में लगे हैं. इन सबके पीछे एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि पंचायत चुनाव में नक्सलियों के साथ-साथ पुलिस की कार्रवाई का ख़ामियाजा ग्रामीणों को ही भुगतना पड़ेगा.

feedback@chauthiduniya.com

नेपाल में प्रशिक्षण दिया जा रहा है

मनोज कुमार राव

माओवादी पूर्वी चंपारण में संभवत फिर एक बार बमों के धमाके व आधुनिक हथियारों का भरपूर प्रदर्शन करेंगे. जानकारी के अनुसार इस बार नेपाल को प्रशिक्षण का केंद्र बनाया गया है. माओवादी संगठन के लोग विशेष तौर पर बेरोज़गारों पर नज़र रखे हुए हैं. ज़्यादातर उन ग़रीबों को शामिल किया जा रहा है जो अपने अपने क्षेत्रों में सामंती प्रताइना से गुज़र चुके हैं. नेपाल से सटे ज़िलों के अस्पतालों में से असाध्य बीमारी मसलन एड्स, कैंसर आदि से जूझने वालों की तलाश हो रही है. अपनी ज़िंदगी से उम्मीद छोड़ चुके ऐसे लोग अपने परिवार की आर्थिक सुरक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं.

उधर, नेपाल के हाफली जंग ज़िले के झानदों जंगल एरिया में यूसीपीएन नेपाली माओवादी कैडरों द्वारा भारतीय उग्रवादियों को हथियारों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है. साल 2010 में तीन माह के बीच 250 भारतीय उग्रवादियों को हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया गया था. सुब्रतो मुखर्जी, हरिसावरण मरांडी और नेपाल के हमले जंग के बीर बहादुर के अधीन अत्याधुनिक आर्म्स चलाने का प्रशिक्षण दिया जा गया है. इनमें युवतियां भी शामिल हैं. इनको सीमा के रास्ते भेज दिया जाएगा, चुनावों में ख़लल डालने के लिए.

ख़ुफ़िया सूत्रों की रिपोर्ट पर राज्य पुलिस मुख्यालय ने पूर्वी चंपारण पुलिस को अलर्ट कर दिया है. ग़ौरतलब है कि पूर्वी चंपारण के पकड़ीदयाल अनुमंडल में विगत चार पांच साल पहले माओवादियों के इतने धमाके हुए कि यहां की धरती लाल हो गई थी. चाहे वह मधुबन धमाका हो अथवा इस अनुमंडल में हुए अन्य माओवादी हमले. यहां की आम जनता रात-रात भर जागने को विवश थी.

मालूम हो कि 2010 के नवंबर माह में काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने नेपाल की विदेश मंत्री सुजाता कोइराला, मंत्री भीम रावल के अलावा अन्य अधिकारियों को पत्र भेजकर यह सूचना दी गयी थी कि माओवादी नेताओं ने नक्सलियों को प्रशिक्षण देने के लिए तीन भारतीय नक्सली नेताओं के साथ गुप्त समझौता कर लिया है. समझौते के अनुसार भारतीय नक्सली नेताओं में बिहार के सीतामढ़ी ज़िले के निवासी पंकज के अलावा विनोद गुरुंग व रजाक अंसारी का नाम सामने आया था. वह पत्र अब सच साबित हो रहा है. जिस समय यह सूचना दी गई थी उस समय प्रशिक्षण देने की सहमति बनी थी. संभवत अब प्रशिक्षण का कार्य पूरा हो चुका है और प्रशिक्षित माओवादियों ने पकड़ी दयाल अनुमंडल सहित मोतिहारी मंडल कारा को भी अपना निशाना बनाया हुआ है. कुल मिलाकर माओवादी पूरी तरह से तैयार दिख रहे हैं.

feedback@chauthiduniya.com

घटिया खाने से बच्चे बीमार

बक्सर, चौसा, डुमरांव, ब्रह्मपुर तथा चौगाई प्रखंडों में ही अब तक जांच की गई है. इन प्रखंडों में स्वास्थ्य जांच के बाद लगभग दो हज़ार बच्चे गंभीर बीमारियों से पीड़ित मिले. इन बच्चों में आंख, कान, पेट, एनीमिया, श्वास नली में बीमारियां पाई गईं.

बक्सर

बक्सर के विद्यालयों में घटिया खाना खाने की वजह से छात्र बीमार हो रहे हैं. इससे बच्चों को खिलाए जा रहे पोषाहार एमडीएम की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह लग गया है.

बताया जाता है कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए मिड डे मील योजना चलाई जा रही है. इस योजना का उद्देश्य यह है कि बच्चों को पौष्टिक भोजन मिले. सालों से चल रही इस योजना के मूल्यांकन तथा इससे होने वाली लाभ-हानि की जानकारी के लिए विद्यालयों के छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है. जांच का कार्य एनजीओ को सौंपा गया है. यह काम अक्टूबर 2009 से शुरू होने के बाद भी आजतक पूरा नही हुआ है.

जांच के बाद जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं, वह भी चिंताजनक हैं. बक्सर, चौसा, डुमरांव, ब्रह्मपुर तथा चौगाई प्रखंडों में ही अब तक जांच की गई है. इन प्रखंडों में स्वास्थ्य जांच के बाद लगभग दो हज़ार बच्चे गंभीर बीमारियों से पीड़ित मिले. इन बच्चों में आंख, कान, पेट, एनेमिया, श्वास नली में कई तरह की बीमारियां पाई गईं. लड़कियों में ज़्यादातर एनीमिया अर्थात ख़ून की कमी की बीमारी पाई गई है. डॉक्टरों का कहना है कि विद्यालय के पोषाहार में पौष्टिक भोजन नही दिया जाता है. जांच कराने वाली संस्था के सचिव विनोद कुमार सिंह ने बताया कि बीमार बच्चों को बेहतर इलाज के लिए अस्पतालों में रेफर कर दिया जाता है, जबकि इसी संस्था के सचिव मनोज वर्मा कहते हैं कि पौष्टिक भोजन, शुद्ध पानी तथा स्वच्छता की जानकारी होने से ही कई तरह की बीमारियों से बचाव किया जा सकता है. जानकार बताते हैं कि राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा ब्लड ग्रुप की जांच का प्रावधान नहीं किया गया है, लेकिन बक्सर ज़िला प्रशासन द्वारा बच्चों के ब्लड ग्रुप की जांच कराई जा रही है. प्राथमिक विद्यालयों को जांच के दायरे से बाहर रखा गया है. सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना में उजागर हुई गड़बड़ी से नौनिहालों के भविष्य पर तो प्रश्न चिन्ह लग ही गया है, साथ ही यह योजना अपने उद्देश्यों से भी भटक गई है.

जय मंगल पाण्डेय
feedback@chauthiduniya.com

एक नज़र

बांध को लेकर मधुबनी के लोग नाराज़

मधुबनी के पाली पंचायत में बाढ़ में ध्वस्त हुए महाराजी बांध की मरम्मत का कार्य प्रारंभ न होने के कारण यहां के लोगों में आक्रोश व्याप्त है. ज्ञात हो कि पाली गांव 17 किलो मीटर की महाराजी बांध से गांव घिरा हुआ है. यह महाराजी बांध एक दर्जन स्थानों पर कई वर्षों से ध्वस्त पड़ा हुआ है. जिसकी वजह से लोगों को हर साल बाढ़ से होने वाली दिक्कतों को झेलना पड़ता है. सुरक्षा बांध की मरम्मत न होने के कारण पाली पंचायत के लोगों को हर साल भारी मुश्किलों से गुज़रना पड़ता है. जदयू नेता राजेन्द्र मिश्र, भाजपा के शिवशंकर झा नूनू ने सरकार से शीघ्र महाराजी बांध की मरम्मत का कार्य शुरू कराए जाने का आग्रह किया है.

डीआईजी ने पाठ पढ़ाया

मुजफ्फरपुर ज़िले में बेहतर पुलिसिंग का पाठ पढ़ाने डीआईजी बच्चू सिंह मीणा नगर थाना पहुंच गए. डीआईजी के पहुंचने के साथ एसएसपी राजेश कुमार, सिटी एएसपी विकास बर्मन भी आ गए. बैठक करते हुए डीआईजी ने शहरी क्षेत्र के थानाध्यक्षों को कार्यशैली में सुधार लाने का फरमान जारी किया. उन्होंने कहा कि लंबित केस को लेकर बोझ बने पदाधिकारी चलने वाले नहीं हैं. सभी पदाधिकारियों को केस निष्पादन के लिए टारगेट दिया गया है. इसके साथ ही प्रत्येक थाने में जन संवाद कर लोगों की समस्याओं का निपटारा किया जाएगा. इस दौरान सभी थानाध्यक्षों को उन्होंने शराब, स्मैक और स्प्रिट के कारोबारियों को सात दिनों के भीतर सफ़ाया करने का समय दिया.

भाजपा का सहयोग निधि कार्यक्रम

सीवान के भाजपा ज़िला कार्यालय में आजीवन सहयोग निधि कार्यक्रम का शुभारंभ भाजपा ज़िलाध्यक्ष प्रो. अभिमन्यु कुमार सिंह की अध्यक्षता में किया गया. इस कार्यक्रम का उदघाटन प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष लालबाबू प्रसाद ने किया. इस मौके पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि भाजपा अनुशासित, स्वच्छ व पारदर्शी पार्टी है. उन्होंने कार्यकर्ताओं से अधिक से अधिक भागीदारी निभाने की अपील की. इस मौके पर प्रदीप कुमार रोज, ज़िला महामंत्री सरोज सिंह, विनोद सिंह, त्रिपुरारी सिंह, दीनानाथ सिंह पटेल सहित कई लोग मौजूद थे.

संजीवनी के टाउनशिप की मांग

संजीवनी का है ऐलान, झारखंड में हो सबका मकान. अपने इसी उद्देश्य के साथ काम कर रही संजीवनी बिल्डकॉन के टाउनशिप की बोकारो में ज़बरदस्त मांग है. बोकारो, जहां हाल ही में संजीवनी का भव्य उदघाटन हुआ है, वहां लोगों में अब अपने घर का सपना पूरा होने का भरपूर उत्साह नज़र आ रहा है. सैकड़ों की संख्या में लोग संजीवनी की टाउनशिप में बुकिंग करा रहे हैं. अगले 1 महीने में कंपनी ने 5 अन्य नई परियोजनाओं को लांच करने की तैयारी की है. लोगों का मानना है कि किफ़ायती दरों पर प्लॉट, बंगला एवं डुप्लेक्स और वो भी विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ उपलब्ध कराना ही संजीवीनी की विशेषता है.

महिला जागरण का नया दौर शुरू

स्त्री और पुरुष शिव और शक्ति की तरह एक दूसरे के पूरक हैं. महिलाओं के बिना संसार का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, लेकिन महिला जागरण का नया दौर आरंभ हो चुका है. अब महिलाएं प्रतिकार करने को आगे बढ़ रही हैं. स्वार्थी और शोषक प्रवृति के पुरुषों को सावधान हो जाना चाहिए. यह विचार विश्व महिला दिवस के अवसर पर जागो बहन की ओर से आयोजित एक विचार-गोष्ठी में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमिटी के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉ. अनिल सुलभ ने व्यक्त किए. डॉ. सुलभ ने कहा कि नारी आन्दोलन को आगे बढ़ाने के लिए स्त्रियों को सुलझे और नेक विचारों वाले पुरुषों का साथ अवश्य लेना चाहिए.

–चौथी दुनिया ब्यूरो

झरिया में फिर भड़की आग

राजापुर कोयला परियोजना इलाक़े की बस्ती में हुए गैस रिसाव को लेकर झरिया कोयलांचल में एकबार फिर जनता का गुस्सा फूट पड़ा है. इस प्रकरण ने झरिया पर मंडरा रहे ख़तरे के बादल के रंग को और काला कर दिया है, जिसकी वजह से वहां के लोग दहशत में जी रहे हैं. हालांकि प्रबंधन ने डोजरिंग कार्य शुरू कराया था, लेकिन गैस रिसाव थमने का नाम ही नहीं ले रहा है. बताते हैं कि गैस रिसाव के कारण दोबारी बस्ती से सहाना पहाड़ी को जाने वाला मार्ग भी प्रभावित हो गया है. वहां के लोगों का कहना है कि क़रीब एक माह पहले भी गैस का रिसाव हुआ था. तब भराई कार्य कराया गया था, लेकिन पर्याप्त भराई न होने के कारण फिर से गैर रिसाव होने लगा. बताया जाता है कि भूमिगत आग से बनने वाली गैस को निकालने के लिए मार्ग चाहिए. यदि पूर्णरूपेण ब्लैक होल की भराई हो भी जाती है तो भी गैस अपना मार्ग ढूंढ लेती है. भारी मात्रा में ओबी भी भराई के अलावा आग बुझाने के भी उपाय हों, तभी इससे निजात मिल सकती है. आग और गैस रिसाव को देखते हुए सिम्फर के वैज्ञानिक एम. सहाय ने बोका पहाड़ी में पूर्व में हुई बोर होल की जानकारी ली. इस दौरान उन्होंने कहा कि अब भूमिगत आग की गति सीमा की मापी की जाएगी. ग़ौरतलब हो कि 2010 के मार्च माह से आग की गति सीमा मापने का कार्य बंद है. तब से रिपोर्ट के अनुसार आग आरएसपी कॉलेज से 70 मीटर की दूरी पर धधक रही थी. भूमिगत आग प्रतिमाह लगभग दो मीटर की रफ्तार से कॉलेज की ओर बढ़ रही है, इस हिसाब से आग महज़ 50 मीटर के फ़ासले पर है. दूसरी ओर राजापुर परियोजना पदाधिकारी एमके सिंह का कहना है कि धनुडीह से आग का प्रकोप इस ओर बढ़ रहा है. इस कारण गैस और धुंए के बादल निकल रहे हैं. उन्होंने कहा कि डोजर और हॉलपैक से भराई का कार्य भी असफल रहा. दो दिनों तक गैस और धुंआ निकलने के बाद तीसरे और चौथे दिन भी गैस रिसाव जारी है. अब धुंए के साथ आग की तेज़ लपटें भी उठ रही हैं. विषेषज्ञों की मानें तो स्थिति गंभीर है. बिना खुदाई आग पर नियंत्रण संभव नहीं है. विशेषज्ञ दबी ज़ुबान में यह भी कह रहे हैं कि भविष्य में इस आग से झरिया शहर में अधिक परेशानी हो सकती है. तक़रीबन 400 की आबादी वाले दोबारी गांव में वर्ष 1993 से ही पानी की समस्या है. विस्थापन का दबाव बना रहे बीसीसीएल के अधिकारियों ने यहां के एक मात्र नल को भी उखाड़ दिया है. तब से आज तक यहां के लोगों को पानी के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है. वहां के लोगों का कहना है कि बीसीसीएल की यही मंशा है कि यह जगह किसी तरह ख़ाली हो जाए. इन लोगों की रुचि आग पर क़ाबू पाने की नहीं है. विडंबना देखिए 20 वर्षों से आग की स्थिति की जानकारी के लिए अध्ययन किया जा रहा है और आजतक इसका हल निकाला नहीं जा सका है. उधर, सिम नौ के सभी मुहानों से धुंआ निकल रहा है, वहीं चट्टाने तड़तड़ा कर टूट रही हैं. डर है कि कहीं भूधसान की घटना न हो जाए. डीजीएमएस एवं बीसीसीएल की ओर से यह क्षेत्र अग्नि प्रभावित है. वर्तमान स्थिति अलार्मिंग है. दूसरी ओर बंद राजापुर परियोजना से निकल रही आग और गैस का मुआयना करने पहुंचे एसडीओ को भारी आक्रोश का सामना करना पड़ा. सर्वे में आईजेआरडीए की टीम को भी सर्वे से रोक दिया गया. झरिया कोलफील्ड बचाओ समिति ने बीसीसीएल एवं ज़िला प्रशासन की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं.

दोबारी बस्ती ख़ाली करो

एसडीओ के दोबारी बस्ती (लगभग 60 घर) ख़ाली करने के आदेश ने आग में घी डालने का काम किया. एसडीओ का कहना था कि जान-माल की सुरक्षा के लिए बस्ती के लोग झरिया विहार बेलगड़िया चले जाएं. प्रत्येक परिवार को घर मिलेगा. इतना सुनते ही बस्ती के लोग भड़क गए और कहा कि हमलोग यहां खैराती ज़मीन पर नहीं रह रहे हैं. यह हमारे बाप-दादाओं की ज़मीन है. ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बीसीसीएल ने पांच एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण किया है. क़रार के मुताबिक़ सभी को नौकरी नहीं मिली है. वहीं बीसीसीएल के अधिकारियों ने कहा कि पांच एकड़ ज़मीन के बदले नौ लोगों को नौकरी दे दी गई है. मगर ग्रामीणों का कहना है कि हम लोगों को नौकरी नहीं मिली है. हमलोग यहां मरना पसंद करेंगे, मगर बिना नौकरी लिए बस्ती नहीं छोड़ेंगे. इस पर एसडीओ ने मौक़े पर उपस्थित झरिया के अंचलाधिकारी संजीव कुमार को ज़मीन व मकान का सर्वे करने के आदेश दिए. दूसरी ओर दोबारी के प्राथमिक विद्यालय स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. ख़तरे को देखते हुए शिक्षा ज़िला अधीक्षक रतन महावार ने प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को जांच कर रिपोर्ट भेजने को कहा है. बताया जाता है कि इस विद्यालय को कोइरीबांध स्थित गुरुनानक विद्यालय में समायोजित करने और शिक्षिकाओं को अन्यत्र प्रतिनियुक्ति करने पर विचार चल रहा है. उधर, विद्यालय स्थानांतरण की सूचना से बस्ती के लोग आक्रोशित हैं. सवाल उठाया जा रहा है कि बच्चे इतनी दूर कैसे जाएंगे. बहरहाल, अगर समय रहते ज़िला प्रशासन व बीसीसीएल ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो भविष्य में किसी बड़ी घटना से इंकार नहीं किया जा सकता.

राजीव रंजन
feedback@chauthiduniya.com

नेपाली ट्रेन बंदी के कगार पर

भारत तथा नेपाल के बीच वर्षों से क़ायम अटूट मैत्री संबंध की प्रतीक एवं अंतराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र के लोगों के लिए लाइफ़ लाइन माने जाने वाली नेपाली ट्रेन की हालत जर्जर होकर बंद होने के कगार पर पहुंच गई है. दुष्यंत कुमार के कथन अपनी विरासत को संभालो वर्ना यह आख़िरी दीवार भी गिर जाएगी, से सबक़ लेकर यदि शीघ्र इसके सुधार के लिए सरकारी स्तर पर प्रयास नहीं किया गया तो सामरिक दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण यह अंतरराष्ट्रीय रेल मार्ग भी इतिहास के पन्नों में दफ़न होकर रह जाएगा. उल्लेखनीय है कि पड़ोसी तथा मित्र राष्ट्र नेपाल के इस एकमात्र रेलखंड का इतिहास लगभग आठ दशक पुराना है. स्थानीय ज़ुबान में नेपालिया ट्रेन के नाम से मशहूर जयनगर से जनकपुर नेपाल तक के 29 किलोमीटर रेलमार्ग पर चलने वाली नैरो गेज की इस ट्रेन ने अपने 8 दशक के सफ़र में कई उतार-चढ़ाव देखे हैं. नेपाल में रेलवे की शुरुआत वर्ष 1937–38 में मानी जाती है. नेपाल रेलवे के इतिहास के अनुसार तत्कालीन अंग्रेज़ी हुकूमत ने नेपाल के विस्तृत भूभाग में फैले वनों से होने वाली लकड़ियों की ढुलाई सुगमता पूर्वक करने के लिए इस रेल मार्ग का निर्माण करवाया था. तब नेपाल के राजा शमशेर राणा एवं दरभंगा महाराज के बीच हुए समझौते के आधार पर जयनगर में नेपाल रेलवे के लिए ज़मीन उपलब्ध कराई गई. जिसमें दो किलोमटर रेलवे लाइन के साथ नेपाल रेलवे के महाप्रबंधक कार्यालय का निर्माण भी जयनगर में किया गया, जो कालांतर में पहले जनकपुर और बाद में काठमांडू स्थानांतरित कर दिया गया. लकड़ी ढुलाई के लिए अंग्रेज़ों द्वारा निर्मित इस मार्ग पर यात्रियों के सफ़र की शुरुआत 50 के दशक में हुई. तब जयनगर से जनकपुर होते हुए बिजलपुरा नेपाल तक कुल 69 किलोमीटर में यह ट्रेन चलती थी. वर्ष 1976 नेपाल रेलवे के इतिहास में एक काला अध्याय माना जाता है. इसी वर्ष विधिया पुल टूटने के बाद जनकपुर से विजलपुरा तक ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया गया. मात्र 29 किलोमीटर के छोटे रेलखंड वाले नेपाल रेलवे को वर्ष 1992 में उस समय पुन: जीवन सा मिला जब भारत सरकार के द्वारा डीज़ल से चलने वाले 4 इंजन एवं 18 डिब्बों की सौग़ात मिली. तब से नेपाल रेलवे की दूरी यातायात व्यवस्था इसी इंजन व डिब्बों पर आश्रित है. देश में राजनीतिक अस्थिरता, वित्तीय कुप्रबंधन एवं तकनीकी कौशल के अभाव ने इसे अत्यंत रूग्न अवस्था में ला दिया है. स्थिति यह है कि नेपाली ट्रेन चलते-चलते कब और कहां रुक जाएगी, इसका कोई भरोसा नही है. वित्तीय कुप्रबंधन के कारण नेपाल रेलवे के 52 स्थायी समेत 177 रेलकर्मियों को बीते 4 माह से वेतन नही मिल सका है. आर्थिक संकट से घिरे कर्मियों के हड़ताल प्रदर्शन की एक अलग समस्या. बावजूद इसके रेलवे को लेकर नेपाल सरकार का रवैया बिल्कुल ढुलमुल बना हुआ है. हालांकि भारत सरकार ने नेपाल रेलवे की स्थिति में सुधार के लिए आवश्यक पहल की है. भारत सरकार ने इस मार्ग का अंतिम सर्वेक्षण कराया है. समस्तीपुर के मंडल रेल प्रबंधक सत्य प्रकाश त्रिवेदी ने एक भेंट में बताया कि नेपाल सरकार की सहमति के पश्चात यह मामला भारत सरकार के विदेश विभाग से भारतीय रेलवे के पास पहुंच चुका है. भारतीय रेल निर्माण एजेंसी की तलाश कर रही है. इसकी हालत बेहतर होती है तो अर्थव्यवस्थाओं में शुमार भारत तथा चीन के बीच स्थित नेपाल में रेलवे के विकास में योगदान करके भारत सरकार अपनी पकड़ भी मज़बूत कर सकती है.

नित्यानंद
feedback@chauthiduniya.com

रंगो का त्योहार होली के अवसर पर सभी जिले के निवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

अभिषेक आनंद झा
वरीय भाजपा नेता व प्रत्याशी
मधुपुर विधानसभा क्षेत्र देवघर, झारखंड

रंगो का त्योहार होली के अवसर पर सभी जिलेवासियों को हार्दिक शुभकामनाएँ

सुनील कुमार खवाड़े
समाजसेवी सह मुख्य संयोजक
भारत स्वाभिमान ट्रस्ट, देवघर (झारखंड)

होली की हार्दिक शुभकामनायें
पंचमुखी हनुमान मंदिर ट्रस्ट
गुलाबबाग, जीरो माईल
पूर्णियाँ की तरफ से स्थापित
शुद्ध देशी घी की बनी
मिठाई की एक मात्र दुकान

होली की हार्दिक शुभकामनायें
मो. इमरान
मुखिया प्रतिनिधि
दुबानोची पोठिया किशनगंज

होली की हार्दिक शुभकामनायें
पूर्णिया जिला कबड्डी संघ सचिव
मारवाड़ी युवा मंच गुलाबबाग उपाध्यक्ष
सुमित लोहिया
कि तरफ से
होली की हार्दिक शुभकामना

हम मकान नहीं घर बनाते हैं...
Yash Raj Enterprises Pvt. Ltd.
excellence in Real Estate....
An ISO 9001:2008 Certified Company
• PROMOTER • DEVELOPER
• MARKETER • SERVICE PROVIDER
9234601786, 9234602786, 9234603786
E-mail: yashraj221@gmail.com
Website : www.yashrajenterprises.com

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. DELHIN/2009/30467

अंग्रेजो के ज़माने का यात्री विश्रामगार लगभग डेढ़ साल पहले तोड़ दिया गया, लेकिन इतने दिनों के बाद भी इसका पुन: निर्माण नहीं किया गया है.

यात्री विश्रामगार की हालत ख़राब

दानापुर रेल मंडल बक्सर–आरा रेल खंड के रघुनाथपुर स्टेशन पर बने यात्री विश्रामगार को ध्वस्त करने के डेढ़ साल बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ. अंग्रेज़ो के ज़माने का यात्री विश्रामगार लगभग डेढ़ साल पहले तोड़ दिया गया, लेकिन इतने दिनों के बाद भी इसका पुन: निर्माण नहीं किया गया है. इससे यात्रियों को भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है. बरसात तथा जाड़े के मौसम में यात्रियों को सुरक्षित बैठने की जगह नहीं मिलती है. अन्य स्टेशनों का भले ही जीर्णोद्धार हो रहा हो, लेकिन रघुनाथपुर स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का घोर अभाव है. बलिया यूपी ज़िले के कई गांवो के लोग भी रघुनाथपुर स्टेशन से ही आना–जाना करते हैं.

जलापूर्ति कनेक्शन नहीं मिला

बक्सर के ब्रह्मपुर में करोड़ों रुपये ख़र्च कर लगाई गई पेय जलापूर्ति टंकी का पानी बेकार हो रहा है. लोगों को पेय जलापूर्ति कराने के लिए प्रखंड परिसर में करोड़ो रुपये ख़र्च कर पीएचईडी द्वारा नलकूप बनाकर हौज बनाया गया. पूरे नगर में सड़कों के किनारे पाइप बिछा कर किनारे–किनारे स्टैंड भी बनाए गए हैं. दो वर्ष पूर्व ही पूरे तामझाम के साथ उदघाटन कर इसे चालू किया गया था, लेकिन दो साल के बाद भी यहां के लोगों को एक बूंद पानी भी नहीं मिला. सरकारी व्यवस्था चुस्त होने के बाद भी लोगों के घरों में जलापूर्ति का कनेक्शन आज तक नहीं दिया गया. काग़ज़ों पर तो कनेक्शन हो गया है पर सच्चाई यह है कि नलकूप के चालू होने के बाद इसका पानी बेकार ही चला जाता है. अभी से ही लोग पानी की समस्या को लेकर परेशान होने लगे हैं. न जाने कब तक पानी ऐसे ही बेकार बहेगा और लोग जलसंकट से जूझते रहेंगे.

–जय मंगल पाण्डेय

भवानी फर्निचर
मोतिहारी

होली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ
लकड़ी के सामानों के लिए हमारे यहां अवश्य पधारें

होटल हीमेन
स्टेशन रोड (पूर्णिया जक्शन के समीप)

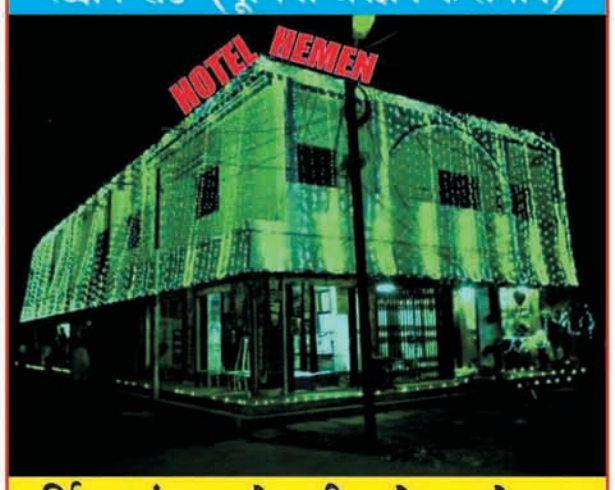

पूर्णिया जंक्शन के करीब स्टेशन रोड पर
नैसर्गिक आनन्द के लिए हीमेन में पधारें

HOTEL Sarvodaya

Om nanda, Rajendra Path, Patna-800 001.
Tele-0612-2322411/12/13, 0612-3200119, 9334192818, 9334103678,
Fax +91-612-2322414, Email : hotelsarvodaya@sify.com
Location : Located in the heart of Patna, 5 Kms. from the Airport and just half kilometre away from the Railway Station
We have facilities of Transit Rooms

FACILITIES
- Round the clock power supply A.C. & Lift with Generator Backup
- Transit Rooms
- Round the clock Room service
- Running Hot & Cold water
- Three A.C. BANQUETS HALLS (Capacity 10, 40 & 80) well equiped
- Travel Desk A.C. & Non A.C. (Luxuary Car) Rly. & Air Reservation/Transport
- Safe Deposit Lockers
- Credit Card Accepted
- Direct Dialing Facility from room
- Sufficient parking space
- Out Door Catering

The Saffron Court
A.C. Multi Cusine Restaurant
Tasty & mouth watering food (Indian, Chinese/Mughlai)

grand opening with new theme

" EMPOWERMENT THROUGH EDUCATION"

TECHNO MISSION SCHOOL

South-West Corner of Patel Maidan, (Near Law College) Kashipur, Samastipur- 848101, E-mail : technomission.principal@gmail.com
Run & Managged by : Samastipur Club in collaboration with Apurva Welfare Society, Samastipur

FREE ADMISSION
to the students of deprived group & Economically weak students in the light of R.T.E. ACT 2009 (Section-12)

Admission From KG to Class IX under Session April 2011 to March 2012 is going on

UP-TO-DATE TECHNOLOGY DRIVEN CLASSES

Good Wishes to Guardians, Students,
All Indian nationals and well wishers on the occasion of HOLI

Mr A.K. Lal (Chairman)

Vacancy
Applications are invited for the Post of Computer Assitant (Specially for Female)

Unique Features
- Located in the heart of town. Eco-friendly Campus.
- Built up with well-vantilated & spacious rooms.
- Spread over Free & Open Areas with Gorgeous playground.
- Easily accessible & Congestion-Free.
- English Medium, Co-educational, C. B. S. E. Curriculum (KG to IX) * Special Emphasis on Co-Curricular activities and CCE.
- Well-Skilled & devoted teachers.
- Learning through activities. Dance, Yoga, Games & Sports Book Club etc.
- Conveyance facilities on the major routes.
- Special attention to "SPOKEN ENGLISH" & "PERSONALITY DEVELOPMENT".
- No Need of any Private tution for our Students.
- Regular Health Chek-up, Regular Physical & Cultural Activities, Compulsory Book Club.
- Periodical Seminars & Symposium, Periodical Educational Tour.
- On the Concept of K.G. to P.G. in one Campus.

Mr M.K. Karna (Manager)

CONTACT : 9431245057, 9204068555, 9934304741, 9304051574

चौथी दुनिया

उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड

दिल्ली, 21 मार्च–27 मार्च 2011

www.chauthiduniya.com

प्रभुदयाल कठेरिया

धरती निगल गई या आसमान!

पूर्व सांसद के तीन रिश्तेदारों के अपहरण को 13 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई सुराग़ नहीं मिल पाया है. यह मामला लोकसभा में भी गूंजा और इसकी सीबीआई जांच कराने की भी घोषणा की गई. मगर सीबीआई की चार टीमें भी अपहृतों को तलाश नहीं कर पाईं. इस दौरान पूर्व सांसद पर चार बार क़ातिलाना हमले हुए. सरकार ने उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई और बाद में उसे वापस भी ले लिया गया.

राजेंद्र सारथी

जब सत्तारूढ़ पार्टी के सांसद के परिवार के तीन संबंधियों का ट्रक सहित अपहरण हो जाए और वह अपहर्ताओं का पता लगाने के लिए अपनी एड़ी से लेकर चोटी तक का ज़ोर लगा दे, फिर भी सरकारी मशीनरी यह पता न लगा पाए कि उन तीनों को ज़मीन निगल गई या आसमान खा गया. तो सोचिए, इस देश में आम आदमी की क्या बिसात है? ऐसा नहीं है कि हमारे देश की जांच एजेंसियां नाकारा हैं. अगर उन्हें दबावमुक्त रखा जाए तो वे पूरी तरह सक्षम हैं. जांच एजेंसियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच करने ही नहीं दी जाती. होता यह है कि जांच में जहां शक की सुई किसी दबंग व्यक्ति की तरफ़ हुई कि सौ तरह के दबाव जांच एजेंसियों पर पड़ने शुरू हो जाते हैं. परिणाम स्वरूप जांच जहां की तहां रुक जाती है. इस मामले को 13 साल गुज़र चुके हैं, लेकिन उन तीनों अपहृत युवकों का आज तक कोई पता नहीं चल सका है. हम बात कर रहे हैं फ़िरोज़ाबाद संसदीय सीट से भाजपा के तीन बार सांसद रह चुके प्रभु दयाल कठेरिया के तीन संबंधियों की. सांसद की मौसी का लड़का रामशरण, छोटे भाई का साला राम खिलाड़ी और बुआ के लड़के का बेटा अशोक, उनके ट्रक पर यमुना की रेती लाने का काम करते थे. ये तीनों 18 फ़रवरी 1997 को संजय प्लेस स्थित कठेरिया के मकान से सुबह दस बजे रेती लाने के लिए रवाना हुए थे, लेकिन रास्ते में ही उनका ट्रक सहित अपहरण कर लिया गया था.

ताज्जुब यह है कि उन दिनों केंद्र में भाजपा की सरकार थी. अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे. राज्य में भी भाजपा की सरकार थी, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे. कहीं किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं थी. अपहरण की रिपोर्ट थाना जैतपुर में दर्ज़ हुई थी. स्थानीय पुलिस ने यूं ही समय गंवा दिया, लेकिन वह उस केस को वर्कआउट नहीं कर पाई. इसके बाद कठेरिया सांसद होने के नाते लोकसभा के स्पीकर से मिले और उन्हें अपनी व्यथा बताई. कठेरिया इस मामले में प्रधानमंत्री से भी मिले और उनसे सीबीआई जांच की मांग की. बाद में स्पीकर और गृहमंत्री इंद्रजीत गुप्ता ने लोकसभा में इस संबंध में सीबीआई से जांच कराने की घोषणा की. कुछ समय बाद ही जांच के लिए सीबीआई की चार टीमें आगरा पहुंचीं और जांच शुरू की. सीबीआई की टीमें भी स्थानीय पुलिस की जांच के बिंदुओं के आसपास ही घूमती रही. महीनों की जांच के बाद परिणाम शून्य ही रहा. इसे क्या माना जाए, जांच एजेंसियों का नाकारापन या और कुछ? यही नहीं पूर्व सांसद प्रभुदयाल कठेरिया के ऊपर चार बार क़ातिलाना हमले हुए और हर बार वे बाल-बाल बच गए. एक बार तो उनपर हुए हमले के दौरान पेट्रोल पंप के एक कर्मचारी की गोली लगने से मौत भी हो गई. इन घातक हमलों के मद्देनज़र ही प्रभुदयाल कठेरिया को केंद्र सरकार ने ज़ेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की थी.

हाल ही में 19 अगस्त 2010 को उनके निवास पर जो कि पेइंग गेस्ट हाउस भी है, में छह लोगों के एक दल ने ख़ुद को आयकर विभाग से संबद्ध बताकर छापा मारा और उनके निवास की तलाशी लेनी चाही. कठेरिया उस समय निवास पर नहीं थे. उन तथाकथित आयकर अधिकारियों ने उनके निवास पर मौजूद लोगों को इतना आतंकित कर दिया था कि घबराकर गेस्ट हाउस का एक कर्मचारी छत से कूद गया था जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था. थोड़ी देर बाद ही कठेरिया वहां पहुंच गए थे. उन्होंने उन तथाकथित आयकर अधिकारियों से कहा कि मेरे यहां कोई कारोबार तो होता नहीं है, तब किस बात की तलाशी लेनी है तुम्हें? यदि तलाशी लेनी भी है तो अपनी पहचान के साथ ही ज़िले के अधिकारी की अनुमति भी लाओ. इसी बीच उन्होंने अपने कमरे में जाकर अपने सूत्रों को इन सब बातों की जानकारी देनी शुरू कर दी. सांसद कठेरिया के निवास के नीचे उनके सुरक्षाकर्मी खड़े थे जो कुछ देर पहले उनके साथ ही आए थे. आयकर विभाग के अधिकारी बनकर आए लोगों ने ख़तरे को भांप लिया और एक-एक करके वहां से खिसकना शुरू कर दिया. दो युवक नहीं भाग सके थे, जिन्हें कठेरिया के साथियों ने पकड़कर ख़ूब धुना और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया. इस घटना के चार घंटे बाद ही चार अन्य युवक रिवाल्वर से लैस होकर दोबारा उनके घर आए और अपने को उनका मित्र बताकर निवास की सीढ़ियां चढ़ने लगे. सुरक्षाकर्मियों ने युवकों के पास शस्त्र भांप लिए थे. इसलिए उन्होंने युवकों को रोका. जब युवक जबरन सीढ़ियां चढ़ने लगे तो सुरक्षाकर्मियों ने वार्निंग देकर उन्हें रोका और कहा कि अब यदि उन्होंने एक क़दम भी आगे बढ़ाया तो उनकी एसएलआर की गोलियां उन्हें भूनकर रख देंगी. इस पर चारों युवक रुक गए और तुरंत ही अपनी मोटर साइकिलों पर सवार होकर वापस चले गए.

ताज्जुब की बात यह है कि प्रभुदयाल कठेरिया को क़ातिलाना हमलों से बचाने के लिए ज़ेड श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी, वह 19 अगस्त को कठेरिया के निवास पर हुई दो घटनाओं के बाद 24 अगस्त 2010 को यकायक वापस ले ली गई. कठेरिया भयभीत हो गए. कहें तो किससे कहें? अब वे सांसद भी नहीं थे. इसके बाद कठेरिया मुख्यमंत्री मायावती से मिले. उन्हें अपनी व्यथा से अवगत कराया. मुख्यमंत्री ने इस पर 11 गनमैनों की सुरक्षा टीम भेजने के आदेश कर दिए. मगर प्रदेश की यह सुरक्षा टीम भी बमुश्किल तीन महीने ही रह पाई थी कि प्रदेश सरकार ने उसे यकायक वापस बुला लिया. इस समय कठेरिया अपनी सुरक्षा के लिए दो गनमैन अपने ख़र्च पर लगाए हुए हैं. उल्लेखनीय है कि 7 जुलाई 1952 को जन्मे प्रभुदयाल कठेरिया पप्पू ब्रास बैंड नाम से भदरौली में बैंडबाज़े का काम करते थे. साथ ही वे समाज सेवा में भी जुट गए. अपनी इस लोकप्रियता को भुनाने के लिए उन्होंने 1989 में लोकसभा का चुनाव निर्दलीय लड़ा और उन्हें 16 हज़ार वोट मिले थे. छिबरामऊ के भाजपा नेता रामप्रकाश त्रिपाठीजी जो मंत्री भी रहे थे, उनकी इस उपलब्धि से बहुत प्रभावित हुए. त्रिपाठी की छत्रछाया मास्टर प्रभुदयाल कठेरिया को मिली. उन्होंने 1989 में ही उन्हें भाजपा ज्वाइन करा दी.

सन् 1990 में भाजपा ने फ़िरोज़ाबाद लोकसभा सीट की टिकट के लिए अपने कार्यकर्ताओं से नाम मांगे तो मास्टर प्रभुदयाल कठेरिया ने भी आवेदन कर दिया. उन्हें पार्टी का टिकट मिल गया और वे चुनाव जीत गए. इसके बाद 1996 और 1998 के लोकसभा चुनाव में भी उन्हें विजय हासिल हुई. 2004 में जब फिर लोकसभा चुनाव हुए तो भाजपा ने लोकसभा प्रत्याशी के रूप में प्रभुदयाल कठेरिया की जगह किशोरीलाल माहौर को टिकट दे दिया. यह बात प्रभुदयाल कठेरिया को बहुत नागवार गुज़री. उन्होंने भाजपा से त्यागपत्र दे दिया और निर्णय लिया कि वे निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे. उन्होंने निश्चय कर लिया था कि वे किसी भी क़ीमत पर भाजपा प्रत्याशी को जीतने नहीं देंगे. वही हुआ भाजपा प्रत्याशी 52 हज़ार वोटों से बसपा प्रत्याशी से हार गया, जबकि उस चुनाव में प्रभुदयाल कठेरिया को 60 हज़ार वोट मिले थे. अब हम बात करते हैं 2009 में हुए लोकसभा चुनावों की. इस चुनाव में प्रभुदयाल कठेरिया कांग्रेस पार्टी की टिकट पर आगरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे. कांग्रेस के पास टिकट आवेदन करने वालों में अनेक पुराने कांग्रेसी नेता, कांग्रेस के आला अधिकारियों तक पहुंच रखने वाले व्यापारी और अफ़सरों की लंबी लाइन थी, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को प्रभुदयाल कठेरिया का दावा ही सबसे मज़बूत लगा और उन्होंने इनका ही टिकट फ़ाइनल कर दिया. कठेरिया चुनाव हार गए. उन्हें एक लाख वोट प्राप्त हुए. यहां उल्लेखनीय यह है कि कांग्रेस को इस सीट पर 1989 से अब तक कभी 14 हज़ार वोट से अधिक नहीं मिले थे.

2004 में भाजपा ने प्रभुदयाल कठेरिया का टिकट क्यों काट दिया? इस संबंध में भाजपा के वरिष्ठ संगठन पदाधिकारियों का कहना है कि हर पार्टी चाहती है कि उसका चुना गया जनप्रतिनिधि क्षेत्र में अपनी गतिविधियों से पार्टी का आधार मज़बूत करे. दूसरे पार्टी यह भी चाहती है कि उसका चुना गया जनप्रतिनिधि अध्ययनशील हो और किसी न किसी विषय का विशेषज्ञ प्रवक्ता बनकर संगठन को मज़बूती देने वाला सिद्ध हो, लेकिन पार्टी ने प्रभुदयाल कठेरिया को इन मामलों में एकदम निष्क्रिय पाया. पार्टी ने यह भी महसूस किया कि कठेरिया अब अपने रोज़गार के साधनों में अधिक व्यस्त रहने लगे हैं. दूसरे उनका कार्यक्षेत्र फ़िरोज़ाबाद के स्थान पर आगरा अधिक हो गया था. फ़िरोज़ाबाद संसदीय क्षेत्र के लोगों में उनकी पकड़ ढीली हो गई थी. इसीलिए पार्टी ने उनके स्थान पर किसी दूसरे को चांस देना उचित समझा.

2009 में प्रभुदयाल कठेरिया कांग्रेस की टिकट पर क्यों हार गए. राजनीति के पंडितों का मानना है कि इसकी मुख्य वजह कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों का उनके साथ न लगना है. कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी से लेकर ज़िले के सभी पदाधिकारी किसी न किसी बहाने अभिनेता व नेता राजबब्बर के प्रचार में फ़िरोज़ाबाद में तो सक्रिय दिखाई दिए, लेकिन कठेरिया के चुनाव में उनकी उपस्थिति नदारद रही. कठेरिया से कुछ वे लोग भी नाराज़ थे जो कांग्रेस में वर्षों से खट रहे थे और कठेरिया की वजह से टिकट की दावेदारी में उनकी उपेक्षा की गई. एक कारण टिकट का बहुत देर बाद घोषित होना भी रहा. कठेरिया को चुनाव ललडने के लिए मात्र 19 दिन का समय ही मिला था.

वैसे यह बात एकदम सत्य है कि चुनाव बहुत महंगे हो गए हैं. लोकसभा के चुनाव में करोड़ों रुपये ख़र्च होते हैं. यह चुनाव लड़ना किसी सामान्य आदमी के बस का नहीं रह गया है. इसलिए प्रत्येक पार्टी गांठ के पूरे और विजय की अधिकतम संभावना वाले प्रत्याशी का ही चयन करती है. चाहे वह प्रत्याशी बाहर से आया हुआ ही क्यों न हो. अब किसी भी राजनीतिक पार्टी में पुराना कार्यकर्ता होना उतने महत्व का नहीं रह गया है जितना यह कि वह कितना धनी है और पार्टी फ़ंड में कितना दे सकता है.

feedback@chauthiduniya.com

प्रभुदयाल कठेरिया 1990 में भाजपा की टिकट पर फ़िरोज़ाबाद लोकसभा सीट से चुनाव जीते थे. इसके बाद उन्हें 1996 और 1998 के लोकसभा चुनाव में भी विजय हासिल हुई. 2004 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने लोकसभा प्रत्याशी के रूप में कठेरिया की जगह किशोरीलाल माहौर को टिकट दे दिया. यह बात प्रभुदयाल कठेरिया को बहुत नागवार गुज़री. उन्होंने भाजपा से त्यागपत्र दे दिया और निर्णय लिया कि वे निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे. उन्होंने निश्चय किया कि किसी भी क़ीमत पर भाजपा प्रत्याशी को जीतने नहीं देंगे. वर्ष 2009 में उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन इसमें उन्हें कामयाबी नहीं मिली.

चौथी दुनिया

उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार 13 मई 2007 गठित हुई थी. तभी से सपा द्वारा कई तरह के धरने-प्रदर्शन किए गए, किंतु वे धरने-प्रदर्शन सफल नहीं हो सके थे.

अंबेडकर विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्रियों का पूरा तंत्र विश्वविद्यालय के पूरे प्रशासन पर क़ब्ज़ा जमाए हुए है.

चौथी दुनिया

बच्चों का यौन शोषण करने वालों की ख़ैर नहीं

प्रियंका सिंह

बच्चों के शोषण संबंधी विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में मंज़ूरी दे दी है. विधेयक में बाल-शोषण करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त सज़ा का प्रावधान किया गया है. विधेयक की सातवीं धारा में 16 से 18 वर्ष की आयु के बीच मर्ज़ी से हुए यौन संबंधों को अपराध नहीं माना गया है. प्रस्तावित विधेयक बच्चों के ख़िलाफ़ होने वाले अपराध, ख़ासकर यौन-शोषण के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए लाया गया है. बच्चों से दुष्कर्म के मामलों में कम से कम पांच साल की कैद और पचास हज़ार रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है. इस विधेयक में अच्छी बात यह है कि समाज में विश्वासनीय और अधिकारिक हैसियत रखने वाले व्यक्तियों द्वारा किए गए अपराधों को ज़्यादा संगीन जुर्म की श्रेणी में रखने का प्रावधान किया गया है और अगर अपराध 12 साल से कम उम्र के या विकलांग बच्चों के साथ हुआ हो तो इसे भी ऐसे ही दर्जे में रखने का प्रावधान किया गया है. समाज या सरकार यौन-उत्पीड़न रोकने के संबंध में नियम-क़ानून बनाते हैं. इन नियम-क़ानूनों के ज़रिए यौन-उत्पीड़न के दोषियों को सज़ा भी मिलती है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि सज़ा सिर्फ़ उन्हीं को मिलती है या मिलेगी जिनका मामला सामने आ जाता है. लेकिन समाज में तो यौन-उत्पीड़न के अनगिनत मामले ऐसे भी होते हैं जहां यौन-उत्पीड़न सहना एक विवशता होती है. यौन उत्पीड़न के अधिकतर मामलों में देखा गया है कि आरोपी ज़्यादातर बच्चे के रिश्तेदार या जानने वाले ही होते हैं. यौन उत्पीड़न इतना संवेदनशील विषय है कि समाज का विषम बिंदु आसानी से पकड़ में नहीं आता. इसके लिए किन विरोधाभासों को दोष दिया जाए. समाज में बढ़ते खुलेपन को या सैक्स को दबा-छिपाकर रखने से उपजी कुंठा को? एकांगी परिवार में असुरक्षित रहते बच्चों को या सामूहिक परिवार में अपनों के ही द्वारा असुरक्षित बच्चों को? मल्टीमीडिया के खुले माध्यम को या यौन शिक्षा के अभाव को? ये समस्त तथ्य इतने विरोधाभासी हैं कि इन पर वाद-विवाद तो महीनों और वर्षों तक चलाया जा सकता है, पर यौन-उत्पीड़न की समस्या का हल नहीं निकाला जा सकता. समाज में अनगिनत बच्चे यौन-उत्पीड़न के शिकार हो रहे हैं. सबसे ज़्यादा यौन-शोषण की शिकार बच्चियां ही होती हैं. दिनोदिन बढ़ते बच्चों के यौन शोषण के मामलों ने यह साबित कर दिया है कि देश में नौनिहाल कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं. बाहर ही नहीं घर के भीतर भी इनका यौन-उत्पीड़न होता है और इसमें वही लोग शामिल होते हैं जिन पर उनकी सुरक्षा का दायित्व होता है. एक सरकारी सर्वे के मुताबिक पांच से बारह साल की उम्र के 53 फ़ीसदी बच्चे ऐसे पाए गए, जिन्हें पारिवारिक व्यक्तियों ने ही यौन उत्पीड़न का शिकार बनाया. यौन-शोषण को लेकर चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी के एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट की ऑफिस इंचार्ज नीलिमा कुंवर के निर्देशन में दिसंबर 2010 के अंतिम दिनों में एक सर्वे कराया गया था. इस सर्वे में नौ साल से बारह साल तक की 249 लड़कियों को रखा गया था. जिन स्कूलों में यह सर्वे कराया गया, उनमें पांच हिंदी माध्यम के स्कूल थे और पांच अंग्रेजी माध्यम के. प्रमुख स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों से इस संबंध में प्रश्नोत्तरी के माध्यम से जानकारी ली गई थी. इन लड़कियों ने स्वीकार किया कि घर या बाहर वे इस तरह के हादसों का शिकार हुईं. 249 में 123 लड़कियों ने बताया कि उत्पीड़न करने वालों ने उनके शरीर के नाज़ुक अंगों को छुआ. 41.2 प्रतिशत लड़कियों ने बताया कि उन्हें शरीर के छिपे हिस्सों को दिखाने के लिए दबाव का सामना करना पड़ा. इतना ही नहीं उन्हें दूसरे तरह के यौन-शोषण का सामना भी करना पड़ा. सर्वे में शामिल आधी लड़कियों ने बताया कि उनका यौन-उत्पीड़न परिचितों ने ही किया. हालांकि कुछ ने कहा कि उनके स्कूल के आसपास चक्कर काटने वाले कुछ लोगों ने उनका यौन उत्पीड़न किया. हालांकि इस तरह की घटनाएं बहुत कम हुईं, जिनमें किसी अजनबी ने यौन उत्पीड़न किया हो. अधिकांश मामलों में लड़कियों से शरीर के छिपे हिस्सों को दिखाने का दबाव डाला गया. इन लड़कियों को शरीर के अंग अपने दोस्तों, रिश्ते के भाइयों या शिक्षकों को दिखाने पड़े. सर्वे में कहा गया है कि इस तरह की घटनाएं इन परिस्थितियों में हुईं हैं, जब कोई किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा होता है. ऐसे में इसे बचाने के लिए सामने आए लोगों ने ही बाद में उसका शोषण किया. नीलिमा कुंवर कहती हैं कि एक बार इस तरह की घटना होने के बाद पीड़िता को बार-बार उसी व्यक्ति द्वारा परेशान किया जाता है. उत्पीड़न करने वाला बच्चियों को यह भी समझा देता है कि यदि उसने किसी से ये बातें कहीं तो कोई उस पर भरोसा नहीं करेगा और उसकी बदनामी होगी. ऐसे में इन लड़कियों के सामने इन हादसों से गुज़रने के बाद ख़ामोश रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता. नीलिमा कुंवर का कहना है कि चूंकि कम उम्र की लड़कियां इन बातों से अनजान होती हैं और उन्हें सेक्स के संबंध में भी अधिक जानकारी नहीं होती है, इसलिए वे चुप रहना ही बेहतर समझती हैं. जो लड़कियां इन बातों को समझ पाती हैं, वे या तो अपराध बोध के चलते या फिर शर्म के कारण इस बारे में किसी को बता नहीं पातीं. इस तरह के यौन-उत्पीड़न की शिकार लड़कियां जननांगों के घाव, पेट दर्द की परेशानी और पेशाब के रास्ते में इन्फ़ेक्शन से पीड़ित हो जाती हैं. इस हादसे से गुज़रने के बाद उनके व्यवहार में भी काफ़ी बदलाव आ जाता है. मनोरोग विशेषज्ञों का मानना है कि यौन शोषण के कारण बच्चों में असुरक्षा की भावना पैदा होती है. बच्चे अकेलेपन के आदि हो जाते हैं. वे लोगों से मिलने जुलने से डरते हैं. वे अक्सर सहमे-सहमे से रहते हैं.

feedback@chauthiduniya.com

विधानसभा चुनाव बसपा के लिए आसान नहीं

डॉ. सुनील कौशिक

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियां शुरू हो गई हैं. बहुजन समाज पार्टी सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार है. वह इसके लिए अपनी पार्टी से बड़े से बड़े मोहरे को भी बलि चढ़ाने के लिए भी तत्पर है, बशर्ते इससे पार्टी को लाभ मिल रहा हो. प्रदेश में 13 मई 2007 को बसपा की सरकार बनी थी. पार्टी सुप्रीमो मायावती ने अपने दलित वोट बैंक को लुभाने और उस पर क़ब्ज़ा जमाए रखने के लिए जहां महामाया ग़रीब आर्थिक मदद योजना, कांशीराम शहरी ग़रीब आवास योजना, अंबेडकर ग्राम्य विकास जैसी योजनाओं का ढोल पीटना शुरू कर दिया था, वहीं 30 अप्रैल 2010 की समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों को 500 दाग़ियों को पार्टी से निकाले जाने की जानकारी दी थी, लेकिन वे कौन लोग थे जिनको पार्टी से निकाला गया था, इसकी लिस्ट उन्होंने पत्रकारों को नहीं दी. इससे इनकी वह घोषणा एकदम थोथी सिद्ध हुई. मायावती ने पार्टी से कुछ दाग़ी निकाले ज़रूर थे, लेकिन वो सबके सब छुटभइये नेता ही थे. बड़ी मछलियों पर उन्होंने हाथ नहीं डाला था. यदि बड़े नेताओं पर वे हाथ डालतीं तो पार्टी में बचता ही क्या? मुख्यमंत्री मायावती ने इस बात के भी संकेत दिए हैं कि 2012 के विधानसभा चुनावों में वे किसी भी दाग़ी को टिकट नहीं देंगी. सोचिए क्या यह संभव है? सब जानते हैं कि बसपा में अब दाग़ी लोगों का ही जमावड़ा अधिक है. बसपा के आधे दाग़ी इससे पूर्व सपा में थे. सपा ने जब उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया तो बसपा ने इन सभी को अंगीकार कर लिया था. मुख्यमंत्री को चुनाव की वैतरणी पार करनी है तो दाग़ियों को टिकट देनी ही पड़ेगी, वर्ना इन दाग़ियों का अपने-अपने क्षेत्र में इतना वर्चस्व तो है ही कि वे निर्दलीय लड़कर चुनाव में ख़ुद भले ही न जीत पाएं, पर बसपा की हालत ज़रूर ख़राब कर सकते हैं.

मुख्यमंत्री मायावती ने अपने वोट बैंक को रिझाने और ख़ुद को उनका सबसे बड़ा हितचिंतक दिखलाने के लिए फ़रवरी माह में प्रदेश के सभी ज़िलों का दौरा किया. इस दौरे का उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा करना उद्देश्य दिखलाया. दौरे में उन्हें सभी ज़िलों में विकास कार्य असंतोषजनक मिले. कार्रवाई स्वरूप उन्होंने अपने एक माह के दौरे में 79 आईएएस समेत अधिक अन्य दोयम दर्जे के अधिकारियों को निलंबित और तबादले करने की कार्रवाई करके अपने वोट बैंक को यह संदेश देने की कोशिश की कि वे ही उनकी सबसे बड़ी हितैषी हैं और पार्टी के लिए सक्षम मुख्यमंत्री भी और रहेंगी, जबकि इन सब कार्रवाइयों को आगामी विधानसभा चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है. दौरों के दौरान मायावती का मीडिया के सामने न आना और मीडिया के सवालों से ख़ुद को बचाए रखना भी यह दर्शाता है कि वे चुनावी अभियान को घोषित नहीं करना चाहतीं. यहां उल्लेखनीय यह है कि अब मायावती ने विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र ही वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की एक कमेटी गठित की है, जो जल्द ही उन्हें विधानसभा चुनावों में कैसे जीत हासिल हो, इस पर अपनी रिपोर्ट बनाकर देगी.

समाजवादी पार्टी मायावती पर सबसे बड़ा आरोप यह लगाती है कि उन्होंने जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा पत्थरों, पार्कों और मूर्तियों पर ख़र्च कर दिया है. सरकारी ख़ज़ाने का दुरुपयोग कर मुख्यमंत्री स्वयं अपनी मूर्ति लगवा रही हैं. इससे पूरे प्रदेश का विकास ठप हो गया है. राष्ट्रीय लोकदल की नज़र में बसपा की प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर विफल है. प्रदेश में क़ानून व्यवस्था बिलकुल ध्वस्त हो चुकी है. हर दिन हो रहे बलात्कार और हत्या जैसे अपराध बसपा सरकार की नाक़ामी ख़ुद व ख़ुद बयां कर रहे हैं. हर ज़िले का प्रशासन सरकारी एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है और ग़रीबों का ख़ून चूसने में लगा हुआ है. वैसे प्रत्यक्ष में जो दिखाई दे रहा है, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि वर्तमान में बसपा के मंत्री, विधायक, कोऑर्डिनेटर तथा कार्यकर्ता महिलाओं पर अत्याचार करने में आगे हैं. यही वजह है कि मायावती के लिए अब अपनी पार्टी के लोग ही मुसीबत बन गए हैं जिसके कारण वे बहुत दुखी हैं. उन्होंने अपनी पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं के ख़िलाफ़ कार्रवाई करके जनता में पैठ बनाने की कोशिश की थी, लेकिन आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला इतना बढ़ गया कि उन्हें वरिष्ठ नेताओं के ख़िलाफ़ की गई अपनी कार्रवाई को वापस लेना पड़ा. इससे जनता में ग़लत संदेश ही गया. कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी का घर जलाने के मामले में सीबीसीआईडी द्वारा फ़ैज़ाबाद के बीकापुर से विधायक जितेंद्र सिंह उर्फ़ बब्लू व लालबहादुर शास्त्री, गन्ना संस्थान के अध्यक्ष एस.एस इंतिज़ार आब्दी उर्फ़ बॉबी को दोषी पाए जाने पर जेल भेज दिया गया. इससे सरकार की बहुत किरकिरी हुई, लेकिन इससे भी ज़्यादा किरकिरी तब हुई जब जेल में उन्हें जेल प्रशासन द्वारा किशोर बैरक में रखा गया. इससे स्पष्ट हो गया कि सरकार उन्हें बचाने में लगी हुई है. जिन लोगों ने पार्टी की फ़ज़ीहत कराई, उनमें वर्ष 2007 में तत्कालीन मंत्री जमुनाप्रसाद निषाद पर महाराजगंज जनपद की कोतवाली में एक पुलिसकर्मी की हत्या, वर्ष 2008 में तत्कालीन राज्यमंत्री और फ़ैज़ाबाद ज़िले के विधायक आंदसेन यादव पर शशि नाम की एक छात्रा का अपहरण, औरैया जनपद के बसपा विधायक शेखर तिवारी पर अधिशासी अभियंता की हत्या, बुलंदशहर ज़िले के बसपा विधायक भगवान शर्मा उर्फ़ गुड्डू पंडित पर एक शोध छात्रा के साथ दुराचार और बीडीपी सदस्य के अपहरण का आरोप, बदायूं जनपद के बसपा विधायक योगेंद्र सागर पर बीए की छात्रा के साथ दुराचार का आरोप, बांदा जनपद के विधायक पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी पर बालात्कार का आरोप तथा ऐसे ही विभिन्न प्रकार के आपराधिक आरोप वाले दर्जनों मंत्री और विधायक हैं जिनके नाम के आगे माफ़िया शब्द लगा रहता है.

मायावती के लिए अब अपनी पार्टी के लोग ही मुसीबत बन गए हैं जिसके कारण वे बहुत दुखी हैं. उन्होंने अपनी पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं के ख़िलाफ़ कार्रवाई करके जनता में पैठ बनाने की कोशिश की थी, लेकिन आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला इतना बढ़ गया कि उन्हें वरिष्ठ नेताओं के ख़िलाफ़ की गई अपनी कार्रवाई को वापस लेना पड़ा.

अभी हाल ही में बसपा के दो और विधायक अपनी ही सरकार के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं. मामले को ठंडा करने के लिए सरकार ने अपने एक विधायक के ख़िलाफ़ मंडलायुक्त को जांच सौंप दी है, लेकिन विपक्ष की मांग है कि पहले विधायक के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज हो. उधर दूसरे विधायक के गनर और ड्राइवर के ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज कर पुलिस से निष्पक्ष जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है, लेकिन इस प्रकरण में भी विपक्ष विधायक के ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज करने की मांग पर अड़ा है. भाजपा ने तो राजभवन में दस्तक देने की घोषणा की है. उधर बचाव में सरकार का कहना है कि क़ानून से ऊपर कोई नहीं है. दोनों ही प्रकरणों में निष्पक्ष जांच हो रही है. विधायकों में एक विधायक लखीमपुर खीरी ज़िले से है. धौरहरा विधानसभा क्षेत्र से बसपा विधायक बाला प्रसाद

अवस्थी पर एक दलित महिला के साथ दुराचार के प्रयास का आरोप है. स्वर्ण वर्गों में बसपा सरकार के प्रति असंतोष पनप रहा है. उन्हें शिकायत है कि मुख्यमंत्री ने अपने वोट बैंक को ध्यान में रखकर ही योजनाएं लागू की हैं. इनमें बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का दर्शन एकदम ग़ायब है.

बसपा सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप भी लगाया जाता है. पिछले दिनों कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी ने आरोप लगाया कि यमुना एक्सप्रेस वे के लिए गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा व आगरा के लगभग 12 सौ गांवों के किसानों की 21 हज़ार हैक्टेयर क़ीमती कृषि भूमि को जबरन हथिया लिया गया, जबकि मुआवज़ा उन्हें बाज़ार भाव से न देकर मनमाने ढंग से दिया जा रहा है. किसान अपने मुआवज़े के लिए आंदोलनरत हैं. उन्होंने कहा कि किसानों को हरियाणा की तर्ज़ पर ज़मीन का उचित मुआवज़ा दिया जाए. हरियाणा सरकार ने अधिग्रहीत भूमि के लिए एक बार में बाज़ार भाव से मुआवज़ा देने के बाद 30 साल तक प्रीमियम देने का प्रावधान कर रखा है.

feedback@chauthiduniya.com

चार साल पूरे होने पर निशंक सरकार ने जश्न मनाया

राजकुमार शर्मा

देहरादून में भारतीय जनता पार्टी सरकार के चार वर्ष पूरे होने के अवसर पर सूबे की डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक सरकार ने सूबे में बड़ा जलसा आयोजित कर जश्न मनाया. इसका आलम यह रहा कि सूबे के मुखिया निशंक ने जोश में होश गंवा दिया. राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने से सरकार को दौड़ाने में अहम भूमिका निभाने वाले जनरल भूवन चंद खंडूरी की इस जलसे में ग़ैर मौजूदगी ने इस बात का जनता में सहजता से संकेत दे दिया भाजपा के अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा है.

इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सूबे की सरकार के मुखिया निशंक ने नगर महापालिका के मेयर विनोद चमोली से कराकर इस बात का प्रचार करवाया कि चमोली ने भी अब पाला बदल लिया है, और उनकी निष्ठा पूरी तरह से उनके साथ है. विनोद चमोली इस बात से साफ़ इनकार करते हैं और कहते हैं कि मैंने भाजपा सरकार के कार्यक्रम की अध्यक्षता राजधानी के मेयर की हैसियत से की, इसमें किसी तरह की गुटबंदी की बात सरासर ग़लत है. खंडूरी के सूत्रों से कार्यक्रम में भाग न लेने के कारणों की जानकारी करने पर पता चला कि जनरल को जानबूझ कर बुलावा ही देर में भेजा गया जिसके चलते उपलब्धता के बावजूद वे कार्यक्रम में अपनी उपेक्षा का भान कर भाग लेने नहीं पहुंचे. जनरल खंडूरी ने विकास पुरुष के नाम से विख्यात राजनीति के चाणक्य नारायण दत्त तिवारी की सरकार को 56 घोटालों के आरोप के नागपाश में बांधकर उन्हें सत्ता से बाहर किया था. जनरल ने सूबे की कमान थामते ही पंचायत में महिलाओं को पचास प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा कर के महिलाओं के प्रति अपना आभार व्यक्त कर दिया था. सैनिकों और उनके परिवार के लिए जब वे कुछ करना ही चाहते थे कि उनके अपने बने नेताओं ने संसद के आम चुनाव में जिस तरह टिहरी एवं हरिद्वार संसदीय सीट पर दल के लिए फ़ैसला लिया इसके चलते ही सूबे की पांचों सीट से भाजपा का सूपड़ा साफ़ हो गया. यह खेल दिल्ली में बैठे एक नेता के इशारे पर खेला गया जिसे यह पूरी तरह से पता था कि टिहरी राजघराने का अपमान भाजपा को इस चुनाव में भारी पड़ सकता है, जिसका परिणाम भी उनके सोच के अनुरूप ही रहा. संसद के आम चुनाव में भाजपा को ध्वस्त करने का षड्यंत्र एक राजनीतिक साजिश के तहत किया गया जिसका पूरा ताना बाना दिल्ली दरबार में गुटों में बटी भाजपा के एक नेता की सहमति से जनरल के ख़ास रहे सिपहसालारों ने रचा, जिसके चलते इस हार का पूरा ठीकरा जनरल खंडूरी के सर पर फोड़ा गया. भाजपा हाई कमान के समक्ष जो हाई प्रोफ़ाइल नाटक रचा गया उसमें जनरल का सच नहीं टिक सका. युद्ध के मैदान में विजेता रहे जनरल खंडूरी अपनों के विश्वासघात के चलते राजनीतिक युद्ध हार गए. अंततः उन्होंने हथियार डालना ही उचित समझा, क्योंकि राजनीति में ज़लालत झेलना अब उनके वश का नहीं रहा. देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने तिवारी राज को इस लिए नकारा था कि उन्हें भ्रष्टाचार घोटाला पसंद नहीं था. तिवारी जी अपने पांच साल के शासन में भ्रष्टाचार पर किसी तरह का लगाम लगाने की समर्थ कोशिश सरकार द्वारा किए जाने का संदेश नहीं दे सके. सूबे में भाजपा ने निज़ाम बदल कर अपना उल्लू तो सीधा कर लिया, लगातार महाकुंभ में घोटाला से लेकर ऋषिकेश, जल विद्युत परियोजनाओं के वितरण सहित कई घोटालों का छिटा निशंक सरकार पर पड़ने के साथ ही सूबे के प्रतिपक्ष के नेता हरक सिंह रावत, यशपाल आर्या ने इस सरकार को घोटाले की सरकार के नाम से ही नामकरण कर दिया. इस राज्य का प्रतिपक्ष भी बड़ी सावधानी से जिस हथियार से भाजपा ने तिवारी सरकार को मात दी. इसी से वे भी सूबे की भाजपा सरकार को अपने निशाने पर ले रहे हैं. भाजपा के जानकार बताते हैं कि ऐसी स्थिति जनरल के राज में नहीं थी. भाजपा के जलसे में सूबे के मुख्यमंत्री निशंक ने अपने पैंतालीस मिनट के सारगर्भित भाषण में अपनी तथा अपनी सरकार की ख़ूब पीठ थपथपाई. उन्होंने कांग्रेस के हरिद्वार से सांसद व केंद्र में मंत्री हरीश रावत के सवाल को यक्ष प्रश्न की तरह अनुत्तरित ही छोड़ दिया. हरीश रावत ने इनसे सीधा सा सवाल किया था कि आख़िर दस वर्ष गुज़र गए हमारी मां, बहनें कब तक आपात एंबुलेंस में प्रसव की विवशता झेलती रहेंगी? अपने भाषण में दो हज़ार से अधिक आपात एंबुलेंस में पैदा हुए बच्चों को जिस तरह से मुख्यमंत्री साहसी, शूर वीर बता रहे थे, उसे सुनकर इस कार्यक्रम में भाग लेने आईं सेना की दर्जन भर महिलाओं का हंसी से पेट फूला जा रहा था, और सभी मुख्यमंत्री की इस तरह की समझ को उपहास के तौर पर ले रही थीं. इस कार्यक्रम में आए सैकड़ों पूर्व सैनिक एवं उनके परिजन मंच पर अपने प्रिय नेता जनरल रहे भूवन चंद्र खंडूरी को देखना चाहते थे. सभा में खंडूरी की अनुपस्थिति ने जितने मुंह इतनी बातों को जन्म दे दिया है. इस दिन देहरादून में खंडूरी की मौजूदगी के बावजूद चार साला जलसे में न आना, भाजपा नेताओं का आपसी द्वंद कितना सतह पर आ चुका है इसको अब झुठलाया नहीं जा सकता. मुख्यमंत्री ने अपनी उपलब्धियों में सात बिंदु जिसमें 108 जीवनदायिनी एंबुलेंस सेवा, 50 हज़ार युवकों को रोज़गार सहित, अटल सस्ता राशन योजना, प्रत्येक न्याय पंचायत में अटल आदर्श ग्राम का अभिनव प्रयास सहित केंद्र सरकार की वृद्धाओं, विधवाओं, विकलांगों को पेंशन देने की योजनाओं को अपना प्रयास बताकर अपनी पीठ थपथपाई. मुख्यमंत्री द्वारा चार वर्ष पूर्व चुनावी वादों पर एक शब्द न बोलने के साथ 56 घोटाले के नायक तिवारी जी से गलबहियां करने पर कोई उचित तर्क नहीं दे सके, जिससे लोगों को भारी निराशा हुई. सरकार के मुखिया ने जिस तरह ज़िला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान सहित तीन महिला नेताओं को हल्के आरोपों के बावजूद इन पर रहम नहीं किया. इससे इस सरकार के महिला विरोधी होने का आरोप स्वयं ज़ोर पकड़ने लगा है. इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में वापसी में यहां की नारी शक्ति के साथ पूर्व सैनिकों एवं उनके परिजनों ने जो भूमिका निभाई थी, इससे खेलना निशंक ने बंद नहीं किया तो ये दोनों ताक़तें अब भाजपा को भी धूल चटा सकती हैं. मुख्यमंत्री को समय की ज़रूरत को देखते हुए तिवारी से नहीं, ईमानदार नेता के रूप में चर्चित अपने नेता जनरल खंडूरी से गलबहियां करनी चाहिए. अगर समय रहते सुधार नहीं हुआ तो मिशन-2012 की वापसी एक स्वप्न बन कर रह जाएगा.

feedback@chauthiduniya.com

स्वतंत्रता सेनानी के परिजन बदहाली में जी रहे हैं

लक्ष्मणदास गुप्ता उर्फ़ शांति

जो लोग देश हित में क़ुर्बानी दे देते हैं वे यह नहीं सोचते कि उनके बाद उनके परिवार का क्या होगा, क्योंकि देशभक्ति का जुनून व्यक्ति को यह सब सोचने ही नहीं देता. लेकिन क्या देश का यह दायित्व नहीं होना चाहिए कि वह शहीदों के परिजनों का ध्यान रखे. उनके जीवनयापन में किसी प्रकार की दिक्क़त न आने दे. देश में सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन जिन्होंने देश के लिए अपना सुख-चैन क़ुर्बान कर दिया, अपना जीवन लुटा दिया उनके परिवार वालों के लिए किसी सरकार ने कुछ नहीं किया.

देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ क़ुर्बान करने वाले ऐसे ही एक स्वतंत्रता सेनानी थे लक्ष्मणदास गुप्ता उर्फ़ शांति. उन्हें ब्रिटिश सरकार ने 1942 में इटावा में देशद्रोह के जुर्म में गिरफ्तार किया था. उन्होंने ख़ुशी-ख़ुशी देशद्रोह का जुर्म क़ुबूल भी कर लिया. 4 जनवरी 1943 को उन्हें विभिन्न धाराओं में 44 साल की सज़ा हुई. वाराणसी और नैनी के जेलों में वह पांच साल कुछ महीने रहे. देश आज़ाद होने के बाद उन्हें जेल से रिहा किया गया.

आज़ादी के दो दशक बाद स्वतंत्रता सेनानियों की तरफ़ सरकार का ध्यान गया और जेल के प्रमाणपत्रों के आधार पर स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन बांधी गई. केंद्र सरकार ने उन्हें दो सौ रुपए प्रति माह और राज्य सरकार ने 60 रुपए प्रतिमाह पेंशन निर्धारित की. महंगाई के साथ पेंशन भी धीरे-धीरे बढ़ती रही, लेकिन लक्ष्मणदास गुप्ता को जीवन भर इस बात का मलाल रहा कि वह अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाए और न ही किसी सरकार ने उनके बच्चों

शांति देवी

के लिए कुछ किया. लक्ष्मणदास की मृत्यु 13 जनवरी 1983 को हुई. इसके बाद उनकी पेंशन उनकी पत्नी शांति देवी को मिलने लगी. शांति देवी की मृत्यु 30 दिसंबर 2009 में हो गई और उनके साथ ही पेंशन का सिलसिला भी ख़त्म हो गया. लक्ष्मण दास के दो लड़के राकेश कुमार गुप्ता उम्र 55 वर्ष और प्रमोद कुमार गुप्ता उम्र 50 वर्ष हैं. उनके दोनों अशिक्षित पुत्र आज बहुत ही ग़रीबी की हालत में आगरा में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं. राकेश एक कपड़े की दुकान पर तीन हज़ार रुपए महीने की नौकरी करता है तो प्रमोद संजय प्लेस में एक किराए की गुमटी में गुटखा तंबाकू बेचता है. उनके अपने कई बच्चे हैं. किराए के मकान में रहकर ये मुफ़लिसी की ज़िंदगी काट रहे हैं. इस ग़रीबी में भी उन्हें गर्व है कि उनके पिता ने देश की आज़ादी में योगदान दिया. अपने पिता के ताम्रपत्र व अन्य प्रमाण पत्रों को वे इस तरह सहेजे हुए हैं जैसे कोई घर के ज़ेवरों को सहेजता है.

शांति देवी ने अपने मरने से पहले इटावा प्रशासन को एक हलफ़नामा दिया था कि मेरे दो पुत्र राकेश और प्रमोद हैं, उन्हें वारिस एवं वंशज प्रमाण पत्र बनाकर दे दिया जाए, लेकिन आज तक वह प्रमाण पत्र भी प्रशासन ने बनाकर नहीं दिया.

वे कहते हैं कि क्या देश की सरकार का यह दायित्व नहीं होना चाहिए कि जिन लोगों ने देश को स्वतंत्र कराने में अपने जीवन के सुखों की आहूति दी है, कम से कम उसकी एक पीढ़ी को तो सुविधाएं दी जाएं.

मनोज सिकरवार
feedback@chauthiduniya.com

सपा के आंदोलन से सरकार भयभीत

समाजवादी पार्टी द्वारा उत्तर प्रदेश में चलाया गया तीन दिवसीय बसपा हटाओ, प्रदेश बचाओ आंदोलन प्रदेश सरकार पर दबाव बनाने में तो पूरी तरह सफ़ल रहा है. तीनों दिन प्रदेश में किसी भी कार्यालय में कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं बैठ सका. हर अधिकारी की ड्यूटी कहीं न कहीं क़ानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लगी हुई थी. प्रदेश के हर ज़िले में चप्पे-चप्पे पर पुलिस मुस्तैद रही थी कि कहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता किसी कार्यालय में तालाबंदी न कर दें और प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री के पुतले न फूंकें. लाख चौकसी के बाद भी सपा के कार्यकर्ताओं ने पहले दिन ही अनेक कार्यालयों में तालाबंदी की और प्रदेश की मुख्यमंत्री के पुतले भी फूंके. समाजवादी पार्टी के इस तीन दिवसीय आंदोलन पर दूसरे दिन से प्रशासन की सख्ती तेज़ हो गई. इसके बावजूद कई ज़िलों में दूसरे और तीसरे दिन भी सपाई कई सरकारी कार्यालयों पर ताले जड़ने में सफ़ल हुए. निश्चित रूप से सपा का यह आंदोलन

विधानसभा चुनावों के लिए नए समीकरण तैयार कर गया है. पहले दिन समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव को कथित रूप से नज़रबंद किए जाने का असर संसद में भी दिखा. समाजवादी पार्टी के सांसदों ने संसद में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चलने दिया. इस मामले पर केंद्र सरकार और लोकसभा अध्यक्ष को सक्रिय होना पड़ा. लोकसभा अध्यक्ष के निर्देश पर महासचिव ने गृहसचिव उत्तर प्रदेश से बात की, तब कहीं जाकर मुलायम सिंह यादव और उनके सांसद पुत्र अखिलेश यादव दिल्ली पहुंचे. मुलायम सिंह यादव द्वारा कांग्रेस द्रमुक में सीटों की खींचतान को लेकर चल रहे मनमुटाव के दौरान केंद्र सरकार को अपने समर्थन की बात दोहराकर केंद्र सरकार को अपने पाले में कर लिया था. इसका उन्हें तुरंत ही फ़ायदा भी मिल गया. आंदोलन के अंतिम दिन भी सपा के बड़े नेताओं की धरपकड़ जारी रही. जैसे अखिलेश यादव को दोबारा लखनऊ के अमौसी हवाई अड्डे पर गिरफ्तार कर लिया गया.

दरअसल इस तीन दिवसीय आंदोलन का प्रशासनिक अधिकारियों पर इतना ख़ौफ़ रहा कि आंदोलन को कुचलने के लिए कई तरह की कार्य योजनाएं तैयार की गई थीं. किस अधिकारी की कहां ड्यूटी रहेगी यह भी तय किया गया था. जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को स्वयं मुख्यालयों के गेट पर तैनात होना पड़ा. सभी कार्यालयों पर पुलिस पिकेट लगाए गए. वास्तव में देखा जाए तो इस आंदोलन से बसपा मुखिया घबराई हुई दिखीं और इस घबराहट ने ही बसपा को कुछ समय के लिए ही सही, बैकपुट पर धकेल दिया. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को साफ़ तौर पर निर्देश दिए थे कि जिस जनपद में आंदोलन सफ़ल रहेगा, वहां के अधिकारियों को किसी भी क़ीमत पर नहीं बख़्शा जाएगा. इसी भय से दर्जनभर ज़िलों में लाठीचार्ज भी पुलिस द्वारा किया गया जिससे शासन को साफ़ दिखे कि पुलिस और प्रशासन ने सपा के आंदोलन को कुचलने में कोई कोताही नहीं बरती. पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों में भय के चलते अधीनस्थों को अपने कार्यालयों के पास रखे ईंट-पत्थरों को हटवाने, अपनी गाड़ियों और कार्यालयों की सुरक्षा के साथ-साथ कार्यालयों को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ही खोलने के निर्देश थे. आंदोलन से एक दिन पहले अनेक सपा नेताओं को सुरक्षा नगर की सुरक्षा की दृष्टि से ही घर से उठाकर जेल भेज दिया गया था.

रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, आज़म खां, नीरज शेखर, अंबिका चौधरी, आर.के.सिंह पटेल, विश्वंभर प्रसाद निषाद, ऊषा वर्मा (सांसद), मिथिलेश कुमार (सांसद), वीरपाल यादव, एमएलसी यशवंत सिंह, पूर्व सांसद रघुराज शाक्य, रामनरेश यादव, प्रेमदास कठेरिया, फ़ुरक़ान अहमद, एमएलसी रामनरेश मिनी, तेज प्रताप सिंह उर्फ़ तेजू, सुखदेवी वर्मा, पूर्व मंत्री रघुवर दयाल वर्मा, चौधरी संजय यादव, सरोज शर्मा, रामजीलाल सुमन, सुखराम यादव, जितेंद्र चौहान, राजा अरिदमन सिंह भदावर, रामसकल गूजर, हरीओम यादव, सीताराम शर्मा, रामवीर यादव जैसे वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में सपा के हज़ारों कार्यकर्ताओं ने बसपा सरकार को हिला दिया.

उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार 13 मई 2007 गठित हुई थी. तभी से समाजवादी पार्टी द्वारा कई तरह के धरने-प्रदर्शन किए गए, किंतु वे धरने-प्रदर्शन सफल नहीं हो सके थे. सरकार के कार्य करने के तौर-तरीक़ों पर सपा द्वारा विरोध तो अनेक बार जताया गया था, लेकिन सही बात तो यह है कि जनता व ज़मीनी कार्यकर्ताओं का समर्पण भाव न तब किसी भी आंदोलन में दिखाई दिया था और न इस बार के तीन दिवसीय आंदोलन में दखाई दिया, जबकि प्रदेश की बसपा सरकार ने समाजवादी पार्टी के पहले के ज़बरदस्त हल्ला बोल आंदोलनों को ध्यान में रखकर ही प्रदेश में क़ानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक इंतज़ाम किए थे. बसपा सरकार का अंदाज़ा था कि सपा के आंदोलन में लाखों कार्यकर्ता अपनी गिफ्तारी देंगे. इसी बात को ध्यान में रखकर मुख्यमंत्री मायावती ने हर ज़िले में अनेक अस्थाई जेलें बनवाई थीं. हम सपा के तीन दिवसीय आंदोलन को ऊपरी तौर पर तो सफल कह सकते हैं पर जिस तरह लाखों कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की आशंका थी, वैसा कुछ भी नहीं हुआ. लगता है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलाम सिंह यादव ने अरब देशों में चल रहे स्वप्रेरित जनआंदोलनों की सफलता से प्रेरित होकर ही जल्दबाज़ी में इस आंदोलन की रूपरेखा बनाई लगती है. पार्टी कार्यकर्ताओं पर यह तीन दिवसीय कार्यक्रम ऊपर से जबरन थोपा हुआ-सा लगता है.

राजनीति के पंडितों का मानना है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने जिस तरह आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर एक महीने तक लगातार प्रदेश के ज़िलों में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की और लापरवाह और उदासीन 79 आईएएस अफ़सरों के स्थानांतरण किए, साथ ही इससे भी अधिक द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के निलंबन और स्थानांतरण किए इससे मुलायमसिंह यादव घबरा गए, उन्हें लगा कि मायावती ने प्रदेश में अपने नंबर बढ़ा लिए हैं. कहीं वोट के समीकरण बिगड़ न जाएं, इसलिए मुलायम सिंह यादव ने भी फटाफट बसपा हटाओ, प्रदेश बचाओ आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर इसको अमली जामा पहनाया दिया. प्रजातंत्र में जनता सर्वोपरि है. अब यह तो जनता ही तय करेगी कि वह आगामी विधानसभा चुनावों में किसके हक़ में फ़ैसला करेगी. वैसे तब तक तो राजनीतिक पार्टियां अनेक प्रकार के हथकंडे और फंडे अपनाकर जनता को आकर्षित करेंगी, मोहेंगी.

प्रियंका सिंह
feedback@chauthiduniya.com

विश्वविद्यालय में फर्जीवाड़ा

देश के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक, जिसमें देश के सर्वोच्च पदों को सुशोभित करने वाली विभूतियों ने अध्ययन किया और विश्वविद्यालय को गौरवान्वित किया. ये सब जुमले विश्वविद्यालय में हर मंच पर विश्वविद्यालय के नीति नियंताओं द्वारा कहे-सुने जाते हैं, पर शायद ये जुमले किसी को प्रेरित नहीं कर पाते तभी तो स्वर्णिम इतिहास वाले इस विश्वविद्यालय का भविष्य अत्यंत धूमिल नज़र आता है. आलम यह है कि न तो डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले, न पढ़ाने वाले और न ही काम करने वाले विश्वासपूर्वक यह बता सकते हैं कि परीक्षाएं कब होंगी, परिणाम कब आएंगे, प्रवेश कब होंगे, लेकिन हर व्यक्ति यह जानता है कि अंक कैसे बढ़ेंगे, बिना प्रवेश डिग्री कैसे बनेगी, फेल से पास कैसे होंगे. हालात इतने संगीन हैं कि आए दिन फ़र्ज़ी मार्कशीट जारी होने की सूचनाएं आती हैं, चार्टों पर काट-पीटकर फ़र्ज़ी अंक बढ़ाने से आसान कोई कार्य नहीं है, लेकिन यदि छात्र ने पढ़कर परीक्षा दी है तो उसकी अंकतालिका बनना दुश्वार है और यदि अंकतालिका त्रुटिपूर्ण है तो इसको ठीक कराना एवरेस्ट पर चढ़ने से भी दुष्कर कार्य है. छात्र की जेब में माल है तो कार्य की तेज़ी की कमाल है. दूर दराज़ से आने वाले ग़रीब छात्रों की कोई सुनने और कहने वाला नहीं है. दलाल इतने विद्वान हैं कि छात्र को कार्य के विज्ञान के साथ काम का अर्थशास्त्र भी पढ़ा देते हैं. विश्वविद्यालय में काम के अर्थशास्त्र से सब परिचित हैं. फिर भी पता नहीं क्यों विश्वविद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी और प्रत्येक अधिकारी उदासीन नज़र आता है. सब लोग सब जानते हैं, सब समझते हैं, पर अनजान बने रहते हैं. विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्रियों का एक पूरा तंत्र विश्वविद्यालय के पूरे प्रशासन पर क़ब्ज़ा जमाए हुए है. आंखों में धूल झोंकने के लिए जब भी इन अर्थशास्त्रियों को हटाया जाता है तो मलाईदार कुर्सियों की नीलामी से होने वाली आय हालात को बद से बदतर बना देती है. बीते समय में बीएड परीक्षाओं में पूर्व परीक्षार्थियों को परीक्षा दिलाने को लेकर कर्मचारियों पर जो कार्रवाई हुई, वह भ्रमित करने के लिए ही हुई जान पड़ती है, क्योंकि हालात सुधरे हों ऐसा लगा नहीं. बीए एवं बीएससी की परीक्षा में भी अधीक्षक बदले गए, लेकिन कुछ बदला हो ऐसा दिखता नहीं. पिछले वर्ष शेयरमनी के नाम पर हुए घोटाले में एक वित्त अधिकारी और चार कर्मचारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई, लेकिन विश्वविद्यालय के अधिकारी और कर्मचारियों के अर्थशास्त्र सिद्धांत और मज़बूत होते चले गए.

डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय

आलम यह है कि न तो डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले, न पढ़ाने वाले और न ही काम करने वाले विश्वासपूर्वक यह बता सकते हैं कि परीक्षाएं कब होंगी, परिणाम कब आएंगे, प्रवेश कब होंगे, लेकिन हर व्यक्ति यह जानता है कि अंक कैसे बढ़ेंगे, बिना प्रवेश डिग्री कैसे बनेगी, फेल से पास कैसे होंगे.

डॉ. आशुतोष पचौरी
feedback@chauthiduniya.com